वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
कोटा

एम.जे.एम.सी. - 5
विश्व का समाचार जगत
(World Press)

विश्व का समाचार-जगत्- 2

पत्रकारिता एवं जनसंचार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
(Master of Journalism & Mass Communication)

विश्व का समाचार-जगत्
एशिया में जनसंचार

2

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

पत्रकारिता एवं जनसंचार
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

विश्व का समाचार- जगत् 2

पाठ्यक्रम विशेषज्ञ समिति

- **प्रो. जी.एस.एल. देवड़ा**
  कुलपति
  कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा
  (अध्यक्ष समिति)
- **डॉ. अब्दुल वहीद खान**
  निदेशक (विकास एवं प्रशिक्षण)
  कॉमनवेल्थ सेण्टर ऑफ लर्निंग 1285 ब्राइवे
  सूट 600, वैंकवर (कनाडा)
- **राधेश्याम शर्मा**
  पूर्व-महानिदेशक
  माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता
  विश्वविद्यालय, भोपाल(म. प्र.)
- **डॉ. ओ.पी. केजरीवाल**
  निदेशक, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी
  तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली
- **प्रो. ए.के. बनर्जी**
  पूर्व-अध्यक्ष
  पत्रकारिता विभाग
  बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
  वाराणसी
- **प्रो. जे.एस. यादव**
  भारतीय जनसंचार संस्थान
  नई दिल्ली
- **डॉ. भंवर सुराणा**
  ब्यूरो चीफ/ विशेष संवाददाता
  दैनिक हिंदुस्तान
  जयपुर
- **डॉ. रमेश जैन**
  अध्यक्ष-जनसंचार विभाग
  कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा
  (सचिव, समिति)

संयोजक

डॉ. रमेश जैन- अध्यक्ष, जनसंचार विभाग
कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

पाठ-संपादक एवं भाषा-संपादक

पाठ-संपादक
डॉ. रमेश जैन
अध्यक्ष, जनसंचार विभाग
कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

भाषा-संपादक
डॉ. विष्णु पंकज
वरिष्ठ साहित्यकार-पत्रकार
जयपुर

अकादमिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

- डॉ. आर.वी. व्यास, कुलपति
- डॉ. एच.बी. नन्दवाना, विभागाध्यक्ष
- डॉ. पी.के. शर्मा, निदेशक, पा.सा.उ. एवं वि. विभाग

पाठ्यसामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग

- योगेन्द्र गोयल
  सहायक उत्पादन अधिकारी

सर्वाधिकार सुरक्षित ! इस पाठ्यक्रम का कोई भी अंश कोटा खुला विश्वविद्यालय/ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना या मिम्योग्राफी(चक्रमुद) अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करना वर्जित है।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के विषय में और अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, रावतभाटा रोड, कोटा से प्राप्त की जा सकती हैं।

पाठ-लेखक

(1) प्रो. प्रदीप माथुर
भारतीय जनसंचार संस्थान
नई दिल्ली

(2) डॉ. अर्जुन तिवारी
अध्यक्ष, पत्रकारिता विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

(3) मुरली मनोहर मंजुल
वरिष्ठ जनसंचारकर्मी
जोधपुर

(4) गुलाब बत्रा
वरिष्ठ पत्रकार 'वार्ता' समाचार समिति
जयपुर

(5) डॉ. विष्णु पंकज
वरिष्ठ जनसंचारकर्मी
जयपुर

(6) जयदेव
वरिष्ठ जनसंचारकर्मी
जयपुर

(7) डॉ. रमेश जैन
जनसंचार विभाग
कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

(8) रामकुमार
स्वतंत्र पत्रकार, लेखक
कोटा

अनुवाद

रामकुमार
स्वतंत्र पत्रकार, लेखक, कोटा

पाठ्यक्रम-पंचम
खण्ड-द्वितीय

2

विश्व का समाचार जगत्

इकाई -4 एशिया में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी - 1 (दक्षिण एशिया)	8–43
इकाई -5 एशिया में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी - 2 (दक्षिणी पूर्वी एशिया)	44–80
इकाई 6 एशिया में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी - 3 (पूर्वी एशिया)	81–113

खंड एवं इकाई परिचय

खंड परिचय

विश्व का समाचार जगत् का खंड-2 आपके सामने है। इस खंड में शिक्षार्थियों के लिए तीन इकाइयां है। 1 दक्षिण एशिया में जनसंचार और नई प्रौद्योगिकी, 2 दक्षिणी-पूर्वी-एशिया में जनसंचार और नई सूचना प्रौद्योगिकी तथा 3 पूर्वी एशिया में जनसंचार और नई सूचना प्रौद्योगिकी।

ये तीनों इकाइयां एशिया में जनसंचार और नई सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में विस्तार से प्रमाणिक जानकारी देती है।

इकाई परिचय

इकाई 4 'एशिया में जनसंचार और नई सूचना प्रौद्योगिकी (दक्षिण एशिया) से संबद्ध है। इसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, तथा श्रीलंका के जनसंचार माध्यमों के उद्भव और विकास, दशा एवं दिशा, जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में सरकार की नीति, प्रेस स्वतंत्रता के प्रमुख मुद्दे आदि बिन्दुओं की विस्तार से प्रामाणिक जानकारी दी गई है। जनसंचार के तीनों माध्यम समाचार पत्र रेडियो और टेलीविजन के बारे में भी विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

इकाई 5 में दक्षिण पूर्व एशिया के दस देशों - 1 बुनेई दारुस्लम, 2 कम्बोडिया, 3 इंडोनेशिया, 4 लाओस, 5 मलेशिया, 6 म्यांमार, 7 फिलिपिन्स, 8 सिंगापुर, 9 थाईलैण्ड तथा 10 वियतनाम के जनसंचार माध्यमों, सरकार की नीति, नई सूचना प्रौद्योगिकी पर यथेष्ट अध्ययन सामग्री दी गई है। जनसंचार माध्यमों के प्रति दक्षिण पूर्वी देशों में सरकार की नीति क्या रही है और संचार माध्यमों को कितनी स्वतन्त्रता है, इस तथ्य को भी इस इकाई में उजागर किया गया है।

इकाई 6 में पूर्वी, एशिया के देशों- चीन, हांगकांग, (चीन), मकाऊ (चीन), जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया, तथा ताईवान के जनसंचार माध्यमों पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला गया है। सूचना युग में पूर्वी एशिया के ये देश किस प्रकार समय के अनुसार विकास रत है या यह पीछे रह गए है, इस इकाई के अध्ययन से आप जान सकेंगे।

आशा की जाती है कि प्रस्तुत तीनों इकाइयां आपको एशिया में जनसंचार और नई सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देगी।

इकाई 4 एशिया में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी-1 (दक्षिण एशिया) Media in Asia-1 (South Asia)

इकाई की रूपरेखा

4.0 उद्देश्य

4.1 प्रस्तावना

4.2 बंगलादेश में जनसंचार और नई सूचना प्रोद्योगिकी

4.2.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

4.2.2 जनसंचार : उदभव एवं विकास

4.2.2.1 समाचारपत्र

4.2.2.2 रेडियो

4.2.2.3 टेलीविजन

4.2.3 नई सूचना प्रोद्योगिकी

4.2.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति

4.2.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे

4.3 भूटान में जनसंचार और नई सूचना प्रौद्योगिकी

4.3.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

4.3.2 जनसंचार: उदभाव एवं विकास

4.3.2.1 समाचारपत्र

4.3.2.2 रेडियो

4.3.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी

4.3.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति

4.3.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे

4.4 भारत में जनसंचार और नई सूचना प्रौद्योगिकी

4.4.1 राष्ट्रीय पीरप्रेक्ष्य

4.4.2 जनसंचार: उद्भव एवं विकास

4.4.2.1 समाचारपत्र

4.4.2.2 रेडियो

4.4.2.3 टेलीविजन

4.4.3 नई सूचना पौद्योगिकी

4.4.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति

4.4.5 प्रेस स्वतंत्रता के प्रमुख मुद्दे

4.5 मालदीव में जनसंचार और नई सूचना प्रौद्योगिकी

4.5.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

4.5.2 जनसंचार : उद्भव एवं विकास
4.5.2.1 समाचारपत्र
4.5.2.2 रेडियो
4.5.2.3 टेलीविजन
4.5.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी
4.5.4 जनसंचार माध्यमों के सन्दर्भ में नीति
4.5.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे
4.6 नेपाल में जनसंचार और नई सूचना प्रौद्योगिकी
4.6.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य
4.6.2 जनसंचार: उद्भव एवं विकास
4.6.2.1 समाचारपत्र
4.6.2.2 रेडियो
4.6.2.3 टेलीविजन
4.6.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी
4.6.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति
4.6.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे
4.7 पाकिस्तान में जनसंचार और नई सूचना प्रौद्योगिकी
4.7.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य
4.7.2 जनसंचार: उद्भव एवं विकास
4.7.2.1 समाचारपत्र
4.7.2.2 रेडियो
4.7.2.3 टेलीविजन
4.7.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी
4.7.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति
4.7.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे
4.8 श्रीलंका में जनसंचार और नई सूचना प्रौद्योगिकी
4.8.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य
4.8.2 जनसंचार उद्भव एवं विकास
4.8.2.1 समाचारपत्र
4.8.2.2 रेडियो
4.8.2.3 टेलीविजन
4.8.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी
4.8.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति
4.8.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे

4.9 सारांश
4.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें
4.11 निबन्धात्मक प्रश्न

4.0 उद्देश्य

इकाई 4, 5 एवं 6 में एशिया के जनसंचार माध्यमों के उद्भव एवं विकास तथा उनके योगदान पर प्रकाश डाला गया है। 'एशिया के जनसंचार माध्यमों को तीन इकाइयों में विभक्त किया गया है-दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पूर्वी एशिया।

- प्रस्तुत इकाई 'दक्षिण एशिया' से संबद्ध है।
- दक्षिण एशिया में जो देश सम्मिलित है, वे हैं- भारत, बंगलादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका।
- दक्षिण एशिया के आठ देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, के जनसंचार माध्यमों के उद्भव विकास, दशा एवं दिशा के संपूर्ण परिप्रेक्ष्य से आप परिचित हो सकेंगे।
- दक्षिण एशिया के देशों की स्थिति, जनता, राजनैतिक स्थितियों एवं विभिन्न जनसंचार माध्यमों के विकास और समस्याओं से अवगत हो सकेंगे।
- दक्षिण एशियाई देशों में नए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के विकास के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- विभिन्न देशों में प्रेस की स्वतन्त्रता एवं विभिन्न माध्यमों के संदर्भ में भावी संभावनाओं से पीरचित हो सकेंगे।
- इस प्रकार दक्षिण एशिया के जनसंचार माध्यमों और नई सूचना-प्रौद्योगिकी का विस्तार से आप अध्ययन कर सकेंगे।

4.1 प्रस्तावना

ओसियना, मध्य पूर्व एवं पूर्व सोवियत एशिया महाद्वीप के तीन भागों-दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्वी एशिया एवं पूर्वी एशिया में कुल दुनिया की आबादी के 55 प्रतिशत लोग रहते हैं। इस महाद्वीप के कुल 25 देशों के लोगों की स्थितियों, आबादी, समाचारपत्र, रेडियो, टेलीविजन, नई सूचना प्रौद्योगिकी आदि के विकास, दशा एवं दिशा के सन्दर्भ में इस इकाई में दक्षिण एशिया के और अन्य देशों के बारे में चर्चा की गई है। जो आपको विभिन्न जनसंचार माध्यमों के विकास की बाधाओं, तुलनात्मक स्वरूप एवं गति की जानकारी देंगे जिसे पढ़कर आप भारत सहित दक्षिण एशियाई जनसंचार माध्यमों से परिचित हो सकेंगे एवं अपनी दृष्टि को विस्तार दे सकेंगे।

4.2 बंगलादेश में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी

4.2.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप के पूर्व में 1,44,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला बंगलादेश दुनिया का सर्वाधिक आबादी की दृष्टि से आठवां देश है जहां 127.2 मिलियन लोग

निवास करते हैं। म्यांमार की 193 कि.मी. सीमा को छोडकर यह चारों ओर भारत की सीमाओं से घिरा है। पदमा और ब्रहापुत्र नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व बांगलादेश में मिलती है। अकाल, तूफान और बाढ़ जैसी विभीषिका से यह देश ग्रस्त रहता है।

आदिवासी, बिहारी और बंगाली यहां निवास करते हैं। धार्मिक दृष्टि से कुल आबादी का 88.3 प्रतिशत मुसलमान, 10.5 प्रतिशत हिन्दू और 1.2 प्रतिशत अन्य धर्मावलम्बी हैं। 14 अगस्त, 1947 को पाकिस्तान बनने के साथ भारत का यह हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान का एक भाग बन गया। 1971 में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पश्चिम पाकिस्तान के खिलाफ आन्दोलन में बंगाली-भारतीय फौजो ने विजय प्राप्त की और 26 मार्च, 1971 को बांगलादेश एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन गया। इसके बाद बंगलादेश की राजनीति में कई उतार-चढ़ाव आए। बंगलादेश कृषि प्रधान है जहां 75 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। प्रमुख आर्थिक स्रोत नदियां, उपजाऊ भूमि और गैस भण्डार है।

4.2.2 जनसंचार: उद्भव एवं विकास

4.2.2.1 समाचारपत्र

भारत की आजादी से पूर्व यह देश भारत के अंग के रूप में पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों ने 1779 में कलकत्ता में छापाखाने का प्रारम्भ किया। जे.ऐ. हिक्की ने बंगाल गजट के नाम से 1780 में पहला समाचारपत्र कलकत्ता से प्रकाशित किया। 1871 में ढाका में अंग्रेजी पत्र बंगाल टाइम्स सप्ताह में दो बार छपने लगा। रंगपुर, दीकप्रकाश, कविता कुसुमावली, ढाका प्रकाश आदि साप्ताहिक एवं मासिक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन 1860-61 में शुरू हुआ। 1873 में महामार, बंगबंधु, बाल विवाह, ग्रामदत, बालरंजिका, हितसंघानी, हिन्दु रंजिका आदि पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगा। 1900 से 1947 के बीच अंग्रेजों के विरुद्ध राजनैतिक चेतना जागृत करने तथा साहित्य, समाज और संस्कृति को लेकर प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं छपती थी जिनकी संख्या 1947 में 65 थी।

अंग्रेजों के समय ढाका में 1939 में पहला रेडियो स्टेशन शुरू हुआ। यह कलकत्ता रेडियो स्टेशन के अन्तर्गत था। 5 कि.वाट के इस स्टेशन की प्रसारण क्षमता 64 कि.मी. थी। भारत विभाजन के बाद दैनिक पूर्वी पाकिस्तान एवं पैगाम समाचारपत्रों के साथ कुछ साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाएं शुरू हुई। 1948 में पाकिस्तान आब्जर्वर (अंग्रेजी) शुरू हुआ। संगबाद (1950), इत्तफाक (1955) दैनिक शुरू हुए जो इस समय बंगलादेश के प्रमुख दैनिक-पत्र हैं। भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय 1965 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में डिफेन्स ऑफ पाकिस्तान रूल्स लागू किए गये ताकि इत्तेफाक एवं न्यू नेशन जैसे वहां के समाचारपत्रों को दबाया जा सके।

बंगलादेश में आजादी के बाद स्पेशल पावर एक्ट 1974 लागू होने से प्रेस की जो भी उस समय स्वतन्त्रता थी, उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इस अधिनियम के कारण संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी पर आंच आई। मौर्निंग न्यूज, आजाद, दैनिक बांगला एवं पूर्वीदेश ये चार सरकार द्वारा संचालित पत्र तथा दा पीपल, बंगलार बानी एवं सगबाद सरकार

की नीतियों पर चलने वाले पत्र प्रमुख हो गए। विपक्ष या स्वतंत्र पत्रों में गणकन्था, इत्तफाक एवं जनपद को माना जाता था।

1975 के बाद नई सरकार बनी। इसने कुछ सीमा तक प्रेस की आजादी को स्थापित किया। 1934 में प्रेस कमीशन ने कुछ सिफारिशें की। इसने सार्वजनिक क्षेत्र के पत्रों एवं सरकारी नियंत्रण वाली समाचार समितियों की समाप्ति की भी सिफारिश की। प्रेस कमीशन ने प्रेस कानूनों की समीक्षा तथा सूचना स्वतन्त्रता के नए कानून बनाने की भी बात रखी। कमीशन ने प्रेस का स्तर' "सरकारी जनसम्पर्क" मात्र से ऊपर उठाकर 'बेहतर उपयोग करते हुए प्रेस को एक चेन्ज एजेन्ट' बनाने का सुझाव दिया। प्रेस को एक जिम्मेदार दर्जा देने को कहा। तत्कालीन इर्शाद सरकार ने इन सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की। 1980 में ढाका में कई नए पत्र प्रारम्भ हुए, लेकिन समाचार-माध्यमों को बन्द करने या इन पर अंकुश का काम चलता रहा। यहां तक कि बी.बी.सी. संचालन रोक दिया गया और स्पेशल एक्ट के तहत इसके एक संवाददाता को कैद कर लिया गया। यह 1985 तक की स्थिति रही।

फरवरी, 1991 में संसदीय लोकतंत्र की पुन: स्थापना हुई। इर्शाद सरकार का पतन हुआ। खालिदा जिया नई प्रधानमंत्री बनी। स्पेशल पावर एक्ट की कई धाराए हटा दी गई और कई नए पत्रों ने आजादी की सास लेते हुए अपने प्रकाशन शुरू किए।

4.2.2.2 रेडियो

1948 तक ढाका रेडियो की स्थिति बहुत कमजोर थी। पाकिस्तान सरकार के बीच कम्यूनिकेशन लिंक मजबूत करने के लिए 1959, से 1963, 100 कि.वा. एवं 1,000 कि.वा. ट्रान्समीटर ढाका में स्थापित किए गए। चितगांव, राजशाही सिलहट, रंगपुर एवं खुलना में 1954 से 1971 के बीच रिले स्टेशन खोले गए। 1971 की स्वतन्त्रता की लड़ाई में कई ट्रान्समीटर एवं स्टूडियो नष्ट हो गए। बंगला बेतार या रेडियो बंगलादेश पहला अर्थ सैटेलाइट 1975 में प्रारम्भ गया।

1984 तक बंगलादेश का रेडियो एक स्वतन्त्र विभाग के रूप में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करता रहा। मार्शल-ला प्रशासन ने इसे बंगला देश टेलीविजन में मिला दिया। फिर भी, एक महानिदेशक की देखरेख में रेडियो (बांग्ला बेतार) ढाका से मिडियम वेव के 8 स्टेशनों को स्वदेश में प्रसारित करता है। अन्य स्टेशनों के साथ बंगलादेश की सम्पूर्ण आबादी प्रसारण सेवाओं की पहुच में है। रेडियो कार्यक्रमों में 45 प्रतिशत मनोरंजन के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। समाचारों के तीन प्रतिशत, शिक्षा और धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के 9 प्रतिशत कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। अरबी, बंगाली, अंग्रेजी, हिन्दी, नेपाली, उर्दू भाषाओं में विदेश सेवा एवं अन्य कार्यक्रम भी प्रसारित होते हैं।

4.2.2.3 टेलीविजन

1964 में जबकि बंगलादेश का निर्माण भी नहीं हुआ था, यह पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खां की सरकार ने भारत से पहले

ही यहां टेलीविजन युग का सूत्रपात कर दिया था। जापान के सहयोग से ढाका टी.वी परियोजना शुरू की गई। साठ के दशक में ही बाद में, चिटगांव में सेटेलाईट स्टेशन बनाया गया। खुलना और राजशाही में रिले स्टेशन बनाए गए। इस प्रकार देश की आधी आबादी तक टी.वी की पहुँच हो गई थी। अधिकांश कार्यक्रम बंगाली में होते थे।

बंगलादेश के बनने के बाद 1971 में सरकार ने टीवी नेटवर्क का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 'बंगलादेश टेलीविजन कपोरेसन' को यह काम सौंपा गया। 1974 में नए उपकरणों के साथ टी.वी स्टूडियो बना और दक्षिण एशिया में एक सबसे बड़ा टी.वी नेटवर्क वहां बनाए जाने की योजना तैयार की गई।

इसके बाद, बी.टी.वी के रिले एवं सेटैलाईट विस्तार के साथ 95 प्रतिशत क्षेत्र को टी.वी कार्यक्रमों में जोड़ा गया। बी.टी.वी का दूसरा स्टेशन सी.टी.वी चिटगांव में संचालित किया जाने लगा। 1999 में सराकर ने 'एक्यूरो टेलीविजन' (ई.टी.वी) नामक निजी चैनल को स्वीकृति दी। हाई फ्रीक्वीन्सी पर कार्यक्रम प्रसारण के लिए कार्य करते हुए इसने अपने कार्यक्रमों की पहुंच पश्चिम बंगाल, दक्षिण पूर्वी देशों, मध्यपूर्व, यूरोप एवं अमेरिका तक प्रसारित करने के कार्यक्रम बनाए। केबल टी.वी ने 1990 में संचालन प्रारम्भ किया और यह लोकप्रिय माध्यम साबित हुआ। बंगलादेश में केबल टी.वी ऑपरेटरों को सरकार से लाइसेंस लेना होता है जो बी.टी.वी के द्वारा प्रदान किया 'जाता है और उन्हें सरकार को वार्षिक शुल्क देना होता है।

लेकिन बंगलादेश में टी.वी. एक माध्यम के रूप में सम्पन्न-वर्ग की पहुंच में ही अधिक है। सामुदायिक रूप से टी.वी. देखने के कार्यक्रम के संदर्भ में सरकार इस माध्यम का अधिक विस्तार नहीं कर पाई और अधिकांश लोग टी.वी सेट खरीदने की क्षमता नहीं रखते।

4.2.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी जनसंचार

रेडियो एवं टेलीविजन ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण है। वे लाइसेंस शुल्क, विज्ञापन एवं सरकारी सहायता पर निर्भर हैं। निजी चैनल ई.टी.वी की आय का स्रोत विज्ञापन है। ब्रिटिश शासन एवं पाकिस्तान शासन की विरासत के रूप में बांग्लादेश सरकार की सोच उसी अधिनायकवाद की प्रवृत्ती से ग्रस्त है जिसके अन्तरगत इसे जनसेवा के माध्यम के रूप में उपयोग में लिया जाता है। वहां स्वतन्त्रता के बाद में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को राज्य के कानून के दायरे में रखा गया है क्योंकि राजनैतिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विकास की जिम्मेदारी निभाने की दिशा में सरकार इन माध्यमों की अहम भूमिका मानती है। बंगला देश में नए इलेक्ट्रानिक माध्यमों का विकास करने के लिए इन्टरनेट सेवाओं एवं ऑन-लाईन माध्यमों पर भी ध्यान दिया गया है। बंगलादेश टेलिग्राफ एवं टेलीफोन बोर्ड (बी.टी.टी.बी.) ने उच्च गति डेटा कम्यूनिकेशन सेवाओं की स्थापना करके आठ इन्टरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाले केन्द्र उपलब्ध कराए हैं। इसमें इन्टरनेट सूचना सेवा नेटवर्क से इन्टरनेट सुविधा का विस्तार हुआ है। इससे टेलीस्टार, इकोनॉमिक आब्जर्वर इन्डीपेन्डेन्ट, वीकली ढाका कोरियर आदि कई समाचारपत्र प्रकाशन बेवसाईट पर उपलब्ध हैं।

4.2.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति

बंगलादेश में जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में प्रेस की स्वतंत्रता में निरन्तर कमी किए जाने की प्रवृत्ति रही है। 1974 में 'स्पेशन पावर्स एक्ट' के लागू होने तथा इसके जारी रहने के व्यवहार से यह प्रवृत्ति स्पष्ट होती है। इससे समाचारपत्रों एवं जनसंचार माध्यमों की सीमाएं तय हैं तथा सरकार के 1998 के नकारात्मक रुख से प्रेस की स्वतन्त्रता और प्रभावित हुई है। लेकिन, जनसंचार माध्यमो द्वारा देश में स्वतन्त्र शासन के लिए जारी प्रयत्नों के कारण इन माध्यमों के विकास की सम्भावनाएं धूमिल नहीं हुई हैं। बंगलादेश के संविधान में नागरिकों को अभिव्यक्ति एवं बोलने के साथ प्रेस की स्वतन्त्रता के मौलिक अधिकारों की गारन्टी दी गई है। इसके संरक्षण का दायित्व न्यायिक व्यवस्था पर निर्भर है। स्वतन्त्र राजनैतिक-संस्कृति, राजनैतिक संस्थाओं आदि की स्थिति अत्यन्त निर्बल है। आलोचना के प्रति असहिष्णुता एवं स्वतन्त्रता, एकमत धारणा का अभाव इस तथ्य को प्रगट करता है। बंगलादेश में स्वतन्त्रता की क्रांति के परिणामस्वरूप माध्यमों को नियमों से मुक्त करने, माध्यमों को संगठनात्मक रूप देने तथा प्रबंध की कुशलता प्रदान करने के संदर्भ में कोई प्रगति नहीं हुई। यद्यपि वहां भी अन्य देशों की तरह नई मीडिया तकनोलॉजी पर विशेष ध्यान दिया गया है।

4.2.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे

'फ्रीडम हाऊस' के सर्वेक्षण के अनुसार बंगलादेश में प्रेस स्वतन्त्रता आंशिक है। प्रेस की स्वतन्त्रता पर अंकुश को अंकों मे प्रगट किया जाए तो अंकुश का स्कोर बंगलादेश में 100 में से 59, भारत में 37 और पाकिस्तान में 60 है। माध्यमों की सामग्री पर राजनैतिक दबाव एवं नियंत्रण के संदर्भ में भी स्थिति ठीक नहीं है। आर्थिक दबाव भी कम नहीं है। बंगलादेश में साक्षरता का प्रतिशत 38.9 है। सरकार के पास कानूनी एवं अन्य ऐसे हथियार हैं जो मानवाधिकारों से संबंधित समाचारों पर दबाव डालते हैं। कई बार प्रेस की स्वतन्त्रता या अन्य मुद्दों पर माध्यम भी सरकार से एक प्रकार का अपवित्र गठबंधन कर लेते है। पत्रकारों को हमले या धमकियों का सामना भी करना पड़ता है। इस प्रकार प्रेस की स्वतन्त्रता जैसे मुद्दे आज भी वहां उलझे हुए हैं।

Daily News paper Bangladesh

	Frequency	Established	Language	Circulation
Published in Dhaka				
Ittefaq	Daily a.m	1955	Bengali	215,900
Dainik Inqilab	Daily	1986	Bengali	180,140
Janakantha	Daily	1991	Bengali	150,000
Manavzamin	Daily	1998	Bengali	100.000*
Sangbad	Daily a.m	1950	Bengali	73,005
Bhorer Kagoj	Daily	1992	Bengali	70.000*

Danik Sangram	Daily	1970	Bengali	50.980
Bangladesh Observer	Daily a.m	1948	English	42.830
Dainik Dinkal	Daily	1987	Bengali	40.300
Daily Star	Daily	1991	English	30.010
Dainik Khabar	Daily	1985	Bengali	24.355
Dainik Janata	Daily	1984	Bengali	20,090
Banglar Bani	Daily	1971	Bengali	20,000
Ajker Kagog	Daily	1991	Bengali	20,000*
Morning sun	Daily	1990	English	18.125
Daily Shakti	Daily	1982	Bengali	16,510
Banglabazar Patrika	Daily	1992	Bengali	15,000*
Daily Independent	Daily	1994	English	15,000*
New Nation	Daily	1981	English	10,920
Dainik Patika	Daily	1986	Bengali	6,260
Dainik Kishan	Daily	1976	Bengali	6,030
Published in Chittagaon				
Daily Burbokone	Daily	1986	Bengali	28,875
Zamana	Daily a.m	1955	Bengali	17,000
Daily Life	Daily a.m	1977	English	16.065
Azadi	Daily a.m	1959	Bengali	13,000
Dainik Naya Bangla	Daily	1978	Bengali	12,000
People's View	Daily	1970	English	4,018
Purba Tara	Daily	1970	Bengali	4,003
Published in Khaulna				
Daily Purbanchal	Daily	-	Bengali	42,000
Dainik Probha	Daily	1977	Bengali	10,505
Tribune	Daily a.m	1978	English	8.060
Jana Barta	Daily	1974	Bengali	5,000
Daily Janabarta	Daily	1976	Bengali	3,175
Purbanchal Daily	Daily	1974	Bengali	3,000
Published in Rajshahi				
Dainik Barta	Daily a.m	1976	Bengali	3,000
Rajshahi Barta	Daily	1961	Bengali	1,120

Published in Jeso				
Runner	Daily	1980	Bengali	3,150
Thikana	Daily	1976	Bengali	3,150
Spuulinga	Daily	1976	Bengali	3,050
Published in Dinajpur				
Dainik Uttara	Daily	1974	Bengali	6,705

Source: Editor & publisher international year book, 1999, Lent, 1982, *Personal Communication

New Eletronic Media

	Mainline telephones		Cellular telephone		Computers		Internet	
	Number (000)	Per100 People	Number (000)	Per100 People	Number (000)	per100 People	Number of hosts	Number of users
1990	241.8	0.22	0.00	0.00	...	...	0	...
1996	316.1	0.26	2.5	0.00	...	...	0	....
1997	...	...	52.9	0.04	...	...	0	...
1998	482.5	0.40	75.0	0.06	...	...	0	...

Source: ITU. 1998, APT, 1999.

Broadcasting Data (1996)

Radio

Bangladesh Betar (Radio Bangladesh) Stations	9
Program by type	
News	90 h/m
Entertainment	2,120
Educational	175
Cultural/Rligious	300
Other	600

Television

BTV (government owned)	2 Station
	12 relay stations
Program by type:	123.30 h/quarter
News	463.00
Entertainment	46.00
Educational	79.19

Cultural/Religious	56.57
Commercial	76.78
Others	38.36
Ekushey TV (Privately owned to start end of 1999)	

4.3 भूटान में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी

4.3.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

भारत एवं चीन के मध्य 47000 वर्ग किलोमीटर में फैले भूटान को हिमालय की पर्वत मालाएँ चीन से अलग करती हैं। इस देश का भू-भाग अधिकांशत: पहाड़ियां और घाटियां हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। दो प्रतिशत जमीन खेती योग्य है। यहां गर्मियों का मौसम ठंडा और शीतकाल सर्द रहता है। राजधानी थिम्पु की जनसख्या 40,000 है। देश की अनुमानित जनसंख्या कुल 7,59,000 है। भुट्टानियों की जनसख्या 50 प्रतिशत, नेपालियों की 35 प्रतिशत एवं शेष विस्थापित आदिवासी 15 प्रतिशत हैं। यह 75 प्रतिशत लोग बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं। बाकी लोग हिन्दु धर्म को मानते हैं। पुरुषों में 40 प्रतिशत एवं महिलाओं में साक्षरता 30 प्रतिशत है। यूनेस्को (1999) ने सन् 2000 में साक्षरता का प्रतिशत 47.3 माना है।

भूटान के 8वीं सदी से सांस्कृतिक ऐतिहासिक एवं धार्मिक सम्बन्ध तिब्बत से रहे है। चीन के तिब्बत पर एकाधिकार के समय 1959 में लगभग 6000 तिब्बतियों ने भूटान में शरण ली और वहाँ की नागरिकता ग्रहण की। प्रारम्भ में राजशाही राजनैतिक व्यवस्था रही है। बीसवीं सदी के प्रारम्भ में तिब्बत के मॉडल पर धार्मिक प्रमुख जेखन्पो को सर्वोच्च स्थान दिया गया। ब्रिटेन के मार्गदर्शन पर 1907 में वंशगत राजशाही प्रारम्भ हुई। चीन के तिब्बत पर एकाधिकार से पूर्व भूटान की राजनीति अलग-अलग रही। चीन की साम्राज्यवाद प्रवृत्ति को देखते हुए वहां के नरेश जिग्मे दोरजी ने 1961-66 की पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की और भूटान के आधुनिकीकरण के प्रयास शुरू किए। भारत के साथ लम्बी अवधि के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम किए। भारत ने थिम्पु को भारतीय सेना से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण सहयोग दिया तथा विकास में हाथ बंटाया।

भूटान का विभिन्न संविधान नहीं है। राजा ही राज्य का मुखिया है। 1953 में वहाँ राष्ट्रीय एसेम्बली की स्थापना की गई। 1998 में राजा द्वारा दो महत्वपूर्ण अधिकार एसेम्बली को दिए गए। एक तो यह कि क्राउन प्रिंस के हक में दो तिहाई बहुमत से एसेम्बली राजा को हटने पर विवश कर सकती है। दूसरा यह कि मंत्रीमंडल के अधिकांश सदस्यों का यह चुनाव कर सकती है। लेकिन राजनैतिक दलों एवं यूनियन गतिविधियों पर पाबंदी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील राजा है और वह उस न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है।

4.3.2 जनसंचार: उद्भव एवं विकास

4.3.2.1 समाचारपत्र

भूटान में 20वीं सदी के मध्य तक जनसंचार माध्यमों ने जड़ें तक नहीं पकड़ी। अलग-थलग रहने के कारण कम आबादी वाले इस देश में 1950 तक बौद्ध मोनेस्ट्रीज में लकड़ी के ब्लॉक से छपाई करने की पुरानी पद्धति से बौद्ध धर्म की पुस्तकें छापी जाती थी। वहीं औपचारिक शिक्षा दी जाती थी। भूटान का पहला राष्ट्रीय पत्र कुजेन्सिल क्लेरिटी (Kunjesil Clarity) सरकारी गजट के रूप में 1965 में प्रकाशित हुआ। 1961 की पहली पंचवर्षीय योजना के सन्दर्भ में इसे पहले पाक्षिक और फिर साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित किया गया। भूटान के सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ इस पत्र को भी विकसित किया गया। 1986 में भूटान सरकार के सूचना विभाग ने इस बुलेटिन को यू.एन. डेवलपमेन्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत एक गम्भीर समाचारपत्र का रूप दिया। 12 पृष्ठीय यह साप्ताहिक पत्र टेबलॉयड साईज में जोंगखा, अंग्रेजी एवं नेपाली भाषाओं में छपने लगा।

1981-86 की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के समय जनसंचार माध्यमों के विकास को गति मिली। यह अनुभव किया गया कि राष्ट्रीय विकास आत्म-निर्भरता एवं आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में जनसंचार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका (डी.एस.सी.डी.) की स्थापना की। बाद में डी.एस.सी.डी. का नाम डेवलपमेन्ट कम्यूनिकेश कारपोरेशन कर दिया गया जो कम्यूनिकेशन मंत्रालय के अधीन काम करने लगी।

'ह्यूमन राईट्स आर्गेनाईज भूटान रिव्यू' मासिक का 1993 में प्रकाशन शुरू किया गया। इसे भूटानीज खनिज अपील मूवमेंट कोआर्डिनेटिंग कौंसिल का सहयोग था। ये दोनों विपक्षी राजनैतिक दल है जिनका आधार नेपाल में है।

4.3.2.2 रेडियो

रेडियो की शुरूआत नेशनल यूथ एसोसिएशन ने सप्ताह में एक घंटे के कार्यक्रम के साथ 1972 में की। स्वैच्छिक रूप से अपने स्टेशन को न चला पाने के कारण सरकार से देखभाल की प्रार्थना की गई। 1979 में मिनिस्ट्री ऑफ कम्यूनिकेशन ने इस स्टेशन की अधिगृहीत कर लिया और भूटान ब्रोडकास्टिंग सर्विस प्रारम्भ की। 1986 में यूनेस्को ने बी.बी.एस. को 10 कि.वा. का शार्टवेव ट्रांसमीटर उपलब्ध कराया जिससे पहली बार पूरे देश में प्रसारण सम्भव हुआ। भारत की सहायता से मार्च, 1991 में बने नए 50 कि.वाट प्रसारण क्षमता वाले परिसर में बी.बी.एस. ने काम शुरू किया।

सरकार द्वारा सहायता की मांग पूरी करते हुए यूनेस्को तथा डेनिस इन्टरनेशनल डेवलपमेन्ट एसोसिएशन ने एक महती परियोजना 1989-92 पूरी की ताकि स्तरीय कार्यक्रमों का निरन्तर प्रसारण सम्भव हो सके। प्रसारण एवं तकनीकी सुविधाएँ भी प्रदान कराई गई। पांचवीं योजना की विकास प्रक्रिया के लिए खासतौर पर रेडियो की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि असाक्षरता का प्रतिशत अधिक था। 1998 में 60 प्रतिशत आबादी के पास रेडियो

रिसीवर थे। भूटान की यह एक मात्र प्रसारण संस्था बी.बी.एस. हर सप्ताह तीस घंटे चार भाषाओं में प्रसारण करती हे। 1994 में 52 आऊटलेट थे जिनमें 11 का उपयोग मौसम एवं अन्य जानकारियों के लिए किया जाता है।

4.3.2.3 टेलीविजन

2 जून, 1999 तक भूटान में घरेलू टेलीविजन सेवा का सूत्रपात नहीं हुआ था। 1989 में निजी सेटेलाईटं डिशेज पर रोक लगा दी गई थी। विदेशी फिल्मों की लोकप्रियता को देखते हुए ऐसी फिल्मों को टेलीविजन में दिखाए जाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने तथा विकास से सम्बन्धित संदेशों को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए स्थानीय स्तर पर तैयार दृश्य-श्रव्य माध्यमों का उपयोग किया जाता था। इनमें विकास संबंधी कार्यक्रमों, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनैतिक घटनाओं से संबंधित कार्यक्रम शामिल थे। डेवलपमेन्ट सपोर्ट कम्यूनिकेशन डिवीजन (डी.एस.सी.डी.) द्वारा इस प्रकार की विकास सम्प्रेषण व्यूह रचना तैयार करने में योग देती थी।

भूटान नरेश ने 1998 में यह घोषणा की कि जब उनका देश स्वंय अपने टेलीविजन कार्यक्रम तैयार करने में सक्षम होगा, भूटान में टी.वी स्टेशन खोल दिया जायेगा। तदनुसार भूटान के पहले टी.वी स्टेशन ने 2 जून, 1999 को सेवाएं शुरू की। इससे पूर्व भूटान के नगरीय क्षेत्रों में जिनके पास रेडियो कैसेट रिकार्ड थे, वे विदेशी फिल्में देखते थे। यद्यपि परम्परागत मूल्यों एवं संस्कृति की संरक्षा के लिए विदेशी फिल्मों पर रोक थी परन्तु चोरी छिपे यह व्यवसाय चलता था। भूटान में भारत की हिन्दी फिल्में तथा थाईलैण्ड, हांगकांग से फिल्मों की अच्छी माग थी।

4.3.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी

भूटान में इन्टरनेट सेवाएं भी 2 जून, 1999 से प्रारम्भ हुई। एक साल में 500 सब्सस्क्राईबर तैयार हो गए। कम्यूनिकेशन मन्त्रालय के टेलीकाम अनुभाग में इूकवेट शुरू किया गया। यह कार्य कनाडा डेवलपमेन्ट रिसर्च सेन्टर के सहयोग से किया गया। क्यूएसेल कॉपोरशन ने पहले 1997 में सिंगापुर की सिबखेले टेक्नोलॉजी के सहयोग से अपने समाचारपत्र का ऑन लाईन प्रकाशन प्रारम्भ कर दिया था। 1998 में लगभग 4 हजार कम्प्यूटर थे जिनमें 80 प्रतिशत थिम्पु में उपलब्ध थे। 1998 के अन्त तक भूटान में इन्टरनेट की सीधी पहुंच नहीं थी। यू.एन.डी.पी. ने अपने नेटवर्क से संचार माध्यमों को ई-मेल सुविधा प्रदान कर रखी थी। 1998 में आई.आर.डी.सी. के सहयोग से टेली कम्यूनिकेशन अनुभाग ने अन्तर्राष्ट्रीय ई-मेल के लिए राष्ट्रीय इन्टरनेशनल इन्टरनेट सुविधाएं तैयार की।

वर्ल्ड वाइड तकनोलॉजी के अन्तर्गत भूटान में राष्ट्रीय स्तर पर ई-मेल कान्फ्रेंसिंग आदि इन्टरनेट सेवाएं उपलब्ध हैं।

4.3.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति

भूटान की सातवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 में निजी क्षेत्र के विकास पर बल देने की नीति ने 18 सितम्बर, 1992 के शाही आदेश के अन्तर्गत निजी जनसंचार माध्यम संगठनों

के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। आदेश में कहा गया कि "राष्ट्रीय केन्द्रीयकरण नीति के अनुरूप सरकार यह लक्ष्य है कि राष्ट्रीय विकास के हर क्षेत्र में विभिन्न माध्यमों की व्यावसायिक (प्रोफेशनल) वृद्धि के लिए सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिया जाए। सरकार राज्य के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विकास के लिए भूटानी समाज के सभी वर्गों को इस प्रक्रिया में शामिल करना चाहती है।"

सरकार के इस प्रकार आर्थिक विकास के उद्देश्य के साथ जनसंचार माध्यमों की दुनिया में विकास एवं प्रगति की प्रवृत्ति के सन्दर्भ में सरकार ने जनसंचार माध्यमों को निजी क्षेत्र में विकसित होने का अवसर दिया। इससे उस समय जिन माध्यमों के खर्चे का भार सरकार पर था, उससे भी उसे मुक्ति मिली। इसी नीति को आठवी योजना (1997-2002) में बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया। योजना के मुख्य उद्देश्यों में सांस्कृतिक एवं परम्परागत मूल्यों, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय सुरक्षा, संतुलित विकास, संस्थागत विकास, मानव-संसाधन विकास, निजीकरण एवं निजी क्षेत्र पर जोर दिया गया।

1998 तक भूटान सरकार की यह इच्छा नहीं थी कि टेलीविजन शुरू किया जाए क्योंकि वहां के नरेश का विचार था कि इससे पश्चिमीकरण को ही आधुनिकीकरण मानने का युवाओं में भ्रम पैदा होगा। लेकिन पश्चिमी देशों में शिक्षित लोगों एवं नगरीय जनता की लगातार मांग के सन्दर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक प्रसारणों एवं विदेशी माध्यमों की मांग को टालना कठिन हो रहा था। अन्तर्राष्ट्रीय सेटेलाईट प्रसारण के बढ़ते दबाव के बीच भूटान में इस प्रकार के बाहरी माध्यमों के आक्रमण को टालना कठिन हो गया था। आखिर दूरदराज के इलाकों तक आधुनिक जनसंचार माध्यमों को पहुंचाने के लिए सरकार को राजी होना पड़ा।

भारत सरकार द्वारा लगातार बी.बी.एस. को ब्राडकास्ट जर्नेलिज्म में प्रशिक्षण देने, तकनीशियनों एवं प्रबन्धकों को प्रशिक्षण प्रदान करने का सहयोग दे रही है। यद्यपि पहाड़ी क्षेत्र होने एवं सड़कों की खराब दशा एवं दूरदराज़ बस्तियों के कारण जनसंचार माध्यमों के विकास में कई बाधाएं हैं, मौसम के उतार-चढ़ाव भी परेशानी पैदा करते हैं, लेकिन भूटान सरकार जनसंचार सेवाओं के विस्तार के लिए प्रयत्नशील है।

4.3.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे

भूटान में स्वतन्त्रता अभियानों एवं विभिन्न समुदायों के बीच सौहार्द उत्पन्न करने के मुद्दे के प्रसंग में जनमत की अभिव्यक्ति, विचार-विनिमय और वाद-विवाद के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस की जरूरतों को देखते हुए प्रेस की स्वतन्त्रता एवं जनसंचार माध्यमों के विस्तार की आवश्यकता प्रतिपादित की जाती है। सरकार विदेशी माध्यमों के प्रवेश के खिलाफ है। वह प्रसारण सेवाओं एवं माध्यमों के विकास सम्बन्धी लाभ उठाने के लिए प्रसार चाहती है। राजशाही शासन व्यवस्था में स्वतन्त्रता की कल्पना की सीमाएं हैं लेकिन भूटान वासियों में अपने देश की छवि को एशिया में एक आधुनिक राज्य के रूप में प्रस्तुत करने की ललक है।

बोध प्रश्न- 1

1. दक्षिणी एशिया में कौन-कौन से देश सम्मिलित हैं?
2. बंगला देश में नई सूचना प्रौद्योगिकी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

3. भूटान के जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति की घोषणा कीजिए।

4. भूटान में रेडियो और टेलीविजन की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिए।

Media

Mass Media Penetration Bhutan

	Radio receiver		TV receivers		Daily Newspaper		
	Number (000)	per100 people	Number (000)	Per100 people	Number	Cire'n	Per100 people
1980	7	0.50	-	-	-	-	-
1985	18	1.20	-	-	-	-	-
1990	24	1.50	-	-	-	-	-
1995	30	1.60	10	0.54	-	-	-
1996	35	1.80	10	0.55	-	-	-
1997	37	1.90	11	0.55	-	-	-
1998	-	-12*	1.0*	-	-	-	-

Source: UNESCO, 1999, * ITU. 1999.

4.4 भारत में जनसंचार और नई सूचना -प्रौद्योगिकी

4.4.1 राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्य

भारत दुनिया का सातवां विशाल देश है। यह हिमालय पर्वतमालाओं और सागरों से घिरा है। एक ओर हिन्द महासागर है तो पश्चिम में अरब सागर, उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन, भूटान और नेपाल तथा पूर्व म्यांमार और बंगलादेश की सीमाएं हैं। दक्षिण में श्रीलंका है। उत्तर से दक्षिण तक जलवायु भिन्नता है। यह देश विभिन्न प्रकृति एवं वन्य जीवन का धनी है तथा मानसून पर निर्भर है।

भारत की आबादी 20 सदी के अन्त में एक अरब की जनसंख्या पार कर गई। यह संसार की आबादी का 16 प्रतिशत है। लेकिन भू-भाग में दुनिया के भू-भाग का 2.4 प्रतिशत में भारत बसा है। इस प्रकार आबादी का घनत्व 337 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किमी. आता है। बारह नगर ऐसे हैं जिनकी आबादी एक मिलियन से अधिक है। भारत की साक्षरता का प्रतिशत 5.35 है। इसमें पुरुषों की साक्षरता 67 प्रतिशत है, जबकि महिलाओं का 39 प्रतिशत है। केरल में शिक्षा का प्रतिशत सर्वाधिक है। देवनागरी लिपि को सरकारी भाषा के रूप में संविधान में विशेष स्थान दिया गया है। लेकिन अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को भी जारी रखा गया है। भारत में 17 भाषाएँ और 844 बोलियां बोली जाती हैं। कुल आबादी का 80 प्रतिशत हिन्दु, 12 प्रतिशत मुसलमान, 2.4 प्रतिशत ईसाई, 2 प्रतिशत सिक्ख 0.78 प्रतिशत बौद्ध, 0.4 प्रतिशत जैन तथा 0.4 अन्य धर्म मानने वाले लोग यहां निवास करते हैं। भारत की सभ्यता अति प्राचीन है। यहां की समृद्ध प्राकृतिक सम्पदा एवं महान संस्कृति ने इतिहास के लम्बे दौर में विदेशी व्यापारियों एवं यात्रियों को आकर्षित किया। भारत पर अनेक हमले हुए। भारतीय संस्कृति ने कई

आक्रान्ताओं को अपने में समाया। भारत की संस्कृति विविधता में एकता का अनुपम उदाहरण है।

4.4.2 जनसंचार माध्यम : उद्भव एवं विकास

4.4.2.1 समाचारपत्र

18वीं सदी से भारत पर अंग्रेजों का साशन रहा। भारत के जनसंचार माध्यमों के विकास में अंग्रेजी शासन के दो महत्तवपूर्ण प्रभाव परिलक्षित हैं। पहला प्रभाव अंग्रेजी भाषा का है जिसे उन्होने भारत में फैलाया। दुसरा जेम्स आगस्ट्स हिकी नामक अंग्रेज़ ने कलकत्ता में प्रेस लगाकर भारत में पहला समाचारपत्र प्रकाशित किया।

भारत में समाचार माध्यमों का इतिहास दो भिन्न विचारधाराओं और उद्देश्यों को लेकर चलने वाले समूहों के परस्पर संघर्ष का इतिहास है। एक समूह में सदैव अंग्रेजों के खिलाफ और भारत की आजादी के लिए समाचारपत्रों का प्रकाशन किया। दूसरे पक्ष में अंग्रेजी सत्ता के पक्षधर लोगों का समूह था। कुछ समाचारपत्रों को छोड़कर अंग्रेजों ने ब्रिटिश साम्राज्य को पुष्ट करने के लिए समाचारपत्रों का सहारा लिया। राष्ट्रवादी भारतीयों ने सामाजिक, धार्मिक. शैक्षिक एवं राजनैतिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए समाचारपत्र प्रारम्भ किए।

इसाई मिशनरियों ने धार्मिक साहित्य का प्रकाशन करने के लिए 15वीं एवं 16 सदी में छापाखाने शुरू किए। 29 जनवरी, 1780 को हिक्की ने बंगाल गजट नामक पहला समाचारपत्र प्रकाशित किया। भारत के समाचारपत्रों का विकास चारों चरणों में हुआ है। पहला चरण 1818-67 जिसमें राजा राममोहन राय द्वारा हिन्दू समाज के सुधार हेतु प्रकाशित समाचारपत्र एवं अंग्रेजी सत्ता से संघर्ष का समय माना गया है। कलकत्ता और बम्बई भारतीय प्रेस के प्रमुख केन्द्र थे। रॉबर्ट बाईट ने 1861 में 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' की स्थापना की। 1857 के गदर कौ भारतीय स्वतन्त्रता का पहला संघर्ष माना जाता है। इस समय अंग्रेजों के अधीन समाचारपत्रों ने साम्प्रदायिक भावनाओं को उभारने की नीति अपनाई। इस नीति ने भारतीय प्रेस के दूसरे चरम को जन्म दिया।

विकास का दूसरा चरम 1867-1918 तक माना जाता है। इस काल में अंग्रेजों के साम्राज्यवाद को सहयोग करने वाले समाचारपत्रों की कड़ी स्पर्धा के बावजूद भारत के राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वाले लोगों द्वारा शुरू समाचारपत्र उभरने लगे। बालगंगाधर तिलक, महादेव गोविन्द रानाडे, दादाभाई नौरोजी एवं अन्य राष्ट्रवादी नेताओं ने अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ तथा सामाजिक सुधार के लिए समाचारपत्रों को हथियार बनाया। इस काल में कई महत्वपूर्ण समाचारपत्र प्रारम्भ हुए जैसे अमृत बाजार पत्रिका, स्टेट्स मैन, दी हिन्दू, दी पायोनियर आदि समाचार पत्र शुरू हुए। टेलीग्राफ लाइनें भी इसी काल में लगी। ब्रिटिश सरकार ने सरकार की आलोचना करने वाले समाचारपत्रों पर पाबंदी लगाने के लिए 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया लेकिन राष्ट्रवादी पत्रकारों द्वारा पोषित एवं संचालित प्रेस ने भारत में स्वतन्त्रता सग्राम के बीज बो दिए थे।

समाचारपत्रों के विकास का तीसरा चरण 1919-36 का माना जाता है। स्वतन्त्रता आन्दोलन के प्रमुख नेताओं जैसे महात्मा गांधी ने अपने विचारो को फैलाने के लिए यंग इण्डिया (1919), हरिजन (1932) एवं गुजराती में नवजीवनशुरू किए मद्रास में टी. प्रकाशन ने 1922 में 'स्वराज्य' का प्रकाशन प्रारम्भ किया। 1923 में अंग्रेजी का 'हिन्दुस्तान टाइम्स' प्रारम्भ हुआ, जिसने स्वतन्त्रता संग्राम का समर्थन किया और अंग्रेजों की नाराजगी झेली।

भारतीय प्रेस के विकास को आजादी से पूर्व चौथा चरण 1937-47 का दशक माना जाता है। इस काल में पत्रकारिता काफी परिपक्व हो चुकी थी। स्वतन्त्रता संग्राम में दिलचस्पी के साथ प्रेस अन्य प्रमुख व्यावहारिक मुद्दों पर भी विचार करने लगी। दूसरे विश्वयुद्ध एवं स्वतन्त्रता संग्राम की उथल-पुथल का दौर रहा। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में 'नेशनल हेराल्ड' की स्थापना की। राष्ट्रवादी समाचारपत्रों का झुकाव स्वतन्त्रता संग्राम को मजबूत बनाने का रहा। 15 अगस्त,1947 को भारत की आजादी के बाद भरतीय समाचारपत्र जगत् के लिए एक नए युग का प्रारम्भ था। सरकार ने 1952 एवं 1977) में प्रेस कमीशन बनाए ताकि प्रेस सम्बन्धी कानूनों की जांच की जा सके तथा प्रेस के विकास के उपाय किए जा सकें। 1965 में प्रेस कॉन्सिल की स्थापना की गई। लेकिन, 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया। स्वतन्त्र अभिव्यक्ति एवं प्रेस पर पाबंदी लगा दी। 19 महीनों का आपातकाल भारतीय प्रेस के लिए एक बड़ा झटका था।

आपातकाल के बाद भारत में पत्रकारिता का स्वरूप बदल गया। इसका झुकाव व्यावसायिकता की ओर बढ़ने लगा। मुद्रण की नई टेक्नोलॉजी एवं संचार क्रान्ति ने समाचारपत्रों के विकास एवं विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुद्रण एवं अन्य क्षेत्रों में कम्प्यूटर का इस्तेमाल होने लगा। समाचारपत्रों की सामग्री में परिवर्तन आया। समाचार प्रकाशन का कार्य एक विशेष रंग-रूप में उभरा। अनेक समाचारपत्र एवं उनके संस्करण प्रारम्भ हुए। मुक्त अर्थव्यवस्था एवं इलेट्रॉनिक माध्यमों से प्रतिस्पर्द्धा आदि कई ऐसी बातें हैं जिन्होंने पत्रकारिता को नए आयाम दिए तथा पत्रकारिता का व्यावसायिक स्तर भी बढ़ा। अनेक राज्यों के समाचारपत्रों ने अपने राज्य के विभिन्न अंचलों से समाचारपत्र के विभिन्न संस्करण प्रकाशित करने शुरू किए। उपग्रह संचार व्यवस्था (सेटेलाइट) ने समाचारपत्रों के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

4.4.2.2 रेडियो

रेडियो का भारत में प्रारम्भ ब्रिटिश शासन के समय ही हो गया था। एमेच्योर रेडियो क्लब को 1924 में सरकार ने प्रसारण की इजाजत दी। इण्डियन ब्राडकास्टिंग कम्पनी ने निजी क्षेत्र में बम्बई एवं कलकत्ता में 1927 में रेडियो सेवाएं शुरू की। उस समय निजी क्षेत्र ने प्रसारण के क्षेत्र में जो पहल की, उसकी परछाई आज टी.वी के क्षेत्र में देख सकते हैं जहां निजी टी.वी चैनलों को संचालन की छूट है। दरअसल, निजी मेच्योर क्लब्स के प्रयासों ने तत्कालीन सरकार को प्रसारण प्रणाली के विकास के लिए बाध्य किया।

अंग्रेजी सरकार ने इण्डियन स्टेट ब्राडकास्टिंग सर्विस की 1930 में स्थापना की। 1936 में इसका नाम 'ऑल इण्डिया रेडियो' या 'आकाशवाणी' किया गया। भारत की आजादी के समय

1947 में दिल्ली, बम्बई, मद्रास, लखनऊ, पेशावर (अब पाकिस्तान में) तथा ढाका (अब बंगलादेश में) में रेडियो सेवाएं जारी थीं। सरकार की मंशा गैर राजनैतिक कार्यक्रमों के प्रसारण एवं सूचना माध्यम के रूप में रेडियों का विकास करने की रही, लेकिन यह इतना शक्तिशाली माध्यम था कि इस पर सरकार ने सदैव नियन्त्रण रखा और यह ध्यान रखा कि इसका उपयोग स्वतन्त्रता संग्राम के लिए सहायक न बने।

आजादी के बाद रेडियो सरकार की नीतियों एवं विकास योजनाओं के संदर्भ में सम्प्रेषण का एक अति महत्वपूर्ण साधन बन गया। कृषि, साक्षरता लोक संगीत, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य आदि कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीण चेतना का यह एक उपयोगी माध्यम साबित हुआ। लेकिन रेडियो के विस्तार की गति धीमी रही। रेडियो सेवाओं के विस्तार की संरचना का दौर 1975-76 में तब शुरू हुआ जबकि इण्डियन स्पेस रिसर्च आर्गनाइजेशन (इसरो) ने भारत के विभिन्न प्रदेशों के 2400 गांवों में कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए यू.एस. नेशनल एरोनाटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) से सैटेलाईट प्राप्त किया।

भारत की आजादी के समय आकाशवाणी के कुल छः स्टेशन थे। सन् 1999-2000 में यह संख्या बढ़कर 198 हो गई। साथ ही 310 प्रसारण केन्द्रों का जाल बिछ गया देश के 90 प्रतिशत क्षेत्र में 97% प्रतिशत आबादी की पहुंच में रेडियो प्रसारण पहुंच गया। अब रेडियो और दूरदर्शन एक स्वयत्तशासी संस्था के अंग हैं। 1997 में 'प्रसार भारती' का गठन किया गया। सरकार या किसी राजनैतिक दल के दखल के बिना एक सशक्त जनसंचार प्रणाली के विकास की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया।

आकाशवाणी: आकड़े एक नजर में

1. केन्द्र-198	
2. ट्रांसमीटर	
(क) मीडियम वेव	144
(ख) शार्ट वेव	55
(ग) एफ.एम.	111
कुल 310	
3. कवरेज	
क्षेत्रफल के हिसाब से	90.0%
जनसंख्या के हिसाब से	97.3%

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट 1 999-2000, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

4.4.2.3 टेलीविजन

भारत सरकार की जनसंचार माध्यमों के प्रति मुक्त दृष्टि का परिणाम है कि 20वी सदी के अन्तिम दशक तक आते-आते जनसंचार माध्यमों के विकास की गति तेज हुई है और प्रसारण माध्यमों की लोकप्रियता बढ़ी है। टेलीविजन समाचारों एवं मनोरंजन की दृष्टि से एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरा है। यद्यपि प्रसारण माध्यमों की स्थापना के प्रारम्भिक लक्ष्यों

में देश के विकास को गति देना प्रमुख लक्ष्य था लेकिन बाद में यह मुक्त अर्थव्यवस्था एवं मुक्त संप्रेषण के सन्दर्भ में व्यापक बन गया।

भारत में टेलीविजन का प्रारम्भ 1959 में एक शैक्षणिक प्रयोग के रूप में दिल्ली में शुरू हुआ जहां टी.वी क्लब्स के 24 टी.वी सेट्स पर कार्यक्रम प्राप्त होते थे। नियमित टी.वी सेवाएं दिल्ली में 1965 में शुरू हुई। 1975 में देश के 12 नगरों तक टी.वी कार्यक्रमों को बढ़ाया गया। 1982 के बाद भारत में टेलीविजन नेटवर्क का विकास विश्व के एक बहुत बड़े नेटवर्क के रूप में तैयार हुआ। भारतीय टेलीविजन का स्वरूप यूरोप के मॉडल पर एक मजबूत नेटवर्क के रूप में जनसेवा को समर्पित नेटवर्क पर आधारित है जहां की निजी सैटेलाइट चैनल्स को संचालन की इजाजत दी गई है। 1982 में एशियन गेम के समय रंगीन टेलीविजन कार्यक्रम प्रारम्भ हुए। 1997 तक टेलीविजन ट्रांसमीटर की संख्या 900 पर पहुंच गई। सन 1985 से 2000 तक की अवधि में ही टी.वी. नेटवर्क दूरदर्शन ने अपने 20 चैनल्स से 47 अलग-अलग केन्द्रों से 1060 ट्रांसमीटरों द्वारा देश के 74.8 प्रतिशत भू-भाग और 87.9 प्रतिशत आबादी तक अपनी पहुँच का विस्तार किया। 12 भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत करना शुरू किया गया। यूनेस्को के आंकड़े के अनुसार भारत (1999) में 63 मिलियन टी.वी. रिवर्स थे।

दूरदर्शन की वर्तमान स्थिति

कार्यरत चैनल

वर्तमान में दूरदर्शन के निम्नलिखित 20 चैनल प्रसारण कर रहे हैं -

(क) प्राथमिक चैनल	- डी.डी. 1
(ख) मैट्रो चैनल	- डी.डी.2
(ग) समाचार और सामयिक घटनों के चैनल	- डी.डी. न्यूज
(घ) खेल चैनल	- डी.डी. स्पोर्ट्स
(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय चैनल	- डी.डी. इण्डिया
(च) क्षेत्रीय चैनल	- 11 चैनल
(छ) राज्य नेटवर्क	- 4

इन चैनल की कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं को दूरदर्शन के देश भर में फैले 47 स्ट्रडियो पूरा करते हैं। दूरदर्शन केन्द्रों पर उपग्रह अपलिंकिंग सुविधा उपलब्ध है। सात दूरदर्शन केन्द्रों-मुम्बई, चैन्नई, गुवाहाटी, कलकत्ता, तिरूवन्तपुरम, बंगलौर और हैदराबाद पर एनालांग और डिजिटल दोनों के साथ-साथ अपलिंकिंग की सुविधा उपलब्ध है। विभिन्न सेवाओं के लिए पांच अलग-अलग उपग्रह के 20 ट्रांसपोटर प्रयोग में लाए जाते हैं। दूरदर्शन के कार्यक्रम इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। (वेवसाइट-http/ddindia-net) ।

2. भू-केन्द्र नेटवर्क

डी.डी.-1 के लिए ट्रांसमीटर	- 1000
डी.डी.-2 के लिए ट्रांसमीटर	- 57
अन्य ट्रांसमीटर	- 3

कुल - 1060 ट्रांसमीटर

(वार्षिक रिपोर्ट 1999-2000) सूचना और प्रसारण मंत्रालय

1985 से 2000 तक भारत में टेलीविजन परिदृश्य में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। स्थानीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय निजी टी.वी. संचालकों ने निजी चैनल्स के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। केबल एवं टी.वी. चैनल्स का उद्भव 1980 के दशक में हुआ। स्टार, सी.ए.एन., बी.बी.सी., केबल एवं अनेक राष्ट्रीय चैनल शुरू हुए। टाइम्स चैनल, हिन्दुस्तान टेलीविजन, टेलीविजन बाजार, एनाडु टेलीविजन, यू.टी.वी. आदि कई चैनल्स का प्रारम्भ बड़े समाचारपत्रों ने आरम्भ किया।

4.4.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी

भारत में नई सूचना तकनालॉजी के विकास को गति देने की दिशा में भारी दबाव और आधुनिकतम सूचनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करने के कारणों से सूचना प्रौद्योगिकी में तेजी से परिवर्तन आए हैं। भारत दुनिया के बड़े सोपटवेयर निर्माता देशों में से एक है। इन्टरनेट सेवाओं की मांग में तेजी आई लेकिन 1998 तक सरकार की नीति के कारण अपेक्षित विकास रुका रहा। सन् 1995 से 1998 तक निवेश संचार निगम लि. ही एकमात्र संस्थान था जो इन्टरनेट सेवाएं प्रदान करता था। कुछ खास उपभोक्ता समूहों के लिए सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अन्तर्गत नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेंटर तथा एज्यूकेशन एवं रिसर्च नेटवर्क द्वारा भी ये सेवाएं प्रदान की जाती थी। ये सेवाएं डिपार्टमेन्ट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन (डॉट) ने 20 निजी संचालकों को लाईसेंस देकर 1998 में इनका निजीकरण कर दिया। 1999 में 116 लोगों को लाईसेंस मिल गए। लाईसेन्स शुल्क भी घटा दिया गया। केबल कम्पनियां भी मैदान मे आ गई। इन्टरनेट पार्लर एवं साईबर केफे खुलने का दौर शुरू हो गया।

जुलाई, 1999 के इन्टरनेट साफ्टवेयर कन्जोररियम के सर्वेक्षण के अनुसार 1997 में 30 हजार उपभोक्ता थे। लगभग 2.3 मिलियन कम्प्यूटर संचालन में थे। केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों ने सोफ्टवेयरों टेक्नालजी पार्क खोलकर अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी में बड़े बहुराष्ट्रीय संस्थानों को भागीदारी के लिए आकर्षित करने की चेष्टा की। भारतीय भाषाओं में वेब साईट तैयार किए गए। कई भारतीय समाचारपत्र 'ऑनलाइन' पर आ गए। विदेशों में रहने वाले भारतीय इन समाचारपत्रों के पाठक हैं । इस प्रकार वाणिज्य, व्यवसाय, राजनीति, शिक्षा, शोध, रोजगार आदि अनेक क्षेत्रो में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने वाली नई सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को समझते हुए भारत ने इसे तेजी से विकसित किया।

4.4.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति

भारत में विकास से संबंधित संचार माध्यमों को बढ़ावा देने की नीति पर बल दिया गया ताकि संचार माध्यमों को परिवर्तन का बड़ा साधन बनाया जा सके। रेडियो और दूरदर्शन को स्वायतत्ता देने के मसले पर एक दशक के वाद-विवाद के बाद 1990 में राष्ट्रपति ने 'प्रसार भारती' बिल को स्वीकृति दी। इसके बाद, 1997 में रेडियो एवं दूरदर्शन के स्वतन्त्र संचालन के लिए 'प्रसार भारती' निगम की स्थापना की गई। यह निगम प्रसारण समिति तथा संसदीय

समिति के प्रति उत्तरदायी है। कुछ शक्तियां सरकार के अधीन हैं। कामकाज में पारदर्शिता के लिए राजस्थान एवं तमिलनाडू सरकार ने सूचना के अधिकार का कानून पास कर दिया। केन्द्र के पास यह मुद्दा विचाराधीन है। भारत में जनसंचार माध्यमों को संविधान के अन्तर्गत स्वतन्त्रता है।

4.4.5 प्रेस स्वतंत्रता के प्रमुख मुद्दे

मुक्त अर्थव्यवस्था एवं वैश्वीकरण के बीच भारत में वैचारिक मतभेद और सामाजिक बदलाव का जोर है। कुछ लोग सरकार की उपस्थिति को जरूरी मानते हैं तो कुछ क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप बिलकुल न होने की बात करते हैं। सूचना के अधिकार को केन्द्र सरकार द्वारा कानूनी रूप देने की माग जारी है। संगठित समूहो की सूचना के अधिकार की मांग तथा नई सूचना टकनोलॉजी के बीच सरकार द्वारा सूचना माध्यमों पर नियन्त्रण का कार्य समस्याएं बढ़ाने वाला है। ऐसे में सरकार की नीतियों के परिवर्तन का कार्य जन भावनाओं के अनुरूप संचालित होता है।

1955 के पत्रकार अधिनियम के अन्तर्गत पत्रकारों को औद्योगिक कर्मचारी माना गया है। इसके द्वारा पत्रकारों के न्यूनतम वेतन तय करने की दिशा में भी मार्गदर्शन दिया गया है। अर्थव्यवस्था एवं जनसंचार माध्यमों के वैश्वीकरण के सन्दर्भ में संस्थागत एवं माध्यमों के संचालन पर प्रभाव पड़ेगा।

Newspaper Ownership Patterns

Form of ownership	Number for which Circulation available	Cire'n (000)	Percentage share in total circulation
Individual	4,646	22,397	36.6
Joint stock companies	515	22,266	36.4
Firm/Partnerships	407	6,351	10.4
Societies/associations	1,347	4,495	7.6
Trusts	275	3,306	5.4
Government	213	1,347	2.1
Others	219	985	1.5
Total	**7,622**	**61,147**	**100.0**

Cable & Satellite Television, 1992-97

June, 1992	1.28 million
February, 1993	3.30 million
October, 1993	7.28 million
June, 1995	9.30 million
June, 1997	14.9 million

Source : Various National Readership Surveys. 1995 &1997 Ministry of Information and Broadcasting, 1997 Balasubramanian, 1999 Note: The numbers refer only to urban areas.

Satellite Channels

Satellite	Location	Channels
Asiasat-1	100.5 E	Star Plus, Star Sports, Channel V, ZEE Cinema, ELTV
Asiasat-2	105.5 E	STAR Movies, NBC, CNBC, PTV-2
PAS-4	68.5 E	Sony, Home, ATN, BBC World, ABNI, TNT, Cartoon Network, Discovery, CNN, MTV
Intelsat-703	57 E	Sun, Sun Music, Sun Movie, NEPC, TV India, Gemini
Intelsat-704	66 E	Eenadu, Vijay
Gorizont-42	142.5 E	Music Asia, Raj

4.5 मालदीव में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी

4.5.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

मालदीव 1190 लघु द्वीपों का एक समूह है जो भारत और श्रीलंका के दक्षिण-पश्चिम में है। हर द्वीप की आबादी 200 है। 300 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्र है। यहां की कुल आबादी 0.3 मिलियन के लगभग है। यहां की आबादी का अधिकांश भाग मुसलमान है। प्रारम्भिक इतिहास के अनुसार अधिकांश लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक 95.7 प्रतिशत है। अंग्रेजी इसकी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है। अरबों के सम्पर्क से यहां की आबादी इस्लाम धर्म की अनुयायी बन गई। सुल्तानों के शासन में उथल-पुथल रही। 26 जुलाई, 1965 को यह देश आजाद हुआ। माले यहां की राजधानी है। यहां राष्ट्रपति शासन प्रणाली है।

4.5.2 जनसंचार: उद्भव एवं विकास

4.5.2.1 समाचारपत्र

मालदीव में' अलइस्लाह समाचारपत्र के प्रकाशन के साथ प्रेस का प्रारम्भ 1943 में हुआ। गणतन्त्र और राजतन्त्र के उतार-चढ़ावों के बीच प्रैस के विकास की गति मैं बाधा पड़ती रही। 1990 तक दो दैनिक् और दो-दो साप्ताहिक, पाक्षिक मासिक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन होता था। दैनिक हवीरा 1978 में शुरू हुआ और 'आफाथिस' 1979 में प्रकाशित हुआ।

ये दिवेही और अंग्रेजी भाषाओं में छपते है। अधिकांश समाचारपत्रों का प्रकाशन और वितरण मालदीव की. राजधानी माले तक सीमित है। समाचार-संकलन की प्रक्रिया भी असंगठित है। यद्यपि वहाँ तीन समाचार समितियां हैं।

4.5.2.2 रेडियो

मालदीव में 'वायस ऑफ मालदीव' की शुरूआत 1962 में हुई। रेडियो और टेलीविजन सरकार के अधीन है। यहां दो रेडियो स्टेशन हैं। 95 प्रतिशत जनता तक रेडियो की पहुंच है। दिवेही एवं अंग्रेजी भाषाओं में प्रसारण होते हैं। 37 प्रतिशत सूचनाएं, 32 प्रतिशत मनोरंजन, 16 प्रतिशत शिक्षा तथा 15 प्रतिशत कार्यक्रम धर्म से संबंधित होने हैं। समाचारपत्र नगरीय क्षेत्रों तक सीमित है, रेडियो पूरे देश में सम्प्रेषण का सशक्त माध्यम है।

4.5.2.3 टेलीविजन

'टेलीविजन मालदीव' 1978 में शुरू हुआ। केवल एक ही टी.वी. स्टेशन है जो 6-7 घंटे प्रसारण करता है। अनुमानत दस हजार टी.वी. सेट है। भारत के दूरदर्शन, सी.एन.एन., सी.एफ.आई. एवं अरब ब्रोडकास्टर्स ने सैटेलाईट प्रसारण के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई। ढाचागत सुविधाओं में फिर भी कमी है। हिन्दी, अंग्रेजी फिल्में दिखाने के लिए निजी वीडियो सिनेमा की व्यवस्था है। टी.वी. कार्यक्रम तैयार करने में भारतीय मूल्यों से प्रभावित है। लगभग 60 प्रतिशत कार्यक्रम विदेशी होते हैं। समाचार और मनोरंजन के कार्यक्रमों के प्रसारण के अलावा मालदीव में दूरस्थ शिक्षा देने के राज्यूकेशनत्न मीडिया यूनिट है जो कामनवेल्थ ऑफ लर्निंग की सहायता से शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित करता है। राष्ट्रीय एकता को सुद्रढ़ बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

4.5.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी

मालदीव में सूचना प्रौद्योगिकी का सूत्रपात 1996 में हुआ। देश में 3000 कम्प्यूटर हैं। देश के तीन समाचारपत्र ऑन लाईन पर उपलब्ध है। दक्षिण एशियाई में सर्वाधिक घनत्व के साथ टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध हैं। प्रति 100 व्यक्ति 7.5 मैन लाईन्स है। 80 प्रतिशत भू-भाग में ये सेवा उपलब्ध है।

4.5.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति

मालदीव के संविधान में बोलने, लिखने और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की गारंटी तो है लेकिन सीमाओं में ही यह स्वतन्त्रता है। तीन बातें संविधान के विरुद्ध है। इस्लाम के सिद्धान्तों, समाज की एकरूपता एवं व्यक्ति की प्रतिष्ठा को आघात पहुँचाने का कार्य संविधान के नियमों के खिलाफ है। इस कानूनी ढांचे में प्रेस पर पाबंदी है। रेडियो एवं टेलीविजन पर सरकार का पूर्ण अधिकार है।

4.5.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे

भारत में श्रीलंका के नजदीक इस देश में भारतीय माध्यमों का प्रभाव नहीं है यद्यपि लोग भारत की फिल्मों, पत्र-पत्रिकाओं को पसन्द करते हैं। यह मालदीव में जनतन्त्र को पुष्ट करने की दृष्टि से सीमित भूमिका का निर्वाह करती है लेकिन भविष्य में इसका आधार मजबूत हो सकता है। मालदीव में प्रेस को आंशिक स्वतन्त्रता प्राप्त है। जनसंचार माध्यमों पर सरकार

की पकड़ मजबूत है। आय की दृष्टि से कम सम्भावनाओं के कारण पत्रकारिता का दर्जा एक हॉबी की तरह है । पत्रकारों के प्रशिक्षण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

बोध प्रश्न-2

1. 'भारत में जनसंचार माध्यमों की स्थिति विकासशील है। क्या आप इस मत से सहमत हैं?
2. भारत में समाचारपत्रों की वर्तमान दशा एवं दिशा पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए।
3. 'प्रसार भारती' की स्थापना किन उद्देश्यों को लेकर की गई है?
4. 'मालदीव में जनसंचार' विषय पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए।

Mass Media Penetration

	Radio receivers		TV Reciever		Daily newspaper		
	Numbers (000)	Per100 People	Number (000)	Per100 People	Number	Cire'n	Per100 People
1980	13	8.2	1	9.7	2	1,000	0.6
1985	19	10.3	3	1.7	2	2,000	0.8
1990	25	11.6	5	2.4	2	3,000	1.2
1995	31	12.4	7	2.6	2	3,000	1.2
1996	33	12.9	7	2.6	2	3,000	1.2
1997	34	12.9	7	2.8			
1998			10*	3.9*			

Source : UNESCO, 1999 ITU 1999

4.6 नेपाल में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी

4.6.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

नेपाल एक हिमालय पर्वत श्रृंखलाओ घिरा हुआ राज्य है। इसके पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम में भारत स्थित है और उत्तर में तिब्बत है। 1 ,40,000 की किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है यह देश। भौगोलिक विविधता से परिपूर्ण है। इस देश में दुनिया की सबसे बड़ी 10 पहाड़ी चोटियों में से 8 स्थित हैं। देश की राजधानी काठमांडु में नेपालियों की आधा मिलियन आबादी आवास करती है। राष्ट्रभाषा नेपाली है जो देश के 50 प्रतिशत लोगों की भाषा है। बीस अन्य भाषाएं बोली जाती हैं जिनमें भोजपुरी और मैथिली भाषा प्रमुख है। 86 प्रतिशत आबादी हिन्दू है। 8 प्रतिशत बौद्ध एवं 3 प्रतिशत मुसलमान हैं। शेष अन्य लोग हैं। नेवार्स, भारतीय, तिब्बती, गुरूंग्स, मागर, वमंग भाटिया, शेरपा, राय, लीम्ब्सं आदि निवास करते हैं। शिक्षा का प्रतिशत 40 है। यहां संविधान सम्मत राजशाही है जिसमें शासन की कार्यकारी शक्तियां नरेश एवं मंत्रिमंडल के पास है जो हाऊस ऑफ रिप्रजेन्टेटीब्ज के प्रति उत्तरदायी हैं। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का हर पांच साल में चुनाव होता है। राष्ट्रीय सभा के सदस्यों को प्रतिनिधि सभा चुनती है। इनमें कुछ की नियुक्ति प्रदेश द्वारा तथा कुछ की जनता द्वारा की जाती है।

4.6.2 जनसंचार: उद्भव एवं विकास

4.6.2.1 समाचारपत्र

नेपाल के एक सदी से भी अधिक समय से शासन करने वाले राणा परिवार के मुखपत्र के रूप में 1901 में नेपाल का पहला समाचारपत्र 'गोरखापत्र' प्रकाशित हुआ। यह साप्ताहिक पत्र था जो 1966 में दैनिक हुआ। 1981 में जनतांत्रिक व्यवस्था लागू होने के बाद कई पत्र शुरू हुए। 1957 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कई अंकुश लगाए परन्तु पत्रकारों की लम्बी मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उन समस्याओं के समाधान हेतु प्रेस कमीशन गठित करने की मांग मान ली। 1960 में किंग महेन्द्रा ने संसद भंग कर दी। निजी क्षेत्र के समाचारपत्रों का विकास अवरूद्ध हो गया। समाचारपत्रों की अभिव्यक्ति पर कई प्रकार की रोक लग गई लेकिन सरकार द्वारा नियन्त्रित गोरखा पत्र एवं राईटिंग नेपाल, दैनिक जारी रहे। 1962 में पंचायत प्रणाली लागू हुई। राजनैतिक दलों के पत्रों पर पाबंदी लगा दी गई एवं सरकार की खिलाफत करने वाले सम्पादकों को सजाए हुई। लेकिन पत्रकारों ने हौसला बनाए रखा। आम जनता का विश्वास निजी क्षेत्र द्वारा प्रकाशित समाचारपत्रों में था। 1981 में प्रेस कानून बदले। छोटे पत्रों की संख्या 90 से बढ़कर 400 हो गई। लेकिन कोई समाचारपत्र सरकार की आलोचना नहीं कर सकता था। 1990 में जब 18 अवसरों पर निजी समाचारपत्रों को जब्त कर लिया और 45 पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया तो प्रेस पर दबाव बढ़ गया। संविधान सम्मत जनतंत्र की स्थापना के बाद अप्रैल, 1990 में राजनैतिक चेतना में वृद्धि के साथ समाचारपत्रों के प्रकाशन एवं स्तर में सुधार और वृद्धि का दौर प्रारम्भ होने लगा। 1962 में नेपाल की राष्ट्रीय समाचार समिति बनी। लेकिन इस सरकारी समाचार समिति से निजी पत्रों का विश्वास नहीं जमा।

जनता के असंतोष को देखते हुए नवम्बर, 1991 में नेपाल के संविधान में प्रेस की स्वतन्त्रता की गारन्टी की व्यवस्था की गई। इससे पूर्व भी 1979 में किंग वीरेन्द्र ने प्रेस को आजादी देने की घोषणा की थी।

1951-60 की अवधि में अधिकांश पत्र साप्ताहिक थे। सरकारों का ध्यान सरकारी माध्यमों पर अधिक होने से निजी क्षेत्र के समाचारपत्रों का विकास बहुत धीमी गति से हुआ। जनतांत्रिक प्रणाली शुरू होने पर भी हालत बहुत नहीं सुधरी। समाचारपत्रों के जब्त होने और सजा के डर से लोग इस क्षेत्र में पूंजी लगाने से डरते थे। राजशाही की खिलाफत करना मुमकिन नहीं था। 1990 के दशक में नए संविधान के प्रावधानों से आश्वस्त नेपाल की प्रेस संस्थागत रूप धारण करना प्रारम्भ किया। 1994-97 के बीच सात दैनिक शुरू हुए। इनमें दो अंग्रेजी भाषा के थे। सरकारी पत्रों की प्रसार संख्या बढने लगी। कई सालों तक के सरकारी नियंत्रण के बाद प्रेस के विकास के अवसर मिले। प्रमुख पत्रों मैं गोरखा पत्र, राईटिंग नेपाल, कान्तिपुर, काठमाण्डु पोस्ट, हिमालया टाइम्स, आज का समाचार पत्र आदि हैं। कई साप्ताहिक भी लोकप्रिय हैं। राजनैतिक दल भी अपने हितों के लिए समाचारपत्र प्रकाशित करते हैं। साप्ताहिक पत्र राजनीति सै प्रेरित हैं। पूर्णतया स्वतन्त्र पत्रों की संख्या कम है।

4.6.2.2 रेडियो

सरकार के स्वामित्व एवं संचालन में नेपाल में रेडियो की शुरूआत 1951 में हुई। इससे पूर्व जनता को रेडियो रिसीवर रखने की आज्ञा नहीं थी। किंग महेन्द्र ने नेपाली भाषा का पक्ष

लिया। 1965 में हिन्दी एवं नेपाली भाषा के समाचार प्रसार बन्द कर दिये गए। 1971 में नेशनल कम्यूनिकेशन प्लान बनाई गई। ब्रिटेन, मलेशिया, जापान एवं आस्ट्रेलिया के सहयोग से रेडियो के आधुनिक उपकरण बनाए गए। सरकार ने रेडियो का उपयोग शिक्षा एवं ग्रामीण विकास में प्रारम्भ किया। 1991 में सरकार ने नेपाल फोरम ऑफ इन्वायरमेन्टल जर्नेलिस्ट्स को काठमाण्डु घाटी में संचालन के लिए एफ.एम. रेडियो के लिए लाईसेंस दिया। इसके बाद कान्तिपुर समाचार समूह सहित कई संस्थानों ने रेडियो सेवाओं के विस्तार में योग दिया। रेडियो नेपाल अर्द्ध-स्वयत्तशासी संगठन द्वारा संचालित किया जात है। एफ.एम. स्टेशन संचालन के लिए भी नेपाल सरकार ने समूहों को यह लाइसेंस दिया है।

4.6.2.3 टेलीविजन

नेपाल टेलीविजन कार्पोरेशन ने एन.टी.वी. को प्रारम्भ किया। इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। 1994 में सैटेलाईट टेलीविजन शुरू हुआ। शांग्रेला केबल को काठमाण्डु घाटी में केबल संचालन की आज्ञा दी गई। रेडियो और टेलीविजन पर अप्रत्यक्ष रूप में सरकार का नियंत्रण है । उसे सरकार और सत्ता में बैठे राजनैतिक दल की भाषा बोलनी पड़ती है। इसमे चैनल और दो निजी संस्थान भी टी.वी. सेवाएं देने में संलग्न है। नेपाल टेलीविजन का दावा है कि वह 40 प्रतिशत आबादी को टी.वी. सेवाएं प्रदान करती है। 28 प्रतिशत भू-भाग पर इसकी पहुंच है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण टेलीविजन की पहुँच की अपनी सीमाएं हैं। कम्यूनिकेशन सैटेलाईट द्वारा सम्पूर्ण आबादी को टी.वी. सेवाएं देने के प्रयास जारी है। लेकिन गरीबी के साथ केवल 15 प्रतिशत आबादी को ही विधुत उपलब्धि आदि कई ऐसी समस्याएं है जो टेलीविजन सेवाओं के मार्ग में बाधा है।

4.6.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी

1999 में नेपाल में अनुमानत: इन्टरनेट सेवाओं का उपयोग करने वालों की संख्या 500 थी। इससे सिद्ध होता है कि नई सूचना प्रौद्योगिकी एवं माध्यम अभी नेपाल में नए हैं एवं उनकी पहुंच का दायरा बहुत सीमित है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में निजी निवेशकों की भूमिका के बारे में स्पष्ट नीति का अभाव है। इस कारण विकास की गति अत्यन्त धीमी है। राईटिंग नेपाल, कान्तिपुर काठमाडु पोस्ट एवं कुछ साप्ताहिक ही अभी ऑन-लाईन पर उपलब्ध हैं।

4.6.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति

नेपाल में जनसंचार माध्यमों के समुचित विकास के लिए स्पष्ट नीति के निर्धारण के लिए अभी कोशिश जारी है। नेपाल की प्रेस इंस्टीट्यूट भी समाचारपत्रों, फिल्मों, रेडियो, टेलीविजन एवं नई सूचना प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए एक नीति तय करने पर बल दे रही है। प्रयास यह है कि प्रेस की स्वतन्त्रता को प्रोत्साहन दिया जाए तथा सूचना का अधिकार दिया जाए ताकि जनतन्त्र के विकास को पुख्ता बनाया जा सके। इन्टरनेट, सेस्यूलर टेलीफोन, कम्प्यूटर्स एवं सैटेलाईट कम्यूनिकेशन ने विकास की दिशा में अपना योग देने के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं जिनका विस्तार जरूरी है। इस भावना के साथ पत्रकारिता की शिक्षा के विकास के लिए कदम उठाए गए हैं। 1984 में स्थापित प्रेस इन्सीदयूट भी पत्रकारिता के विकास एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा जनसंचार माध्यमों की जरूरतों कौ पूरा करने का प्रयास कर रही है।

नेपाल में प्रेस, रेडियो, टेलीविजन एवं सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की सकारात्मक प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होने लगी हैं।

4.6.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे

सरकारी माध्यमों के निजीकरण की मांग के लोकप्रिय होने के बावजूद अभी रेडियो और टेलीविजन का स्वामित्व एवं संचालन सरकार के अधीन है। सरकार के नियन्त्रण में दो दैनिक समाचारपत्र भी हैं। सरकार ने समाचारपत्रो को निजी हाथों में देने तथा इलेक्ट्रोनिक माध्यमों में निजी क्षेत्र की भागीदारी का वादा तो किया लेकिन ओर ठोस कदम नहीं उठाए हैं। निजी क्षेत्र में भी समाचारपत्रों के हित व्यवसाय एवं राजनीति से जुड़े हैं। अत: उनकी वे विश्वसनीयता भी कम है। कुछ का झुकाव वहां की कांग्रेस की ओर है तथा कुछ का कम्यूनिस्ट दलों की तरफ। ऐसे में कोई पत्र पूर्णत: स्वतन्त्र नहीं है।

जनसंचार माध्यमों में निवेश बहुत कम हुआ है और आधुनिक टेकनोलॉजी के बीच बहुत पुराने उपकरणों एवं प्रसार के बीच जनसंचार माध्यम झूल रहे हैं। जनसंचार माध्यमों की अपनी कोई आचार संहिता नहीं हैं। पहाड़ी क्षेत्रो के होने तथा शिक्षा का स्तर कम होने के कारण रेडियो के विकास की भारी सम्भावनाएँ है।

Media **Daily Newspapers Nepal**

Name of Newspaper	Language	Location	Circulation
Aparanha	Nepali	Kathmandu	2.000
Aajako Samacharpatra	Nepali	Kathmandu	20,000
Aadarsha Samaj	Nepali	Pokhara	1,500
Blast Times	Nepali	Dharan	2,850
Bhiswabhumi	Nepali	iKathmandu	8,324
Bibechana	Nepali	Jhapa	1.000
Chautari	Nepali	Butwal	1,000
City	TimesNepali	Kathmandu	2,000
Daily News	Nepali	Kathmandu	500
Gorkhapatra	Nepali	Kathmandu	25,000
Hijo Aaja	Nepali	Jhapa	500
Himalaya Times	Nepali	Kathmandu	22,000
Jana Patra	Nepali	Biratnagar	500
Janamat	Nepali	Pokhara	500
Jana Sagharsha	Nepali	Butwal	5,000
Kantipur	Nepali	Kathmandu	30,000
Koseli	Nepali	Biratnagar	500
Kamandar	Nepali	Kathmandu	2,000

Lumbini	Nepali	Butwal	4,000
Mahanagar	Nepali	Kathmandu	5,000
Nepali	Hindi	Kathmandu	500
Nhugu Bhiswabhumi	Newari	Kathmandu	2,000
Prateek	Nepali	Birgunj	2,610
Purbanchal	Nepali	Jhapa	2,000
Sandhya Times	Nepali	Kathmandu	3,000
Sandhyakalin	Nepali	Kathmandu	19,000
The Rising Nepal	English	Kathmandu	10,000
The Kathmandu Post	English	Kathmandu	10,000
The Commoner	English	Kathmandu	3,000
Valley News	Nepali	Kathmandu	8,500

Souorce : Press Council, Nepal, 1999

4.7 पाकिस्तान में जनसंचार माध्यम और नई सूचना-प्रौद्योगिकी

4.7.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

पूर्व में भारत की 2912 किलोमीटर, उत्तर में 523 किलोमीटर चीन की सीमा और पश्चिम में 909 ईरान एवं 2930 कि.मी. अफगानिस्तान की सीमा के बीच स्थित पाकिस्तान 8,03,940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1999 के मध्य पाकिस्तान की आबादी लगभग 138 मिलियन थी। पाकिस्तान की आबादी का लगभग 95 प्रतिशत मुसलमान हैं जिनमें 77 प्रतिशत सुन्नी तथा शेष शिया मुसलमान है। शेष ईसाई, हिन्दू या अन्य धर्मावलम्बी है। यद्यपि उर्दू 8 प्रतिशत लोगों की मातृभाषा है लेकिन पूरे देश में बोली एवं समझी जाती है। 48 प्रतिशत की भाषा पंजाबी, 12 प्रतिशत की सिन्धी, 10 प्रतिशत की सेवाईकी, 8 प्रतिशत की पश्तु, 3 प्रतिशत की बलुची एवं शेष अन्य भाषाएँ बोली जाती हैं। अंग्रेजी सरकारी कामकाज की भाषा है। साक्षरता 41 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिशत कम है। भारत विभाजन के साथ 14 अगस्त, 1947 को पाकिस्तान बना। 1971 तक पाकिस्तान के दो हिस्से थे पूर्व एवं पश्चिम पाकिस्तान।

गृहयुद्ध के बाद पूर्व पाकिस्तान अलग होकर बंगलादेश के रूप में उभरा है।

4.7.2 जनसंचार उद्भव एवं विकास

4.7.2.1 समाचारपत्र

भारत विभाजन के समय जो भाग पाकिस्तान में गया उसमें लाहौर और कराची ही समाचारपत्रों के प्रमुख केन्द्र थे और इन नगरों के प्रकाशक और पत्रकार हिन्दू थे। जो मुसलमान पत्रकार भारत से पाकिस्तान गए वे पत्रकारिता के खालीपन को पूरी तरह नहीं भर सके। दिल्ली में डॉन तथा उर्दू थे। प्रमुख पत्र जंग और अन्जाम कराची चले गए। बंगाली दैनिक आजाद और अंग्रेजी का मोर्निंग न्यूज कलकत्ता से ढाका चले गये। 1953 में मोर्निंग न्यूज़ ने कराची से भी

संस्करण शुरू कर दिया। 'अन्जाम' राजनैतिक उथल-पुथल एवं प्रतिस्पर्द्धा में टिक नहीं पाया। लेकिन डॉन, जंग और नवा-ए-वक्त पाकिस्तान के बड़े समाचारपत्र समूह के रूप में विकसित हुए।

भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के कारण पाकिस्तान में समाचारपत्रों पर अंग्रेजी शासन के समय के कानूनों को बरकरार रखते हुए प्रेस पर और कई पाबन्दियां लागू कर दी। सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान 1952 ने प्रेस सेन्सरशिप का रास्ता खोल दिया। शासन के प्रारम्भिक सात वर्षों में 15 समाचारपत्रों पर पाबन्दी लगा दी। 1947-58 की अवधि में प्रेस स्वतन्त्रता पर रोक के बावजूद पत्र-पत्रिकाओं की संख्या 556 से 1106 हो गई और प्रसार संख्या में भी वृद्धि हुई। 1947 से 1958 तक समाचारपत्रों की प्रसार संख्या 1,25,000 से बढ़कर 7,16,000 हो गई। पाकिस्तान में 1958 एवं 1990 में मार्शल-ला शासन के लागू होने के बावजूद प्रेस की वृद्धि जारी रही। प्रेस की स्वतन्त्रता पर सर्वाधिक शक्तिशाली एवं हानिकारक हमला 1958-85 के अधिनायकवाद शासन में हुआ। प्रेस पर रोक से 1958 में 260 पत्रों की संख्या में कमी होकर 1960 में 64 रह गई। प्रेस एण्ड पब्लिकेशन (एमेन्डमेन्ट) आरडिनेन्स 1964 नामक काला कानून लागू हुआ। 1965 में भारत के साथ युद्ध के समय डिफेन्स ऑफ पाकिस्तान रूल्स (डी.जी.आर.) लगा। बीस साल आपातकाल और यह कानून जारी रहे। 1971 के बाद भुट्टो ने शासन संभाला। पत्रकारों पर अंकुश, गिरफ्तारियों, धमकियों का दबदबा बना रहा। उसके बाद भी समाचारपत्रों पैर जुल्म जारी रहे। 1985 में मार्शल-ला खत्म हुआ। इसके बाद पत्रकारों एवं अन्तर्राष्ट्रीय माध्यम संगठनों के दबाव से पाकिस्तान में जनतन्त्रीय एवं स्वतन्त्र प्रेस का मार्ग धीरे-धीरे प्रशस्त होने लगा।

4.7.2.2 रेडियो

भारत विभाजन के समय पाकिस्तान को लाहौर. ढाका एवं पेशावर के तीन रेडियो स्टेशन मिले। 1948 में कारांची में रेडियो स्टेशन स्थापित हुआ। 1974 में अर्थ सेटेलाईट स्टेशन बना। रेडियो पर सरकार का एकाधिपत्य है। साक्षरता की कमी के कारण रेडियो ही सबसे बड़ा माध्यम है। 1973 में कारपोरेशन बना। इसके अन्तर्गत 22 रेडियो स्टेशन हैं। रेडियो की पहुँच अब संपूर्ण आबादी तक है।

4.7.2.3 टेलीविजन

पाकिस्तान में अक्टूबर, 1963 में जापान की निप्पोन इलेक्ट्रानिक के साथ समझौते के अन्तर्गत दो टेलीविजन स्टेशनों का इस कम्पनी ने संचालन शुरू किया। इनमें लाहौर में 1964 में एक स्टेशन ने प्रसारण प्रारम्भ किया। टेलीविजन प्रमोटर्स बनी जो बाद में सरकारी संरक्षण में चली गई। पाकिस्तान के टेलीविजन ने कराची, रावलपिंडी एवं इस्लामाबाद के केन्द्र स्थापित किए। 1992 में जापान के सहयोग से पी.टी.वी-2 चैनल आरम्भ किया। शालीमार रिकार्डिंग को सरकार ने अधिकृत किया जिसने 10 प्रसारण केन्द्र प्रारम्भ किए। पाकिस्तान टेलीविजन कारपोरेशन का समाचार ब्यूरो, समाचार पी.टी.वी. एवं इसके क्षेत्रीय समाचार केन्द्रों के लिए समाचार बुलेटिन तैयार करता है। पी.टी.वी.-1 एवं पी.टी.वी-2 के 56 प्रतिशत कार्यक्रम मनोरंजन, 16 प्रतिशत समाचारों, 10 प्रतिशत शिक्षा एवं 8 प्रतिशत संस्कृति एवं धर्म से सम्बन्धित होते हैं।

4.7.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी

पाकिस्तान में कम्प्यूटर का उपयोग करने वालों के पास इन्टरनेट सेवाएं जुलाई, 1995 में पहुंचने लगी। 1996 में 6,00,000 कम्प्यूटर थे तथा इन्टरनेट का प्रयोग करने वालो की संख्या 4,000 थी। यह संख्या 1999 में बढ़कर 10,000 हो गई। कई समाचारपत्र इन्टरनेट पर उपलब्ध है। जंग, नवा-ए-वक्त, डॉन, दी नेशन आदि पत्रों की सेवाएं शामिल है। रेडियो पाकिस्तान की सेवाएं पी.वी.सी. वेब साईट पर उपलब्ध है तथा पी.टी.वी. की भी अपनी वेवसाईट है।

पाकिस्तान टेली कम्यूनिकेशन ऑथोरिटी (पी.टी.ए.) ने इलेक्ट्रानिक सेवाओं पर कई पाबन्दियों लगा रखी है। इन्टरनेट के उपभोक्ताओं को उनकी इलेक्ट्रॉनिक कम्यूनिकेशन के सरकार द्वारा मोनिटरिंग के लिए सहमत होना पड़ता है। इन्टरनेट द्वारा ध्वनि प्रसारण पर रोक है।

4.7.4 समाचारपत्रों के संदर्भ में नीति

पाकिस्तान में सरकार एवं विभिन्न माध्यमों के बीच सम्बन्ध परिवर्तन के दौर में है। प्रेस को अधिक स्वतन्त्रता देने तथा सरकारों हस्तक्षेप से इलेक्ट्रानिक माध्यमों को मुक्त करने की दिशा में निरन्तर दबाव बढ़ रहा है। प्रेस की स्वतन्त्रता के सन्दर्भ में अपेक्षाएं बढ़ रही है। 'फ्रीडम हाऊस' सर्वेक्षण के अनुसार प्रेस की आजादी पर पाबन्दियों के बावजूद पाकिस्तान की प्रेस दक्षिण एशिया की प्रेस में खुलकर बोलने की आदत की शिकार है। इस सर्वेक्षण ने पाकिस्तान में प्रेस की आंशिक स्वतन्त्रता मानी है। पाकिस्तान मैं प्रेस एवं सूचना माध्यमों की आवाज को दबाने एवं सरकार द्वारा अपने नियन्त्रण का शिकंजा दृढ़ रखने की प्रवृत्ति भी अन्य देशों के मुकाबले अधिक मानी गई है।

4.7.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे

यद्यपि 1985 के बाद पाकिस्तान में प्रेस की आजादी में कुछ सुधार आया है लेकिन मौलिक स्वतन्त्रता के अधिकारों के साथ जनसंचार माध्यमों को संस्थागत स्वरूप प्राप्त होना आज भी बाकी है। प्रेस और राजनैतिक स्तर पर डराने, धमकाने का सिलसिला तथा अधिकारियो एवं शक्तिशाली वर्गों के दबाव पर कोई अंकुश नहीं है। 'जंग' जैसे सबसे बड़े पाकिस्तानी समाचार समूह को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रेस कौंसिल की स्थापना एवं पत्रकारों की आचरण संहिता का निर्माण बाकी है। कुल पाकिस्तान में प्रेस के स्वस्थ विकास एवं स्वतन्त्र माहौल की संरचना अभी आधी अधूरी है।

बोध प्रश्न-3

1. नेपाल में रेडियो और टेलीविजन की स्थिति पर प्रकाश डालिए।
2. नेपाल की नई सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी दीजिए।
3. पाकिस्तान में प्रेस की स्वतन्त्रता के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए।
4. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-
    1. पी.टी.वी.
    2. पाकिस्तान की नई सूचना प्रौद्योगिकी
    3. एन.टी.वी.

	Numbers (000)	Per100 People	Number (000)	Per100 People	Number	Cire'n	Per100 People
1980	5.500	6.4	938	1.1	106	1,032	1.2
1985	8,500	8.4	1,304	1.3	118	1.149	1.1
1990	10,650	839	1,989	1.7	398	1,989	1.7
1995	12,500	9.2	2,680	2.0	2232,800	2.1	
1996	12,900	9.2	3,000	2.1	264	-	-
			(7,600)*	(5.7)*			
1997	13,500	9.4	3,100	2.2	271**	1,499**	1.1**
1998	-	-	(8.8) *	303*		-	-

Source: UNESCO, 1999.*ITU,** WAN 1998, 1999.

Newspaper Groups

The Jang Group

PO Box 52
Chundrigar Road
Karachi

The Dawn Group

Haroon House
Dr. Ziauddin Ahmed Road,
Karachi

Media Associations

The all Pakistan Newspaper Editors

3rd Floor, 32 Farid Chabers
Abdullah Haroon Road,
Karachi

The Council of Pakistan Newspaper Editors

1 Victoria Chambers
Abdullah Haroon Road,
Karachi

The Pakistan Federal Union of Jounalists

Karachi Press Club

Sarwar Shaheed Road,

Karachi

News Agencies

Pakistan Press international (PPL)

Press Centre

Shahrah Kamal Ataturk

Karachi

Associated Press of Pakistan (APP)

18-Mauve Area, G-7/1

Islamabad

Press Foundations

The Pakistan Press Foundation

Press Centre

Shahrah kamal Ataurk

Karachi

4.8 श्रीलंका में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी

4.8.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

श्रीलंका 65,610 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भारत के दक्षिण में स्थित है। यहां की आबादी 19 मिलियन है। इनमें 74 प्रतिशत सिन्हाली, 12 प्रतिशत श्रीलंकन तमिल, 6 प्रतिशत भारतीय तमिल एवं अन्य समूह निवास करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्वाधिक 69 प्रतिशत बौद्ध, 15 प्रतिशत हिन्दू 8 प्रतिशत ईसाई एवं 8 प्रतिशत मुसलमान धर्म के मानने वाले हैं। सिन्हाली और तमिल राष्ट्रीय भाषा है। अंग्रेजी का सरकारी कामकाज में उपयोग होता है। अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या लगभग 10 प्रतिशत है। साक्षरता 90 प्रतिशत है।

श्रीलंका भी अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन था। 4 फरवरी, 1948 को इस देश कौ आजादी मिली। 1972 में गणतन्त्र की स्थापना हुई। एल.टी.टीई. के अलगाववादी आंदोलन से श्रीलंका की सामाजिक और राजनैतिक जीवन कठिनाइयों के दौर में है।

4.8.2 जनसंचार. उद्भव एवं विकास

4.8.2.1 समाचारपत्र

श्रीलंका में डच लोंगों ने 1737 में छापाखाना लगाया। अंग्रेजी शासन में भी कई समाचारपत्रों का प्रकाशन होता था। आजादी के समय देश के समाचारपत्रों पर दो निजी समूह एसोसिएटेड न्यूज पेपर्स ऑफ सिलोवेज था। 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' का आधिपत्य था। ए.एन.सी.एल. द्वारा सिन्हाली, अंग्रेजी एवं तमिल भाषा के तीन प्रमुख समाचारपत्रों का प्रकाशन' किया जाता है। 1846 में प्रारम्भ टाइम्स ऑफ सिलोन लि. प्रकाशन का सिलोन टाइम्स भी प्रमुख

पत्र था। यह पत्र 1985 में बन्द हो गया। 20वी सदी के अन्त में इस देश के समाचार जगत पर ए.एन.एस.एस. उपाली न्यूज पेपर्स लि. एवं विलया न्यूज पेपर्स लि. निजी समाचारपत्रों के समूह का प्रभुत्व था। 1971 में आपातकाल लागू किया गया। इसके बाद 1982-83 में आपातकाल को दोहराया गया और आपातकालीन सरकारी शक्तियां ही सरकार के लिए नियम बन गए। एल.टी.टी.ई. द्वारा जारी जातीय संघर्ष ने सरकार के आपातकालीन नियमों को न्यायोचित ठहराया। इस प्रकार आजादी के बाद भी प्रेस को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में श्रीलंका में एक गुणात्मक प्रेस के विकास में अनेक बाधाएं आई।

4.8.2.2 रेडियो

डार्वनर के भाषण के प्रसारण हेतु रेडियो की शुरूआत 1924 में हुई। ब्रिटिश शासन काल से शुरू होकर 1980 तक रेडियो पर सरकार का एकाधिकार रहा। 1945 में श्रीलंका का रेडियो शक्तिशाली प्रसारण से युक्त था। 1950 में व्यावसायिक सेवा का भी प्रारम्भ किया गया। सरकार द्वारा संचालित श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कार्पोरेशन (एस.एल.बी.सी.) का रेडियो पर एकाधिकार है। सिन्हाली, तमिल एवं अंग्रेजी में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। 1984 में सरकार द्वारा रेडियो सेवाओं में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई गई। इससे 11 निजी क्षेत्र कम्पनियां इस क्षेत्र में आई। विदेश प्रसारणों में 60 प्रतिशत कार्यक्रम हिन्दी में प्रसारित किए जाते हैं।

4.8.2.3 टेलिविजन

श्रीलंका में टेलिविजन पर सरकार का नियंत्रण था। टेलीविजन का प्रारम्भ 1979 में हुआ। दो निजी उधमियों ने स्वतन्त्र टेलीविजन नेटवर्क की स्थापना की। दो माह बाद सरकार ने इसे अधिगृहीत कर लिया। श्रीलंका रूपवाहिनी कापोरेशन की 1882 में सरकार ने स्थापना की। 1983 में शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण होने लगा। 1992 मे सरकार ने अपने एकाधिकार में ढील दी। इससे एम.टी.वी., ई.टी.वी. आदि निजी कम्पनियों के चैनल शुरू हुए।

4.4.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी

1994 में मोरातोवा विश्वविद्यालय में इन्टरनेट सेवा प्रारम्भ की गई। व्यावसायिक इन्टरनेट सेवाओं की 1995 से व्यवस्था की गई। मोरातोआ विश्वविद्यालय में सरकार ने लन्कन एक्सपेरिमेन्टल एकेडेमिक एण्ड रिसर्च नेटवर्क (लर्न) स्थापित करने में सहयोग दिया। यह देश में विस्तृत नेटवर्क तैयार करने में सफल रहा। 1997 में इंटरनेट सेवाओं के 9045 उपभोक्ता थे।

4.4.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति

पीपल्स एलायन्स ने 1994 में यू।एन.पी. सरकार को हरा दिया। एलान्स ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में माध्यमों की स्वतन्त्रता का वादा किया था लेकिन नकारात्मक प्रवृत्तियां जारी रही। पत्रकार संगठनों की बराबर प्रेस स्वतन्त्रता की माग उठती रही। आपातकालीन अधिकारों का सरकार फायदा उठाती रहीं। कोई भी राजनैतिक दल सत्ता में हो वर्तमान कानूनों के तहत जब तक कोई कारगर नीति तय नहीं हो, प्रेस की आजादी पर अंकुश जारी रहेगा।

4.4.5 प्रैस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे

श्रीलंका नई संवैधानिक पीर भाषा की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक कानून बनाना भी जरूर है। माध्यमों के लिए प्रैस कोन्सिल कानून एवं प्रैस की स्वतन्त्रता को पुष्ट करने के लिए माध्यमों के सुधार की एकजुट कोशिश करने की जरूरत है।

Advertising Share of Radio Broadcasters

Media	1955 (USS 4 million) percent	1966 (USS 6 million) percent	1997 (USS 7.6 million) percent
MBC (Maharaja	58	59	51
SLBC	34	24	17
FM99/CCL	3	10	23
TNL	5	7	4
Lakhanda	-	-	5

Source: Phoenix Advertising, 1998 Rajapakse, 1997

Advertising Share of TV Stations

	1955 (USS 10.4 million) percent	1966 (USS 11.7 million) percent	1997 (USS 16 million) percent
SLRC	42	44	34
INT	24	21	17
MTB	18	21	23
TNL	7	7	6
ETV/Swarnavahini	5	4	14
ETV	4	4	3
Dyanvision	-	-	-

Source: Phoenix advertising, 1998 Rajapakse, 1997

Newspaper published in Colombo (population 1.2 million)

Group	Title	Established	Frequency	Language	Circulation (E&P)	Circulation (WPT)
ANCL	Dinamina	1909	Daily a.m	Sinhala	140,000	55,000
	Janata	1953	Daily p.m	Sinhala	15,000	5,000
	Silumania	1930	Sunday	Sinhala	254,000	285,000
	Thinakaran	1932	Daily a.m	Tamil	18,500	29,000
	Thinakaran					

	Varamanjari	1948	Sunday	Tamil	22,000	45,024
	Daily News	1918	Daily	a.m	English	85,000
	Observer	1834	Daily	p.m	English	14,000
	Sunday					
	Observer	1923	Sunday	English	120,000	118,000
Wijeya	Lankadipa	1947/1991	Daily a.m	Sinhala	-	134,000
	Irida					
	Lankadipa	1951/1986	Sunday	Sinhala	259,000	275,000
	Midweek					
	Mirror	1961/1995	Wednesday	English	-	N/A
	Sunday	1926/1987	Sunday	English	-	125,000
	Times					
Upali	Divaina	1982	Daily a.m	Sinhala	100.00	130.000
	Divaina					
	Irida					
	Sangrahaya	1981	Sunday	Sinhala	-	252,144
	The Island	1982	Daily a.m	English	33,000	47,000
	Sunday	1981	Sunday	English	87,000	79,443
	Island					
Express	Virakesari	1930	Daily a.m	Tamil	48,000	30,000
	Virakesari					
	Vara					
	Veliyeedu	1930	Sunday	Tamil	-	84,500
	Weekend					
	Express	1995	Saturday	English	-	N/A
Independt	Sunday	1994	Sunday	English	-	75,00
	Leader					
	Lakbima	1994	Sunday	Sinhala	-	136,000
	Thinakkural	1997	Daily a.m	Tami	N/A	
	Peramuna	1998	Sunday	Sinhala	-	N/A

Source: Editor & publisher intenational tear book, 1999; WAN, 1999; Peris, 1997

4.9 सारांश

'दक्षिण एशिया में जनसंचार' इकाई अन्तर्गत बांगलादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका मे जनसंचार माध्यमों (समाचारपत्र, रेडियो और टेलीविजन) की दशा तथा दिशा की विवेचना की गई है।

बंगला देश में प्रेस की स्वतन्त्रता आंशिक है। प्रेस की स्वतन्त्रता जैसे मुद्दे आज भी वहां उलझे हुए हैं। भूटान में इंटरनेट सेवाएं जून, 1999 से प्रारम्भ हुई है। घरेलू टेलीविजन सेवाओं का भी प्रारम्भ जून, 1999 से हुआ है।

भारत में जनसंचार माध्यमों के प्रचार-प्रसार की स्थिति विकास की ओर है। सूचना प्रौद्योगिकी में तेजी से परिवर्तन आए हैं। 1997 में रेडियो और दूरदर्शन को स्वायतता देने के लिए 'प्रसार भारती' की स्थापना की गई है। प्रैस परिषद भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भाषाई पत्र-पत्रिकाओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। मुद्रण की नई तकनीक एवं संचार क्रांति ने समाचारपत्रों के विकास एक विस्तार में विशेष योगदान दिया है।

मालदीव में जनसंचार माध्यमों की स्थिति संतोषप्रद नहीं है। नेपाल में जनसंचार माध्यमों पर सरकार का अंकुश है। पाकिस्तान में प्रेस पर नियंत्रण है। स्वस्थ विकास एवं स्वतन्त्र माहौल की संरचना आधी-अधूरी है।

4.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. मीडिया मोनिटर इन बंगलादेश-एम.टी. अनवर (1996)
2. बंगलादेश प्रेस कान्सिल (1964)
3. मासमीडिया एण्ड नेशनल डेवलपमेन्ट: ए केस स्टडी ऑफ बंगलादेश-जे.पी. दत्ता
4. बंगलादेश चेन्जेज एमिडस्ट ग्रोथ-एन हुड़ा
5. दी डायलेमाज ऑफ स्मॉल स्टेट-जे. ब्रेय
6. इन्ट्रोडक्शन ऑफ भूटान-एफ. पोमारेट, दी गाईड बुक कम्पनी, हांगकांग
7. स्टेटेस्टिकल ईयर बुक, यूनेस्को, पैरिस
8. प्रेस एण्ड दी क्रासरोड्स इन इंडिया-एस के अग्रवाल, उच्च प्रकाशन, दिल्ली
9. टेलीविजन एण्ड दी पब्लिक इन्टरेस्ट-जे.जी. ब्लूमर, सेज प्रकाशन, दिल्ली
10. वर्ल्ड फेक्ट बुक (1999), वाशिंगटन
11. प्रेस एण्ड डेमोक्रेसी इन इण्डिया: एन कौशल
12. खान् ए. डब्ल्यू. एण्ड बाकर: एप्रोडियेट मीडिया फॉर स्माल स्केल डिसटेन्स एज्यूकेशन सिस्टम्स, मीडिया एशिया
13. फ्रीडम हाऊस सर्वे (1996)
14. यूरोपीयन वर्ल्ड ईयर बुक (1999)
15. एम. अहमद: टेलीविजन मालदीव
16. डी. एच. अधिकारी, मीडिया मोनिटर्स, इन नेपाल, एशिया, सिंगापुर
17. नेशनल मास मीडिया डाईरेक्टरी, प्रेस कौन्सिल, काठमांडु
18. बी. कोईराला-कम्यूनिकेशन सीन: नेपाल
19. क्यू. ए. अली-ट्रायल बाई फायर एण्ड फायर आर्म-सी.पी.यू. न्यूज़
20. अल्मुजाहिर-प्रेस सिस्टम इन पाकिस्तान-मीडिया एशिया
21. वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूजपेपर्स-1999, वर्ल्ड प्रैस ट्रेंड्स, पेरिस
22. दी टर्मिंग ऑफ प्रेस इन श्रीलंका-एस.ए. गुनारत्ने, जर्नेलिज्म मोनोग्राम्स

23. एन.डी. उद्‌गामा (1996)-फ्रीडम ऑफ प्रेस इन श्रीलंका, यूनिवर्सिटी ऑफ केलिफोर्नियां डिजरटेशन।

4.11 निबन्धात्मक प्रश्न

1. 'दक्षिणी एशिया' के जनसंचार माध्यमों की दशा-दिशा पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए।
2. 'बंगलादेश में प्रेस की स्वतन्त्रता आंशिक है।' इस कथन की विवेचना कीजिए।
3. 'भूटान में राजशाही तंत्र ने जनसंचार माध्यमों के प्रचार-प्रसार में कोई विशेष रुचि नहीं ली।' इस कथन को दृष्टिगत रखते हुए भूटान में मीडिया की समीक्षा कीजिए।
4. 'भारत में प्रेस की स्वतन्त्रता' पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए।
5. भारत की नई सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में विस्तार से प्रकाश डालिए।
6. श्रीलंका के जनसंचार माध्यमों पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए।
7. 'पाकिस्तान में प्रेस की स्वतन्त्रता नाम के बराबर है।' क्या आप इस कथन से सहमत हैं?
8. मालदीव में जनसंचार माध्यमों के उद्भव एवं विकास पर एक निबंध लिखिए।

इकाई 5 एशिया में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी-2 (दक्षिणी पूर्वी एशिया) Media in Asia-2 (South East Asia)

इकाई की रूपरेखा

5.0 उद्देश्य

5.1 प्रस्तावना

5.2 ब्रु नेई दारूसलम में जनसंचार और नई सूचना-प्रोद्योगिकी

5.2.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

5.2.2 जनसंचार: उद्भव एवं विकास

5.2.2.1 समाचारपत्र

5.2.2.2 रेडियो

5.2.2.3 टेलिविजन

5.2.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी

5.2.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति

5.2.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे

5.3 कम्बोडिया में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी

5.3.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

5.3.2 जनसंचार: उद्भव एवं विकास

5.3.2.1 समाचारपत्र

5.3.2.2 रेडियो

5.3.2.3 टेलिविजन

5.33 नई सूचना प्रौद्योगिकी

5.3.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति

5.3.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे

5.4 इण्डोनेशिया में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी

5.4.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

5.4.2 जनसंचार: उद्भव एवं विकास

5.4.2.1 समाचारपत्र

5.4.2.2 रेडियो

5.4.2.3 टेलिविजन

5.4.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी

5.4.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति

5.5.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे

5.5 लाओस में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी

5.5.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

5.5.2 जनसंचार: उदभव एवं विकास
5.5.2.1 समाचारपत्र
5.5.2.2 रेडियो
5.5.2.3 टेलिविजन
5.5.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी
5.5.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति
5.5.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे
5.6 मलेशिया में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी
5.6.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य
5.6.2 जनसंचार: उद्भव एवं विकास
5.6.2.1 समाचारपत्र
5.6.2.2 रेडियो
5.6.2.3 टेलीविजन
5.6.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी
5.6.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति
5.6.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे
5.7 म्यांमार में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी
5.7.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य
5.7.2 जनसंचार: उद्भव एवं विकास
5.7.2.1 समाचारपत्र
5.7.2.2 रेडियो
5.7.2.3 टेलीविजन
5.7.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी
5.7.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति
5.7.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे
5.8 फिलिपिन्स में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी
5.8.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य
5.8.2 जनसंचार उद्भव एवं विकास
5.8.2.1 समाचारपत्र
5.8.2.2 रेडियो
5.8.2.3 टेलीविजन
5.8.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी
5.8.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति
5.8.5 प्रैस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे
5.9 सिंगापूर में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी
5.9.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य
5.9.2 जनसंचार उद्भव एवं विकास

5.9.2.1 समाचारपत्र
5.9.2.2 रेडियो
5.9.2.3 टेलीविजन
5.9.3 नई सूचना प्रौद्यौगिकी
5.9.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति
5.9.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे
5.10 थाईलेण्ड में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी
5.10.1 राष्ट्रीय पारप्रेक्ष्य
5.10.2 जनसंचार: उद्भव एवं विकास
5.10.2.1 समाचारपत्र
5.10.2.2 रेडियो
5.10.2.3 टेलिविजन
5.10.3 नई सूचना-प्रौद्योगिकी
5.10.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति
5.10.5 प्रैस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे
5.11 वियतनाम में जनसंचार और नई सूचना प्रोद्योगिकी
5.11.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य
5.11.2 जनसंचार उद्भव एवं विकास
5.11.2.1 समाचारपत्र
5.11.2.2 रेडियो
5.11.2.3 टेलीविजन
5.11.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी
5.11.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति
5.11.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे
5.12 सारांश
5.13 कुछ उपयोगी पुस्तकें
5.14 निबन्धात्मक प्रश्न

5.0 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई में दक्षिण पूर्वी एशिया के दस देशों-1 ब्रुनेई दारूस्लम, 2, कम्बोडिया, 3 इण्डानेशिया, 4 लाओस, 5 मलेशिया, 6 म्यांमार, 7 फिलिपिन्स, 8 सिंगापुर, 9 थाईलैण्ड तथा 10 वियतनाम के जनसंचार माध्यमों सरकार की नीति, नई सूचना प्रौद्योगिकी पर प्रामाणिक जानकारी दी गई है।

- इस इकाई में दक्षिण पूर्वी एशिया के दस देशों के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, राजनैतिक व्यवस्था, जनसंचार है उदभव एवं विकास से आप परिचित हो सकेंगे।
- इकाई अध्ययन के बाद आप दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में समाचारपत्रों, रेडियो, टेलीविजन आदि विविध जनसंचार माध्यमों की दशा और दिशा से भी परिचित हो सकेंगे।

- आप यह भी बता सकेंगे कि नई जनसंचार प्रौद्योगिकी के विकास के सन्दर्भ में इन देशों ने क्या प्रगति की है।
- जनसंचार माध्यमों के प्रति दक्षिण पूर्वी देशों में सरकार की नीति क्या रही है और संचार माध्यमों की कितनी स्वतन्त्रता है? इस पक्ष को उजागर करने में भी सक्षम हो सकेंगे।

5.1 प्रस्तावना

एशिया महाद्वीप में जनसंचार माध्यमों के विकास, स्वतन्त्रता और आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों से इन माध्यमों का सम्पूर्ण विश्लेषण करने के लिए एशिया महाद्वीप के जनसंचार माध्यमों का तीन खण्डों में आप अध्ययन करके सम्पूर्ण परिदृश्य का विवेचन कर सकेंगे। इसके लिए इकाई-4 में दक्षिण एशिया के सात देशों -बंगलादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के जनसंचार माध्यमों के उतार-चढ़ाव, स्थिति एवं भावी विकास की सम्भावनाओं और समस्याओं से आप अच्छी तरह परिचित हो चुके हैं।

इस इकाई में दक्षिण पूर्वी एशिया के दस देशों में जनसंचार माध्यमों के उद्भव विकास और भावी सम्भावनाओं का अध्ययन कर आप जनसंचार माध्यमों की समस्याओं और नई सूचना प्रौद्योगिकी की पीरवर्तनकारी स्थितियों के संकेत देने में सक्षम होंगे। इकाई-6 पूर्वी एशिया के आठ देशों के जनसंचार माध्यमों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप सम्पूर्ण एशिया के जनसंचार माध्यमों के बारे में चर्चा करने में सफल होंगे।

5.2 ब्रुनेई दारूस्लम में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी

5.2.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

ब्रुनेई दारूस्लम का अर्थ है-ब्रुनेई:शान्ति का आवास। 5,765 कि.मी. में फैला यह एक छोटा-सा देश है। देश में चार जिले है और बन्दरसेरी बेगावान इसकी राजधानी है। कुल भू-भाग का 85 प्रतिशत जंगलों से घिरा है। बहुत तापमान और वर्षा के कारण मौसम मैं बहुत कम विविधता है। 1999 में यहां की जनसख्या 3,22,982 आंकी गई थी। 20 प्रतिशत साक्षरता है। 63 प्रतिशत मुसलमानों, 14 प्रतिशत बौद्धों एवं 8 प्रतिशत ईसाइयों का यहां वास है। ईसा पूर्व 414 में यहां हिन्दू-बौद्धों का राज्य था। मोहम्मद शाह 14वीं सदी में सुल्तान बना। 1906 में अंग्रेजों ने सुल्तान के सलाहकार के रूप में शासन-संचालन शुरू किया। यहां मलार इस्लामिक राजशाही शासन है। कानून का आधा इस्लामी कानून है।

5.2.2 जनसंचार: उद्भव एवं विकास

5.2.2.1 समाचारपत्र

दारूस्लम में समाचारपत्रों का आरम्भ 1948 में ब्रिटिश रेसिडेंट द्वारा अपने स्तर पर प्रकाशित न्यूजलेटर से हुआ। 1952 में ब्रिटिश पेट्रोलियम कम्पनी ने अंग्रेजों एवं मलय भाषाओं में 'सालम' (शान्ति) पहला समाचारपत्र प्रकाशित किया। 'बोर्नियो बुलेटिन' देश का दूसरा समाचारपत्र 1953 में शुरू हुआ।

अंग्रेजी भाषा में निकलने वाला यह एकमात्र समाचारपत्र है जो 1990 से 'ऑन लाईन' पर उपलब्ध है। पेलिवा ब्रुनेई (टार्च ऑफ ब्रुनेई) तीसरा समाचारपत्र 1956 में मलार भाषा में शुरू

हुआ। यह सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जो निःशुल्क सरकारी कर्मचारियों को वितरित किया जाता है। बितांग हेरियन (डेलीस्टार) 1966 में अंग्रेजी एवं मलय में प्रारम्भ हुआ। तीन चीनी भाषा के पत्र निकले और बन्द हो गए। 1960 के दशक में लगभग 6000 विदेशी पत्र-पत्रिकाएं उपलब्ध थीं। देश की जनसंख्या के कम होने से समाचारपत्रों को विज्ञापन सहयोग नहीं मिल पाता था। सरकार ने अंग्रेजी में ब्रुनेई. दारूस्लम डेली डाइजेस्ट 1990 में प्रकाशित करना प्रारम्भ किया। मीडिया पर्माटा (ज्वैल ऑफ मीडिया) 1998 में दूसरा महत्वपूर्ण दैनिक बना जो बोर्नियो बुलेटिन से ऑन लाईन जुड़ा हुआ है। स्थानीय स्तर पर समाज में. समाचारपत्रों के प्रति रुझान की कमी और सामाजिक ढांचे के कारण समाचारपत्रों का अधिक विकास नहीं पाया।

5.2.2.2 रेडियो

रेडियो ब्रुनेई 1957 में आरम्भ हुआ। अंग्रेजी एवं मलय भाषाओं में प्रसारण शुरू हुए। बाद में चीनी एवं घुड़साली भाषाओं के कार्यक्रम भी शामिल किए गए। रेडियो सेवा सरकार के अधीन है जिसके चार अलग-अलग अनुभाग हैं ।

5.2.2.3 टेलीविजन

टेलीविजन का ब्रुनेई में 1975 में प्रसारण शुरू हुआ। डिपार्टमेन्ट ऑफ रेडियो टेलीविजन के अधीन संचालित है। आधुनिकतम उपकरणों के साथ बहुत कम समय में रंगीन टी.वी. प्रसारण भी चालू कर दिए गए। आर्थिक विकास के लिए तैयार पंचवर्षीय योजना का टी.वी. एक हिस्सा था। ब्रुनेई में मलेशिया के टी.वी. चैनलों एवं स्टार चैनलों की भी पहुँच है। रेडियो टेलीविजन ब्रुनेई अपने कार्यक्रमों के प्रसारण में कानून से सम्बन्धित विभाग के मंत्री के प्रति उत्तरदायी है और उसकी इच्छा पर सारा प्रसारण कार्यक्रम निर्भर करता है।

5.2.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी

ग्लोबल इन्फोरमेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर थाने विश्व के सूचनागत ढांचे में अपने आपको जोड़ने तथा मल्टीमीडिया क्षमता का विकास करने की दिशा में ब्रूनेई ने 1996 में एक पंचवर्षीय योजना तैयार की। निजी क्षेत्र से सहयोग लेने का भी इस योजना में प्रावधान किया गया। योजना के अन्तर्गत मल्टीमीडिया उच्च गति प्रसारण सेवाओं, फाईबर आस्टिक एकसस नेटवर्क आदि के विकास के प्रयत्न शामिल है। ब्रुनेट नामक ऑन लाईन प्रणाली की 1995 में स्थापना की गई थी। बोर्नियो बुलेटिन ऑन लाईन पर है। हर 100 व्यक्तियों के बीच एक कम्प्यूटर है।

5.2.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति

ब्रुनेई के संचार माध्यमों को देश के कानूनों, राजनैतिक दबाव और नियन्त्रण के बीच काम करना पड़ता है। निजी संचार माध्यमों के राजनैतिक एवं आर्थिक मसलों पर सेल्फ सेन्सरशिप रखनी पड़ती है। मलेशिया के टी.वी. चैनल एवं स्टार टी.वी. आदि कै सैटेलाईट पर उपलब्ध होने के कारण ब्रुनेई समाज में चेतना का प्रस्फुटन हुआ है और वे बाहरी सेवाएं एवं सब्सीडाईज्ड हाऊसिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं और राजनैतिक विरोध एवं असंतोष का कोई स्थान नहीं है। लेकिन ब्रुनेई समाज समिति जनतान्त्रिक व्यवस्था के लिए कशमकश में है। मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण वर्तमान व्यवस्था जारी है।

5.2.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे

प्रेस की स्वतन्त्रता के सन्दर्भ में ब्रुनेई को इस वर्ग में रखा गया है जहां प्रेस स्वतन्त्रता नहीं है। ब्रुनेई में पत्रकारिता का एक व्यवसाय (प्रोफेशन) के रूप में विकास नहीं हो पाया है। अध्ययनकर्त्ताओं का मानना है कि जनसंचार माध्यमों का विकास तभी सम्भव होगा जब सरकार स्वतन्त्र निजी माध्यमों को विकसित होने के लिए प्रोत्साहन देगी। अन्यथा ब्रुनेई की युवाशक्ति का पत्रकारिता के अध्ययन में रुझान नहीं हो पाएगा।

मीडिया

Newspapers 1952-98 Brunei

Newspaper	**YearPublished**	**Period of Circulation**
Salam	1952	1952
Bruner Bulletin	1953	1953
Pelita Brunei	1956	1956
Berita Brunei/Berita Borneo	1957	1957-58
Malaysia	1958	1958-58
Suara Bakti	19611	961-61
Daily Star/Bintang Harian	1966	1966-71
Brunei Darussalam Newsletter	1985	1985-
Brunei Darusslam Daily Digest	1990	1990-
Media Permata	1994	1994-

Source: Brunei, 1952, 1953, 1956, 1957, 1958m 1975/1980, 1995a, 1996/1997,

Local Radio and Television Service: 1957-98

Newspaper	Year Published	Period of circulation
Network	Year of operation	Network owenership
Radio Brunei (radio service)	1957 until 1996 (restructurd)	The Department of Brodcasting Brunei
TelevisionBrunei (television sevice)	1975	The Department of Radio Television Brunei
National Network (radio service)	1996-	The Department of Radio Television Brunei
Pelangi Network (radio service)	1996-	The Department of Radio Television Brunei

Harmony Network (radio service)	1996-	The Department of Radio Television Brunei
Optional Network (radio service)	1996-	The Department of Radio
Nur Islam Network (radio service)	1997-	The Department of Radio The Department of Radio Television Brunei

Source: Brunei, 1975/1976, 1984/1985, 1996/1997.

5.3 कम्बोडिया में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी

5.3.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

कम्बोडिया के पश्चिम एवं उत्तर-पश्चिम में थाईलैण्ड, उत्तर में लाओस तथा दक्षिण पूर्व में वियतनाम स्थित है। इसकी दक्षिण-पश्चिम सीमा थाईलैण्ड की खाड़ी के किनारे में लगी है। भू-भाग मैदानी एवं वनों से मुक्त है। शुष्क जलवायु है। आबादी 1999 के अनुमानों से 11.63 मिलियन है। साक्षरता 67 प्रतिशत है। ऐसा माना जाता है। कि प्राचीन काल में चीनी, भारतीय और दक्षिण एशियाई द्वीपों के लोग यहां आकर बसे। हिन्दु एवं बौद्ध धर्म का प्रभाव रहा। यहां बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या 95 प्रतिशत है। सदियों से वियनामी और चीनी यहां बसे हुए है। यद्यपि वियतनामी 5 प्रतिशत और चीनी एक प्रतिशत हैं।

5.3.2 जनसंचार : उद्भव एवं विकास

5.3.2.1 समाचारपत्र

किसी भी स्थानीय भाषा के समाचारपत्र से पूर्व कम्बोडिया में फ्रेंच और वियतनामी भाषा के प्रकाशन अस्तित्व में थे। स्थानीय भाषा 'खमेर' में पहला पत्र 'नागखत्ता' का प्रकाशन 1936 में होने लगा। 1942 में इस पत्र के सम्पादक को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरा खमेर भाषा का पत्र 'कम्पूचिया सोरिया' (कम्बोडियन सन) था जिसका संचालन फ्रेन्च आर्थिक सहयोग से एक बौद्ध संस्था करती थी। इसमें साहित्यिक एवं धार्मिक सामग्री छपती थी।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद राष्ट्रीय एसेम्बली की स्थापना के बाद में 'स्वतन्त्रता' तथा रिनोनेशन खमेर पार्टी ने "खैमेरा पत्रों का 194, में प्रकाशन आरम्भ किया। कम्बोडिया की आजादी के बाद समाचारपत्रों का विकास होने लगा लेकिन 1955 का चुनाव स पूर्व. समाचारपत्रों पर रोक लगा दी गई। 1956 में फिर प्रेस का स्वतन्त्रता दी गई। उस समय कुल 16 समाचारपत्रों में तीन दैनिक थे।

1967 में कम्बोडिया में 13 दैनिक पत्र थे जो खमेर, चीनी, फ्रेंच एवं वियतनामी भाषाओं में प्रकाशित होते थे तथा इनकी सयुक्त प्रसार संख्या 70 हजार थी। राजनैतिक उतार चढ़ावों के बीच प्रेस की आजादी घटती-बढ़ती रही। 1973 में सरकार ने आपातकाल लागू किया। सारे निजी पत्रों पर पाबंदी लगा दी गई। सरकारों के फेरबदल की शृंखला में साम्यवादी शासन में साम्यवादी शैली में माध्यमों की प्रणाली आरम्भ हुई। 1992 में राष्ट्रीय एसेम्बली ने संचार माध्यमों को छूट

तो दी लेकिन कुल नियन्त्रण प्रशासन के पास कायम रहे। 1993 मे सविंधान में प्रेस स्वतन्त्रता की गारन्टी दी गई। परिणामस्वरूप 1998 में खमेर भाषा में' 43 समाचारपत्र छपने लगे। लेकिन 66 प्रतिशत लोग समाचारपत्र नहीं पढ़ते थे। पत्रों की प्रसार संख्या भी 70 हजार से अधिक नहीं थी।

5.3.2.2 रेडियो

कम्बोडिया में रेडियो की शुरुआत फ्रेंच शासन में हुई। 1951 में प्रसारण को सुदृढ़ बनाने के लिए अमरीकन ट्रान्समीटर लगाया गया।1955 में चार रेडिया स्टेशन थे। 1958 में खमेर नेशनल रेडियो की क्षमता 10 कि. वाट थी। 1974 तक रेडियो सेवा का विस्तार निरन्तर होता रहा। 1979-92 के बीच तीन अलग-अलग राजनैतिक समूहों की खींचतान में तीन समूहों के रेडियो संचालन में थे । लेकिन 1998 में 76 प्रतिशत लोगों तक रेडियो की पहुंच थी। रेडियो राजनैतिक उठा-पटक के बीच झूलता रहा।

5.3.2.3 टेलीविजन

वियतनाम एवं सोवियत ब्लॉक के सहयोग से टेलीविजन कम्पूचिया (टी.वी.के.) दिसम्बर 1984 में संचालन में था। 1986 में रंगीन प्रसारण शुरू हुए। उस समय कम्बोडिया में लगभग दो लाख रेडियो रिसीवर तथा चार हजार टी.वी. सेट थे। खमेर, वियतनामी, फ्रेंच, अंग्रेजी लाओ एवं घाई भाषाओं में प्रसारण होने लगे। 1987 में सोवियत रूस ने नामपह में सेटैलाइट स्टेशन का निर्माण किया। 1998 के अन्त तक 65 प्रतिशत आबादी तक पहुंच हो गई।

5.3.3 नई सूचना -प्राद्योगिकी

गरीबी और विद्युत की कमी के कारण केमनेट पहली इन्टरनेट व्यवस्था ने 20वी सदी के अन्तिम वर्षों (1997) में शुरू हो गया। यह काम कम्बोडिया के डाक रात दूरसंचार मंत्रालय ने कनाडा ने अन्तर्राष्ट्रीय डेवलपमेन्ट रिसर्च सेन्टर के सहयोग से प्रारम्भ किया। कम्बोडिया में 1997 में 9 हजार कम्प्यूटर थे तथा 144 इन्टरनेट होस्ट कम्प्यूटर थे। 1998 में नामपेह पोस्ट कोम्बोडिया का ऑन लाईन समाचारपत्र था। दी वॉयस ऑफ कम्बोडिया इन्टरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस तथा टी.वी. -3 की भी वेबसाइट तैयार की।

5.3.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति

कम्बोडिया में प्रेस पर राजनीति का हस्तक्षेप होने के कारण विकास की गति मन्द रही। समाचारपत्रों का व्यावसायिक स्तर कमजोर रहा। 1997 में जबकि संचार के क्षेत्र में तेजी आ गई थी, कम्बोडिया में रेडियो एवं टेलीविजन विकास की ओर थे। इस समय तक सूचना प्रसारण के विकास दिशा में 'ऐसी नीति थी जो सूचना माध्यमों की विश्वसनीयता कायम कर सके। इस दिशा में प्रयत्नों के साथ देश में शिक्षा के प्रभाव तथा सूचना, शिक्षा, मनोरंजन के सन्तुलित कार्यक्रमों के सन्दर्भ में प्राथमिकताएं तय करने की आवश्यकता थी।

5.3.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे

कम्बोडिया में संचार माध्यम, राजनीति के क्षेत्र में संघर्ष एवं शीत युद्ध की छाया से ग्रस्त रहे। यद्‌यपि संघर्ष की परछाइयां छंट गई लेकिन देश में विभाजित विचारधारा की रेखाओं के निशान कायम रहे। सामाजिक और राजनैतिक जीवन के अपने पक्ष अविकसित रह गए। संचार माध्यमों में व्यावसायिकता की कमी के प्रति सभी राजनैतिक दल चिन्तित हैं तथा जनसंचार एवं पत्रकारिता-प्रशिक्षण के लिए प्रयत्न जारी हैं।

1991 में पहली बार कम्बोडिया के इतिहास में संचार माध्यमों को अधिक स्वतन्त्रता दिए जाने के प्रयास किए गए। लेकिन यह कोशिश कारगर साबित नहीं हुई। सरकारी नियंत्रण का शिकंजा फिर कड़ा हो गया। फ्रीडम हाऊस ने कम्बोडिया में 'प्रेस को स्वतन्त्रता नहीं' की श्रेणी में माना है। यद्‌यपि पड़ौसी देश विभिन्न स्तरों पर समाचार माध्यमों पर नियन्त्रण रखते हैं लेकिन पत्रकारों पर हुए हमलों एवं अन्य सन्दर्भों में कम्बोडिया की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई। लेकिन देश के हिंसात्मक वातावरण एवं प्रेस की राजनैतिक प्रकृति के सन्दर्भ में संचार माध्यमों की दशा कोई असाधारण बात नहीं है

5.4 इण्डोनेशिया में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्‌योगिकी

5.4.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

इण्डोनेशिया को उपनिवेशवादी शासन में डच ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। इण्डोनेशिया 17508 द्‌वीपों का समूह है जिनमें छह हजार द्‌वीप आबाद हैं। कुल भू-भाग का क्षेत्र 1.9 मिलियन किलोमीटर है। चीन, भारत और अमेरिका के बाद यह घनी आबादी वाला माना जाता है जिसकी आबादी 20.7 मिलियन है। जापानियों का कुल आबादी का 45 प्रतिशत, सुडानी 14, मडुरीज 7.5 प्रतिशत, मलय लोगों का भी प्रतिशत 7.5 है। बहासा इण्डोनेशिया की राष्ट्रीय भाषा है। 87 प्रतिशत लोग इस्लाम को मानते हैं। ईसाई 9 प्रतिशत, हिन्दु 2 प्रतिशत एवं बौद्ध एक प्रतिशत हैं। 585 भाषाएं एवं बोलियां है। इसलिए इण्डोनेशिया में भी विविधता में एकता की बात लागू होती है। 85 प्रतिशत साक्षरता है। इसकी सीमाएं मलेशिया एवं पापुआ न्यूग्यूयना से लगी है।

5.4.2 जनसंचार: उद्भव एवं विकास

5.4.2.1 समाचारपत्र

इण्डोनेशिया में डच लोगों ने डच ईस्ट इण्डिया के अपने कर्मचारियों के लिए 1615 में एक बुलेटिन निकाला। आम लोगों की अभिरुचि का पत्र 1744 में प्रकाशित किया गया। अपने देश की खबरें जानने के इच्छुक डच नागरिकों के लिए भी 18वीं सदी में समाचारपत्र प्रकाशित किया गया लेकिन इण्डोनेशिया में राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ 1908 के बाद 1910 में पेवरटाडेली में प्रेस का उद्भव हुआ। इसके बाद जापानियों का कब्जा होने पर 1942-45 में जापानियों ने प्रेस पर अपना आधिपत्य जमा लिया और सूचना तन्त्र का उपयोग प्रोपेगेन्डा के रूप में आरम्भ कर दिया। लेकिन उपनिवेशी शासन के खिलाफ स्वतन्त्रता आन्दोलन के प्रमुख नायक पत्रकार थे जिन्हें अनेक यातनाएं भोगनी पड़ी। जापानी सेना के कठोर शासन में भी स्वतन्त्रता सेनानियों ने चालकि

के साथ प्रेस में अपना विरोध व्यक्त करना जारी रखा। जापानियों ने स्वतन्त्रता के बाद डचों ने अधिकार जमाया। उनके एक तिहाई इण्डोनेशिया में पत्र हो गए। विश्वभर में डचों का विरोध हुआ और 1949 में इण्डोनेशिया आजाद हुआ। इस प्रकार आजादी प्राप्त करने की प्रक्रिया में समाचारपत्रों ने समाचारों द्वारा उपनिवेशवाद के खिलाफ विचारों आदि के द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

1957 में सारे डच समाचारपत्रों पर पाबन्दी लगाई गई। 1945-59 तक स्वतन्त्र वातावरण में समाचारपत्रों का विकास हुआ। 1957 में तीन अंग्रेजी दैनिक, 17 चीनी भाषा के दैनिक एवं अन्य समाचारपत्र थे। चीनी पत्रों की प्रसार संख्या 1,29,500 थी। 'इण्डोनेशिया राया' के सम्पादक मविज को सुमात्रा में विद्रोह के बाद नजरबन्द कर लिया गया और वे दस साल नजरबन्द रहे। 1959-65 के बीच विपक्षी पत्र बन्द कर दिए गए। समाचारपत्रों का उपयोग राजनैतिक दलों के प्रोपेगेन्डा के रूप में होने लगा। इसके बाद राजनैतिक वातावरण की अस्थिरता के बीच प्रेस में उतार-चढ़ाव होते रहे और विकास की कोई शुरूआत नहीं हो पाई। 1972 में इण्डोनेशिया में 130 दैनिक पत्र थे लेकिन राजनैतिक अस्थिरता के कारण यहां समाचारपत्रों का इतिहास समाचारपत्रों के छपने और बन्द होने का रहा।

5.4.2.2 रेडियो

17 अगस्त 1945 को स्वतन्त्रता की घोषणा के बाद रेडियो रिपब्लिक इण्डोनेशिया (आर. आर.आई.) संचालन में आया। सरकार ने इसे अपने अधिकार में लेकर डचों के खिलाफ क्रान्ति का हथियार बना लिया। डचों का जावा पर फिर से अधिकार होने पर यह रेडियो स्टेशन निष्प्रभावी हो गया। 1954 में फिर इसके कार्यक्रमों को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। 1970 में आर.आर. आई. के 50 स्टेशन हो गए और 100 क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्र बन गए। विदेश सेवा भी वॉयस ऑफ इण्डोनेशिया के नाम से शुरू हो गई। उपनिवेशवादी संबंधो के कारण इण्डोनेशिया को बेहतर कार्यक्रमों के निर्माण में नीदरलैण्ड पर निर्भर रहना पड़ता था। 1974 में ग्रामीण कार्यक्रमों पर बल दिया गया। इससे पूर्व 1966 में स्कूल ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर दी गई थी। रेडियो, टेलीविजन एवं फिल्म डायरेक्टोरेट ऑफ रेडियो के अन्तर्गत राज्य के अधीन है। सरकार समाज के विभिन्न वर्गों के लिए प्रसारण एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए एक चैनल प्रावधान करने के प्रति जिम्मेदार है।

5.4.2.3 टेलीविजन

टेलीविजन रिपब्लिक इण्डोनेशिया (टी.वी.आर.आई) 1962 में जकार्ता में शुरू हुआ। यह सरकार के अधीन था और एशियन खेलों के अवसर पर विशेष रूप से संचालन में आया। तत्कालीन सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रम की जनता को जानकारी देने के लिए इस माध्यम का उपयोग होने लगा। 1970 के दशक में टेलीविजन की सहायता से एक आधुनिक समृद्ध एवं प्रगतिशील समाज के निर्माण की दिशा में टी.वी. का इस्तेमाल होने लगा। रंगीन टी.वी. 1975 में प्रारम्भ हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय 1969 में टी.वी.आर.आई. के दो स्टेशन एवं सात प्रसारण केन्द्र थे चौथी योजना के अन्त में सरकार ने निजी टी.वी. संचालन के लिए अनुमति दे दी और परिणाम यह हुआ कि 1995 में पांच टी.वी. स्टेशन संचालन में आ गए।

5.4.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी

एक अनुमान के अनुसार 1998 में 67,500 उपभोक्ता थे। लेकिन इस बारे में एक दूसरे से विरोधी आकड़े सामने आते हैं। मलेशिया में 1.6 मिलियन कम्प्यूटर तथा 20वीं सदी के अन्तिम सालों में लगभग तीन लाख इन्टरनेट उपभोक्ता होने का अनुमान है। पहला इन्टरनेट सर्विस प्रोवाईडर 1999 में शुरू हुआ। उसके बाद नई संचार प्रौद्योगिकी के विकास की रफ्तार तेज हुई। इण्डोनेशिया में अन्य जनसंचार माध्यमों की तुलना में इन्टरनेट को अधिक स्वतन्त्रता है। बाली पोस्ट, इण्डोनेशिया ऑब्जर्वर, रिपब्लिक आदि सहित कुल 14 समाचारपत्र ऑन लाईन उपलब्ध हैं।

यद्यपि इण्डोनेशिया ने प्लेबॉय एवं टेन्ट हाऊस जैसी अश्लील पत्रिकाओं के प्रसार पर पाबंदी लगा रखी है लेकिन इनकी वेवसाईट को बन्द नहीं करवाया है। एक्सचेंज रेट्स, राजनैतिक सूचनाएँ एवं अश्लीलता से संबंधित वेबसाईट लोकप्रिय है। सरकार द्वारा इलेक्ट्रोनिक कामर्स, हेल्थ केयर, शिक्षा, पर्यटन, टेलीकम्यूटिग, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं जैसे कार्यों सरकार के ऑन लाईन आदि की कार्य योजना तैयार की गई। सरकार सैटेलाईट के माध्यम से ग्लोबल मोबाईल पर्सनल कम्यूनिकेशन जैसी नई तकनोलॉजी के विकास के लिए प्रयत्नशील है ताकि विकासशील एवं विकसित देशों तथा देश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच संचार माध्यमों एवं सम्प्रेषण के सन्दर्भ में खाई को पाटना सम्भव हो सके।

इण्डोनेशिया ने 1999 में एशिया सेल्यूलर सैटेलाईट के द्वारा मोबाईल कम्यूनिकेशन के विकास की तैयारी कर ली थी। इससे क्षेत्र के अन्य देशों को भी लाभ होगा। इसके अलावा एशिया एवं पेसिफिक क्षेत्र में मल्टीमीडिया सैटेलाईट सेवाओं के विस्तार हेतु एम 2 ए सैटेलाईट प्रणाली आरम्भ करने की पहल की। यह सैटेलाईट आधारित टू-वे डाइरेक्ट टू सब्सक्राईबर जनसंचार मच होगा जो लागत में भी प्रतिस्पर्द्धात्मक होगा।

5.4.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति

इण्डोनेशिया के राजनैतिक जीवन एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लम्बे दौर के उतार-चढ़ावों के बाद 1998 से विधि माध्यमों को अधिक स्वतन्त्रता दिए जाने के लिए पर्यावरण ने ठोस आधार लेना प्रारम्भ किया। पुराने प्रेस सम्बन्धी नियमों एवं कानूनों को सम्बोधित किए जाने के बारे में गम्भीर चिन्तन होने लगा। इण्डोनेशिया 'आशिक प्रेस स्वतन्त्रता' की श्रेणी में आता है। 'जकार्ता पोस्ट' के सम्पादक के अनुसार 'प्रेस की स्वतन्त्रता ' में कमी के होने से जनसंचार माध्यमों को स्वयं अपने काम में सेन्सरशिप का पालन करना पड़ता है। लेकिन 1998 के बाद संचार माध्यमों के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के क्रान्तिकारी परिवर्तनों के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की प्रक्रिया जारी है। 1999 में नया प्रेस कानून लागू किया गया है। इससे माध्यमों के विकास का नया मार्ग प्रशस्त हुआ है।

5.5.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे

प्रेस की स्वतन्त्रता को सीमित करने के लिए पत्रकारों को पत्रकारिता के लिए लाईसेन्स लेने की आशंका के सन्दर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारों का ध्यान इस ओर गया है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पेपर्स ने इसे प्रेस की आजादी का मखौल बताया है और माना है कि

इससे स्वत: ही सेन्सरशिप लागू हो जाती है। अनेक अन्तर्राष्ट्रीय टेलीविजन चैनलों की बीच राष्ट्रीय टी.वी. के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया है।

Media **Revenue by TV Channel Indonesia**

TV Chennel	1995		1996		1997	
	Million Rp	%	Million Rp	%	Million Rp	%
RCTI	624,217	38.1	741,036	33,6	777.083	29.0
SCTV	332.863	20.3	464.262	21.1	548.211	20.5
IVM	229,326	14.0	361,804	14.4	490,803	18.3
TPI	297,638	18.2	343,801	15.6	466,796	17.4
AN-TV	154,075	9.4	291,699	15.6	466,796	17.4
Total	**1,638.119**	**100**	**2,202,608**	**100**	**2,678,016**	**100**

Source: PPP, 1998

Indonesia's top Newspaper

Newspaper	Publishers	Established	Circulation (000)	Readership
Kompas (am)	Kompas	Media Nusantara	1965	5252.04 million
Pas Kota(d)	Media Antarkota jaya	1970	500	2.23 million
Jawa Pos (am) (Surabaya)	Jawa Post	1949	120	1202.23 million
Suara Prembarun (pm)	Media Interakshi Utama	1987	250/387	802,000
Republika	AbdiAbdi Bangsa	1993	327	589,000
Media Indonesia	ChitraMedia NusaPurnama	1969	294	590,000
Saura Merdeka (am) (Sermarang)	Suara Mederka Press	1950	192/2000	402,000
HarionPagi Memorandum(d) (Surabaya)	JawaPost		190	
Pikiran Rakyat (am) (Bandung)	PikiranRakyat Bandung	1956	150/180	696,000
Saura Karya(am)	Saura RakyatMembangum	1971	146	237,000
Surya (Surabaya)	Antar Surya Jaya	1986	141	

Berita Bauna (am)	Berita Bauna Press	1971	138/150	206,999
Merdeka (am)	Merdeka Press	1945	130	
Surabaya Post (pm) (Surabaya)	Surabaya Post	1953	101/115	209,000
Berita Yudha (d)	Bina Media Tenggara	1983	80	
	English language Details			
Indonesia Times (am)	Wiwara Jaya	1974	41	
Indonesia Observer(am)	Indonesia Oberver Ltd.	1966	35	
Jakarta Post(d)	Bina Media Tenggara	1983	48	

Source : WAN, 1999, Editor & publisher international yearbook, 1999

5.5 लाओस में जनसंचार और नई सूचना -प्रौद्योगिकी

5.5.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

चीन, वियनताम, कम्बोडिया, थाईलैण्ड तथा म्यांमार की सीमाओं से घिरा लाओस 2,37,000 कि मी. में फैला एक छोटा-सा देश है। अधिकांश भू-भाग पर्वतीय है और जंगलों से छिपा है। 7 प्रतिशत भूमि खेती योग्य है। मनसूनी जलवायु है तथा बाढ़ या सूखे की चपेट में आना आम बात है। 5.4 मिलियन आबादी है जो अधिकांशत ग्रामीण है। 60 प्रतिशत लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। तीन प्रमुख समुदाय है जिनमें लाओलूम नगरों में रहते हैं। कुछ आदिवासी हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। चीनी, पाकिस्तानी, वियतनामी और भारतीय व्यवसायी भी हैं। अंग्रेजी दूसरे नम्बर की भाषा है। तीन प्रमुख भाषाएँ हैं-लाओलम, मोंग एवं खमाऊं। एक हजार साल की क्षेत्रीय अस्थिरता, एक सदी के यूरोपीय उपनिवेशवाद एवं 30 साल के गृहयुद्ध के बाद लाओस को 1975 में आजादी प्राप्त हुई और लाओस पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (एल.पी.डी.आर.) की स्थापना हुई।

5.5.2 जनसंचार;उद्भव एवं विकास

5.5.2.1 समाचारपत्र

लाओस में समाचारपत्रों की शुरूआत फ्रेंच उपनिवेशवाद के पोषण के लिए 20वीं सदी में आरम्भ में हुई। 1975 से पूर्व लाओस के 41 समाचारपत्र थे जिनमें 11 दैनिक थे। इनमें से अधिकतर पर राजनैतिक दलों का स्वामित्व था। सबसे अधिक लाओ भाषा के 16 समाचारपत्र थे। शेष फ्रेंच, अंग्रेजी एवं अन्य भाषाओं में थे। औपचारिक रूप से मीडिया एवं ब्रॉडकास्टिंग कानूनों का देश में अभाव है। सूचना एवं संस्कृति मंत्रालय माध्यमों पर नजर रखता है। लाओ भाषा के समाचारपत्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे राज्य, राजनैतिक दल एवं आम जनता की भावनाओं

का ध्यान रखें। केन्द्रीय सेन्सरशिप नहीं है। ऐसे में अस्पष्टता एवं सावधानी बरतने की स्थितियों को भी मध्यनजर रखना पड़ता है।

अधिकांश पत्रकारों को पत्रकारिता का औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। सरकार की संवेदनशीलता के सन्दर्भ में स्वविवेक से वे समाचारों का सम्पादन संयम के साथ करते हैं। लाओस के पत्रकार अपना कर्त्तव्य समझते हैं और यह स्पष्टत: ध्यान में रखते हैं कि किस प्रकार के समाचार वे प्रकाशित कर सकते हैं और किन बातों से उन्हें सजग रहना चाहिए। सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी नीतियों के बारे में कोई सवाल खड़ा करने से पहले वे विशेष सावधानी बरतते हैं। यद्यपि 1991 के संविधान में प्रेस की आजादी एवं नागरिकों की स्वतन्त्रता का प्रावधान है। लेकिन बहुत कम लोग इन अधिकारों का उपयोग करने के लिए स्वतन्त्र हैं। लाओस के समाचारपत्र एक प्रकार से नगरीय पत्र हैं। परिवहन समस्याओं के कारण दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक इनकी पहुँच नहीं है। वितरण की कठिनाइयां है।

5.5.2.2 रेडियो

समाचारपत्रों की तरह रेडियो एवं टेलीविजन भी सूचना एवं संस्कृति मंत्रालय के अधीन हैं रेडियो से भी राष्ट्रीय एकता एवं सरकारी नीतियों के पोषण की अपेक्षा की जाती है। दूसरे विश्वयुद्ध से पहले फ्रांस ने रेडियो का प्रारम्भ किया था। वर्तमान में रेडियो का निर्माण 1966 में अमेरिका ने किया। दूरदराज तक पहुँच में आसान, सस्ता और सुविधाजनक होने के कारण लाओस नेशनल रेडियो (एल.एन.आर.) अपनी प्रसारण की क्षमता एवं सामुदायिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की क्षमता से सबसे लोकप्रिय जनसंचार माध्यम सिद्ध हुआ। लेकिन धन, प्रशिक्षित जनसंचारकर्मियो की कमी तथा उपकरणों के अभाव को झेलते एल.एन.आर. के समक्ष श्रोताओं की भी कमी थी क्योंकि युद्ध के विनाश के कारण आम लोग रेडियो रिसीवर खरीदने की क्षमता खो चुके थे। 1994 में रेडियो आस्ट्रेलिया ने बेहतर उपकरण उपाधि कराए एवं यूनेस्को ने आर्थिक सहयोग देकर एल.एन.आर.की क्षमता को बढ़ाने में योग दिया। इससे पूर्व दो दशक तक एल.एन.आर. को अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बहुत सहयोग मिला।

5.5.2.3 टेलिविजन

लाओस नेशनल टेलिविजन 1983 में शुरू हुआ है। 1988 में टी.वी. सेवाओं का विस्तार किया गया। जापानी सहयोग से 1983 में सेवाओं में सुधार का प्रयास किया गया। आस्ट्रेलिया एवं एशिया पेसिफिक इन्स्टीट्यूट फार ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेन्ट (ए.आई.वी.डी.) जनता को सरकार की नीतियों से जोड़ने के माध्यम या एक मच के रूप में टी.वी. का भी रेडियो की तरह सरकार इस्तेमाल करती है। माध्यमों का यह दायित्व माना जाता है कि वे सरकार के लिए अनुकूल वातावरण की रचना करें। सरकार द्वारा जनसंचार माध्यमों का स्वतन्त्र रूप से जनतान्त्रिक प्रक्रिया में अपनी भूमिका अदा करने के सम्बंध में कोई अहमियत नहीं देता।

5.5.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी

लाओस में दूरसंचार की कमजोर ढांचागत स्थिति साक्षरता, का कम, प्रतिशत, लाओ लिपि के लिए कम्प्यूटर हार्डवेयर की असमर्थता आदि के कारण इन्टरनेट कम्प्रैनकेशन के विकास में अवरोध रह। 1996 देश में मात्र पाँच हजार कम्प्यूटर थे। इन्टरनेट के विकास एवं कम्प्यूटर

एप्लीकेशन के लिए पठनीय सामग्री के न होने से नई संचार प्रौद्योगिकी के विकास को गति नहीं मिल सकी। 1994 में इन्टरनेट की शुरूआत जरूर हुई। सरकारी नीतियों' के कारण निजी क्षेत्र भी इस ओर अधिक योग नहीं दे सका।

5.5.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति

कई विकासशील देशों की तरह लाओस में भी विभिन्न माध्यमों के लिए उपकरणों एवं सुविधाओं को जुटाने में विदेशी सहायता पर आर्थिक निर्भरता रही। प्रशिक्षित मानव संसाधनों की भी कमी रही। 1993 में इसलिए सूचना एवं संस्कृति मंत्रालय ने मास मीडिया ट्रेनिंग सेन्टर (एम.एम.टी.सी.) की स्थापना की, लेकिन इस संस्था के पास भी व्यावसायिक अनुभव की कमी थी। अत: इस काम के लिए विशेषज्ञों की सहायता लेनी पड़ी।

5.5.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे

लाओस का आर्थिक भविष्य पर्यटन पर निर्भर है। समाचारपत्र, इलेक्ट्रोनिक माध्यम की व्यूह रचना में यह मुद्दा शामिल है। लेकिन आर्थिक विकास के सन्दर्भ में जनसंचार माध्यमों को नीतिगत ढांचे में सरकार ने महत्व नहीं दिया है लेकिन समाज में ऐसी शक्तियां भी है जो लाओस के सामाजिक एवं आर्थिक स्वरूप को आधुनिक रूप देने की उत्सुक है। सरकार की नीतियों में परिवर्तन की सम्भावना है क्योंकि जनसंचार माध्यमों एवं राज्य की सम्बद्धता से लाओस के लोग अपने जनसंचार माध्यमों के विकास के द्वारा अपने भविष्य की संरचना करने के इच्छुक हैं।

Print media Radio Television laos

Print media

Newspaper	**Publisher**	**Circulation**
Dailies		
Pasason (people) veintiane	Central Committee of LPRP Vientiane Party	10,000
Mar (New Vientiane)	committee	5,000
TWICE WEEKLY Veiniane Times	Ministery of Information & Culture	3,200
WEEKLIES		
Pasason Va Athit (Sunday People) Veintiane Thurakit Sangkorn	Cc of LPRP	2,000
(Buisness-Social)	Veintiane Party committee	2,000
Khao Thurakit (Businss News)	Lao National Party Chamber of Commerce & Industry Khongtap (Army)LaoArmy	
MONTHLIES'		
Haeng Ngan (Labor)Lao	Federationof Trade Unions	
Noum Lao (Lao Youth)		
Nyasvason (Pioneers)		
Vannasin (Literature) magazine		
Sieng Khaen Lao (sound of	Lao Association of Writers	

Lao)	Ministry of Information & Culture
Savannakhet Phatthana (Development)	Savannakhet Province
	Lao Woman's Union
Menhing (Lao Woman)	Muncipal Government
Khoueng Vientiane (Vientiane Province)	
QUARTERLIES	
Seuksa Mai (New Education)	
Soukhaseuksa (Helth Education)	
Pather Lao (Lao Country)	
Aloun Mai (New Dawn)	
Khosana (Propagada)	
Vithayasat Technic (Science and Technology)	Science, Technology & Environment Organization (STENO)
	Radio
Lao National Radio	12 station (AM/FM/SW in Vientiane Luang Prabang Xient Khouan. Luang Namtha,Oudomsay.Savannakhet, Champassak
	Television
Lao National Television (Ch 3 and Stn. 10)	10 Station in Vientrane, Luang Prabang Xieng Khouang Luang Namtha, Oudomasay Houaphan, Sayabourt, Khammoun, Savannakhet, Champassak

5.6 मलेशिया में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी

5.6.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

दक्षिण पूर्वी एशिया में थाईलैण्ड, सिंगापुर, इण्डोनेशिया एवं फिलीपीन्स की सीमाओं से घिरा मलेशिया 13 राज्यों का एक संगठन (फेडरेशन) है। यहां बहु समुदायों का समाज है। इनमें मलय, चीनी और भारतीय प्रमुख है। इसका एक कारण यह भी है कि यह देश चीन और भारत के बीच स्थित है। मलेशिया की 22.7 मिलियन जनसख्या में 47 प्रतिशत नगरीय आबादी है। साक्षरता का प्रतिशत 92.7 है। मलेशिया को 1957 में ब्रिटेन से आजादी मिली। कुआला-लम्पुर (Kualalumpur) मलेशिया की राजधानी है।

5.6.2 जनसंचार: उद्भव एवं विकास

5.6.2.1 समाचारपत्र

मलेशिया के छह समाचारपत्र ऐसे हैं जो 1945-57 के बीच शुरू हुए। मलय भाषा का पहला पत्र रोमन लिपि में दूसरे विश्वयुद्ध के बाद प्रकाशित हुआ। अभी जो 36 समाचारपत्र प्रकाशन में हैं, वे 1962 में शुरू हुए। 12 समाचारपत्रों का प्रकाशन 1963 से 1980 के बीच में हुआ। आजादी के बाद उतुसान मलेशिया (1967) नामक प्रमुख पत्र प्रकाशन में आया। इसकी प्रसार संख्या 5 लाख से अधिक थी। अंग्रेजी में 'स्टार' 1971 से छपने लगा। मलेशिया में छोटे साप्ताहिक समाचार मोस्क्यूटोपेपर (मच्छर समाचारपत्र) के नाम से लोकप्रिय हैं। मलेशिया के समाचारपत्रों की दिशा को वहां प्रेस कानूनों ने प्रभावित किया। 1974 में कानूनी संशोधन के द्वारा अधिकांश समाचारपत्रों का स्वामित्व मलेशियावासियो के हाथों में चला गया। समाचारपत्रों का मलेशियायीकरण करने का प्रयास किया गया।

5.6.2.2 रेडियो

मलेशिया ब्रिटिश उपनिवेशों में से एक था जहां रेडियो सेवाओं का सबसे पहले संचालन आरम्भ हुआ। लेकिन अंग्रेजों ने शुरू में रेडियो के विकास मे अधिक रुचि नहीं ली। 1933 में रेडियो सर्विस कम्पनी ऑफ मलैया संचालन में आई। बी.बी.सी. के अधिकारियों की भागीदारी के साथ ब्रिटिश मलैया ब्राडकास्टिंग कम्पनी (बी.एम.बी.सी.) पहली रेडियो पूर्ण प्रसारण की सेवा शुरू हुई। 1941 में इसे ब्रिटिश सरकार ने खरीद लिया। लगभग 4 साल जापानियों का अधिकार रहा। जापान के आत्मसमर्पण के बाद फिर अंग्रेजी हाथों में रेडियो आ गया। रेडियो मलैया की स्थापना 1946 में हुई और इसका मुख्य कार्य देश की आजादी (1957) तक सामाजिक एवं राजनैतिक असमंजस के वातावरण को नियन्त्रित करना रहा। लेकिन उसके बाद इसके कार्य का विस्तार हुआ और रेडियो को सामाजिक बदलाव का प्रमुख माध्यम माना गया। 1998 में रेडियो के 2,3 स्टेशन के तथा निजी रेडियो स्टेशन की संख्या 14 थी।

5.6.2.3 टेलिविजन

रेडियो टेलीविजन मलेशिया (आर.टी.एम.) ने 28 दिसम्बर, 1963 में श्वेत-श्याम टी.वी. प्रसारण आरम्भ किए। दूसरा श्वेत-श्याम टी.वी. नेटवर्क 1969 में तैयार हुआ। 1970 में आर.टी.एम. ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का सैटेलाईट अर्थ स्टेशन 1970 में स्थापित किया। रंगीन टी.वी. का आरम्भ 28 दिसम्बर, 1978 को हुआ। 1983 तक प्रसारणों का नियन्त्रण सरकार के हाथों में रहा। राजस्व लाभ के लिए निजी मालिकों को सिस्टम टेलीविजन मलेशिया (टी.वी.3) को लाईसेंस देकर 1984 में निजी क्षेत्र के लिए द्वार खोले। दस साल बाद 1955 में दो और निजी चैनल्स को लाईसेंस प्रदान किए। इसके बाद टी.वी. के विकास एवं विस्तार को गति मिली।

5.6.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी

मलेशिया में 1956 में इंटरनेट का उपयोग करने वालों की संख्या 63,945 थी। 1997 में एक मिलियन कम्प्यूटर देश में प्रयोग किए हटे थे। कई पड़ोसी देशोंकी तुलना में संचार प्रद्योगिकी के विकास में मलेशिया अग्रणी था। 1997 में सूचना प्रौद्योगिकी में साक्षरता

(लिटरेसी) का मलेशिया में प्रतिशत 8.2 था। दी स्टार, बेरिटाहेरियन, न्यू स्टेट्स टाइम्स, उतुसान मलेशिया, उतुसान एक्सप्रेस कई समाचारपत्रों को प्रोत्साहन देने में गहरी रूची ली।

5.6.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति

परम्परागत जनसंचार माध्यमों पर लागू कानूनों से हटकर मलेशिया में मल्टीमीडिया सुपर कोरिडर कानून के तहत यह गारन्टी दी गई कि इन्टरनेट को सेन्सर नहीं किया जाएगा। कम्यूनिकेशन एण्ड मल्टीमीडिया एक्ट जो 1 अप्रैल, 1999 से लागू हुआ, में 'नो सेन्सरशिप ' का प्रावधान रखा गया। प्रेस को निजी क्षेत्र तक सीमित रखा। सरकार कोई समाचारपत्र प्रकाशित नहीं करता। यह बात अलग है कि सत्ताधारी राजनैतिक दलों से नजदीकी सम्बन्ध रखने वाली कम्पनियां कई मुख्य धारा के समाचारपत्रों का संचालन करती है। सीधे तौर सुर समाचारपत्रों पर कोई पाबन्दी नहीं है। विदेशी पत्रों में छपे आलेखों का बहिष्कार या यौन और हिंसा से सम्बन्धित कार्यक्रमों पर पाबन्दी लगाई जाती है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि जनसंचार माध्यमों पर सरकार का प्रभाव है तथा आलोचनात्मक पत्रकारिता पर पाबन्दी पर सेल्फ सेन्सरशिप है

यथार्थ में मलेशिया में प्रेस को उतनी स्वतन्त्रता नहीं है जितनी परिलक्षित होती है। यह भी मत है कि प्रेस सामाजिक दायित्व भाव से काम करती है और सम्बंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रमुख समाचारपत्र सरकार का समर्थन करते और लगता है की वे राष्ट्र के विकास में भागीदारी की भूमिका निभाते है। विदेशी समाचारपत्रों के विकास की अनुमति है। दो विदेशी पत्रों 'एशियन वाल स्ट्रीट जनरल एवं इन्टरनेशनल हराल्डट्रिन्यून का मलेशिया में मुद्रण एवं प्रकाशन होता है। विदेशी पत्रकारों को ग्राहमन्त्रालय से आज्ञा लेकर काम करना पड़ता है लेकिन इस दिशा में नियमों को बदलने की सोच जारी है रेडियो के क्षेत्र में भी निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की नीति है।

5.6.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे

मलेशिया में निजी क्षेत्र की जनसंचार माध्यमों के विकास में भागीदारी की नीति की ओर सरकार का रुझान होने से देश में रेडियो एवं टेलिविजन का विस्तार हुआ है। लेकिन सरकार ने देश की एकता एवं विकास को पुष्ट बनाए रखने के लिए अपने स्वयं के दो टी वी. चैनल एवं राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय टी.वी. स्टेशनों के द्वारा कार्यक्रमों के संचालन का काम जारी रखा है। लेकिन पूरी तरह से मुख्य धारा के जनसंचार माध्यमों के जनतंत्र करण की प्रक्रिया को पूर्ण करने की आवश्यकता है। माध्यमों में मानव संसाधन में कमी किए जाने,न्यूज़ प्रिंट की लागत में वृद्धि, विज्ञापन, राजस्व में कमी आदि समस्याओं के कारण जनसंचार माध्यमों की गति में अवरोध आए है

Media	**Newspapers Malaysia**			
Newspaper	**Year Estb.**	**Place of Publication**	**Language**	**Circulation**
Kwong Wah Yit Poh	1910	Penang	Chinese	70,242
Nanyang Siang Pau	1923	Petaling jaya	Chinese	175,339
Sin Chew Jit Poh	1929	Petaling Jaya Chinese	Chinese	264,283
Chineise Daily News	1945	Kuching, Sarawak	Chinese	
		Chinese 16,075		

Miri Daily News	1945	Miri, Sarawak	Chinese	24,230
China Press	1946	Kuala Lumpur	Chinese	171.636*
See Hua Daily News	1952	Sibu, Sarawak	Chinese	54,484
International times	1968	Kuching	Chinese	36,170
Merdeka daily News	1968	Sandakan, Sabah	Chinese	6,948
Malaysia Daily News	1968	sibu, Sarawak	Chinese	21,741
Berita Petont	1970	Kuchin, Sarawak	Chinese	9,600*
New Life Post (bi-Weekly)	1972	Petaling Jaya	Chinese	136,457*
Asia Times	1976	Kota Kinabalu	Chinese	15,729
Morning Post	1981	Tawa, Sabah	Chinese	8,730
Mun Sang POh	1986	Ipoh, Perak	Chinese	79,138*
Overseas Chinese Daily News	1986	Kota Kinabalu	Chinese	18,505*
Guang Ming Daily	1987	Petaling jaya	Chinese	100,475
See Hua Daily News	1993	Kota Kinabalu	Chinese	21,974
New Straits times	1845	Kaula Lumpur	English	155,977
New Sunday Times				
Malay Mail		Kaula Lumpur	English	48.567
	1896			
Sunday Mail				
Sarawak Tribune	1945	Kuching,Sarawak	English	41,617
Sunday Tribune	1993	Kota Kinabalu	English	26,558
Daily Express				
The Star	1971	Petaling Jaya	English	220,493
Sunday Star				252,565
Business times		Kuala Lumpur	English	15,000*
	1976			
Borneo Post		Kuching	English	41.120
	1978			
Sun		Petaling Jaya	English	79,150
	1991			
Borneo Post (Sabah)		Kota Kinabalu	English	21,619
	1994			
The Edge (weekly)	1994	Petaling Jaya	English	11,862
Boreneo Mail	1988	Kota Kinabalu	English	17,007
			BM/Kadayandusum	
New Sabah Times	1998	Kota Kinabalu	English	13,000(c)
Utusan Malayu	1939	Kuala Lumpur	Malay	8,186
Utsan Zaman				8,963
Berita Harian	1956	Kuala Lumpur	Malay	249,756

Berita Minggu				391,813
Utsan Malaysia	1967	Kaula Lampur	Malay	267,765
Mingguan Malaysia	1964			522.857
Utsan Sarawak	1983	Kuching	Malay	31,598
Harian Metro	1991	Kuala Lumpur	Malay	77,036
Metro Ahad				135,313
Tamil Nesan	1924	Kaula Lumpur	Tamil	35,000(c)
Malaysia Nanban	1980	Kaula Lumpur	Tamil	45000(c)
				108,000(c)
Thina Murasan	1987	Kaula Lumpur	Tamil	22,000(c)
				85,000
Makkal Osar.	1991	Kuala Lumpur	Tamil	28,000

Source: Press guide ,1998; Media guide,1999

Note : (C) = claimed circulation;*figures for 1997

Television Channels

Name of station	**Mode**	**Year Operation**	**Coverage**	**Numberofchannels**
Radio and TV Malaysia	Terrestrial	1963 (TV1)	National	1
Radio and TV Malaysia	Terrestrial	1969 (TV2)	National	1
Sistem Television Malaysia.Bhd	Terrestrial	1981(TV3)	National	1
Metrovision	Terrestrial	1995	Khing Valley (K Lumpur and Selangor State)	1
Mega TV	Cable	1995	National	10
ASIRO	Satellite	1996	National Interational	23
National TV	Terrestrial	1997(NIV7)	National	1

Source: The Ministry of Information 1999

5.7 म्यांमार में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी

5.7.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

दक्षिण पूर्वी एशिया के बड़े देशों में यूनियन ऑफ म्यांमार (बर्मा) 6,77,752 वर्ग किलोमीटर में फैला देश है। उत्तर पूर्व में चीन,पूर्व में थाईलैण्ड एवं पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में भारत और बंगलादेश इसके सीमान्त देश हैं। म्यांमार की जनसंख्या 48 मिलियन है। बर्मन लोगों का यहां बाहुल्य है। बर्मीज यहां की भाषा है जिसे बर्मा के अन्य अल्पसंख्यक समुदाय भी अपनी-अपनी भाषा के साथ बर्मीज का उपयोग करते 'हैं। अंग्रेजी का भी बहुत चलन है। 89 प्रतिशत लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। साक्षरता का प्रतिशत 83.6 है। 29 प्रतिशत आबादी नगरों में बसती

है। अपने इतिहास के लम्बे दौर में अन्य देशों से अलग एकान्त इसकी विशेषता रही है। यह एकान्त 1988 में पहली बार टूटा जब कई हमलों के बाद ब्रिटेन ने इसे भारत में जोड़ दिया। ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध 1920 एवं 1930 के दशकों में उभरा। 1941 में राष्ट्रवादियों ने म्यांमार पर हुए जापान के आक्रमण के समय उसका साथ दिया लेकिन जल्दी ही उन्हें पता चला कि जापान की उन्हें आजादी दिये जाने की मंशा नहीं है। उन्होंने फिर 1945 में ब्रिटेन का साथ दिया जिससे जापान की हार हुई। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद 4 जनवरी, 1948 को म्यांमार आजाद हुआ। समाचारपत्रों की पहुँच अधिकांशत: नगरों तक है।

5.7.2 जनसंचार : उद्भव एवं विकास

5.7.2.1 समाचारपत्र

म्यांमार में व्यावसायिक पत्रकारिता की एक लम्बी परम्परा चली आ रही है। आधुनिक शैली के समाचारपत्र की नींव वहाँ 1836 में डाली गई। बर्मी भाषा का पहला पत्र 1874 में प्रकाशित हुआ। म्यांमार एशिया (लाइट ऑफ बर्मा) रंगून से 1919 में प्रारम्भ हुआ। म्यांमार की आजादी के समय 1948 में 30 समाचार पत्र थे। उस समय तक इस देशं का नाम बर्मा था। उस समय बर्मी एवं अंग्रेजी के पत्रों के अलावा चीनी भाषा के पाँच, दो हिन्दी भाषा के एवं एक-एक पत्र उर्दू, तमिल एवं गुजराती भाषा के थे। राजनैतिक दृष्टि में वे पत्र तीन विचारधाराओं को प्रतिबिम्बित करते थे-दक्षिण पंथी, वामपंथी एवं सरकार को नीति के पोषक। समाचारपत्रों पर अंकुश तो था लेकिन काफी सीमा तक वे स्वतन्त्र थे। उस समय समाचारपत्र सरकार की नीतियों पर जानते हुए 'वाचडोग ' की भूमिका का निर्वाह करते थे।

समाचारपत्रों के लिए 1962-88 का समय प्रेस के लिए संकट का था। 1962 में जब सेना ने शक्ति पर कब्जा किया स्थितियां एकदम बदलने लगीं। नई क्रान्तिकारी कोंसिल ने समाचारपत्रों का सरकार से पंजीकरण कराकर के लाईसेन्स लेने की पद्धति चालू की। सेन्सर भी शुरू हो गया। 1966 में रिवोल्यूशनरी कोंसिल ने बर्मी एवं अंग्रेजी भाषा के पत्रों को छोड़कर 12 भारतीय, पाकिस्तानी एवं चीनी भाषा के पत्रों को बन्द कर दिया। सरकार ने अंग्रेजी एवं अन्य भाषाओं के प्रतिष्ठित कई समाचारपत्रों को पहले ही 1960 के शुरू में बन्द कर दिया था। सरकार ने अपना पत्र 'दी वर्किंग पीपल्स डेली ' का बर्मी एवं अंग्रेजी में प्रकाशन करना आरम्भ कर दिया। देश में निजी समाचारपत्रों का धीरे-धीरे सफाया कर दिया गया। इस प्रकार अगस्त, 1988 तक समाचारपत्रों पर सरकार का पूर्ण नियन्त्रण हो गया। लेकिन उसके बाद कुछ समाचारपत्र उभरे और सरकारी पत्रों पर भी प्रभाव डालने लगे लेकिन आजादी की श्वास लेने का यह समय बहुत कम था। नई सरकार बनी। उसने भी शीघ्र ही समाचारपत्रों पर पाबन्दी और सेन्सरशिप थोप दी। सरकार के नियन्त्रण वाले पत्र भी बन्द कर दिए। विदेशी माध्यमों पर भी कड़ी निगाह रखी गई। विदेशी पत्रकारों का आना और काम करना मुश्किल था। सरकारी नियन्त्रण के साथ की मांग (मिरर) शुरू किया गया। इस प्रकार आजादी मिलने के बावजूद जनसंचार माध्यमों की स्थिति सरकारी प्रोपेगेन्डा का हथियार बनकर रह गई।

5.7.2.2 रेडियो

बी.बी.सी. ने दूसरे विश्वयुद्ध के समय बर्मी भाषा की प्रसार सेवा के साथ बर्मा में रेडियो की नींव रखी। 1939 में रंगून के पास 10 कि.वाट का ट्रांसमीटर लगाया गया। आजादी के बाद बर्मा ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (बी.बी.एस.) आरम्भ हुई। कार्यक्रमों के प्रसारण का स्वरूप भी एक जनतांत्रिक देश के ऐसे कार्यक्रमों के समान था। लेकिन माध्यमों की आजादी का 1962 में सेना के सत्ता हथियाने के साथ ही अचानक अन्त आ गया। एशिया के अन्य देशों की तुलना में म्यांमार का रेडियो नेटवर्क सदैव सीमित और कम विकसित रहा। इस स्थिति का कारण सरकार की केन्द्रीयकृत नियन्त्रण की नीति वित्तीय सीमाएं आदि रहीं। यद्यपि रेडियो देश का लोकप्रिय माध्यम है लेकिन रेडियो म्यांमार (पहले जिसका नाम बी.बी.एस. था)एकमात्र सरकारी रेडियो है जो पाँच प्रसारण केन्द्रों माध्यम से सेवाएं देता है। देश में अनुमानत: रेडियो रिसीवर की संख्या 4 मिलियन है।

5.7.2.3 टेलीविजन

म्यांमार में 1980 में जापान के सहयोग से सरकार के स्वामित्व एवं नियन्त्रण में टी.वी. की स्थापना हुई। सेना ने 1990 में दूसरा टी.वी. स्टेशन खोला। इनके कार्यक्रमों का देशभर में प्रसारण होता है। 1990 के प्रारम्भ में स्टार टी.वी. का प्रवेश हुआ। लेकिन: सैटेलाईट रिसीवर डिस्क के लिए सरकारी आज्ञा प्राप्त करनी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में कमी के कारण टी.वी. कार्यक्रमों की पहुँच कम है। वैसे 'एशिया सेट-सैटेलाईट' के कारण टी.वी. का प्रसारण 82 प्रतिशत जनता तक पहुँचना सम्भव है। म्यांमार के 324 कस्बों में से 267 तक इसकी पहुंच है। 1997 में म्यांमार में 2,60,000 रेडियो सेट थे।

800 साल म्यांमार (बर्मा) में राजाओं का शासन चला। इसके बाद एक सदी तक ब्रिटेन ने राज किया। 1948 में आजादी के बाद एक दल या अधिनायक वादी सेना का शासन चला आ रहा है। इस कारण जनतांत्रिक सरकार एवं मुक्त जनसंचार माध्यमों की स्थापना की कोशिशें नाकामयाब रहीं। राजनैतिक शासन प्रणालियों की पुरानी परम्पराओं के बीच आधुनिक राज्यों की मुक्त विचारधाराओं की हवा में जनसंचार माध्यमों को सांस लेने के अवसर कुंठित है।

Media	**Mayanmar**
Broadcast	Yangon
Myanmar Television and Radio Department	**Aweebwaye**
(MTRD)	Office of the Board of Editors
365-367 Bo Aung Gyew St,	296 Bo Sun Pat St.
Kyanktada Township	Pabedan Lownship
Yangon	Yangon
Newspapers	**Myanmar Economic Journal**
Mayanmar Alin	1, Kinwun Mingyl Road
212, theinbyu Road	Dagon Lownship
Botahtaung Township	Yangon
Yangon	**Oksa Dana Journal**
New Light of Myanmar	**Severn Dragеon Myanmar enterprise co.**

22-30 Suand Road
Yangon
Kyemon
77-52nd st.
Payundaung
Yangon
Tabloids
City News
Third Floor, City Central Plaza,
Shwedagon Pagods Road,
Yangon
Magazine
Dana
189-b 33rd St.
Kyauktada Lownship
Yangon
Myanmar Dana
Building 7, Room 8
Lanthit Yeiktha Road
Ltd.
37A-U Tun Myat Road
Tamwe Township
Yangon
News Agencies
Myanmar News Agency
212 Thembyu Road
Botahtaung Township
Yangon
Foreign Bureaus
Agence France Presse
121, Pyithu Lane
70 Mile
Yangon
Associated Press
283-U, Wisara Road
Sanchaung
PO Bo 11111
Yangon
Xinhua News Agency
105 Leeds Rd.
Yangon

5.8 फिलीपींस में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी

5.8.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

इण्डोनेशिया के बाद फिलीपीन्स दूसरा ऐसा द्वीपों का राज्य है जो 3,01,000 वर्ग किलोमीटर भू-भाग के साथ 22 लाख (2.2 मिलियन) वर्ग किलोमीटर के जलीय क्षेत्र में फैला हुआ है। इनमें 2803 द्वीपों का नामकरण हुआ है और केवल एक हजार द्वीप आजाद हैं। पश्चिम एवं उत्तर में चाईना समुद्र है और पूर्व में पेसिफिक सागर। प्राकृतिक स्रोतों की दृष्टि से समृद्ध है। इस देश को पर्यावरणवाद पर्यावरणीय विविधता का प्रदेश (बायडोयरवर्सिटी सुपर स्टार) का सम्बोधन देते हैं। 1999 में यहां की जनसंख्या अनुमानत: 7 करोड़ 39 लाख (73.9 मिलियन) मानी गई है। इसमे से 80 लाख लोग मनीला में रहते हैं। ग्रामीण आबादी 72 प्रतिशत है। नेगीरटो मूल निवासी माने जाते हैं। इसके बाद इण्डोनेशिया और मलय लोग आकर बस गए। स्पेन के लोगों ने वहां लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया। अभी 91.5 प्रतिशत लोग ईसाई मलय है। मुसलमान 4 प्रतिशत है। बौद्ध बहुल देश में कुल 89 भाषाएं एवं बोलियां है। टेगालोग मातृभाषा है। अंग्रेजी बोलने वाला भारत और अमेरिका के बाद तीसरा बड़ा देश है। विद्यालयों में अंग्रेजी मुख्य माध्यम है। यह दूसरी आफिसियल भाषा भी है। शिक्षा का प्रतिशत 94.6 प्रतिशत है। 350 साल तक देश पर स्पेन ने राज्य किया। कुछ समय तक अमेरिका का अधिकार रहा। 1946 में यह देश आजाद

हुआ। स्पेन ने इस देश को ईसाई धर्म दिया तो अमेरिका ने जनतांत्रिक संस्थागत विकास किया। 1972 से 1986 तक देश में मार्शल-ला रहा और जनतांत्रिक परम्पराओं में अवरोध आया।

5.8.2 जनसंचार : उद्भव एवं विकास

5.8.2.1 समाचारपत्र

फिलीपीन्स के जनसंचार माध्यमों की जड़ें उपनिवेशवादी देश के भूतकाल से जमी हुई है। फिलीपीन्स का पहला समाचारपत्र 1811 में छपा। दुसरा 1821 में प्रकाशित हुआ। पहला दैनिक 1846 में निकला और तीन साल चला। 'मनीला टाईम्स' अंग्रेजी दैनिक 1898 में शुरू होकर 32 वर्ष तक प्रकाशन में रहा। इस समय सबसे पुराना पत्र जो अस्तित्व में है- मनीला बुलेटिन है जो 1900 में निकला। स्पेन एवं अमेरिका जैसे दो उपनिवेशवादी देशों ने समाचारपत्रो का प्रारम्भ किया। दूसरे महायुद्ध के बाद कुछ पत्र प्रकाशन में आए। कुछ युद्ध पूर्व के पत्र मनीला बुलेटिन एवं फिलीपीन्स हेराल्ड पुन: शुरू हुए। 1972 में मार्शल-लॉ लगने के बाद प्रेस ने शासन के भ्रष्टाचार, मानव अधिकारों के हनन आदि को लेकर गहरी आलोचना की। परिणाम यह हुआ कि मनीला बुलेटिन को छोड़कर सभी प्रमुख समाचारपत्र बन्द कर दिए गए। पत्रकारों को जेल एवं अन्य यातनाएं दी गई। जनसंचार माध्यमों की आवाज दबा दी गई लेकिन 'बी फोरम और फिलीपीन कॉलेजियन' ने 1980 के दशक में सरकारी माध्यमों के विरुद्ध एक विकल्प खड़ा किया। 1983 में 'जिरोक्स जर्नेलिज्म' और 'कैसेट जर्नेलिज्म' उभरने लगा जिसको अधिनायक वादी शासन के लिए दबाना कठिन हो गया।

1987 में संविधान' में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का प्रावधान रखा गया। इससे यहां स्वतन्त्र प्रेस के विकास का मार्ग खुला। परिणामस्वरूप 1997 में जहां 50 राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र छपने लगे जिनकी प्रसार संख्या 70 लाख (7 मिलियन) थी। 418 सामुदायिक पत्रों की स्थानीय प्रसार संख्या 7,55,873 हो गई। 1998 में देश के टॉप 10 समाचारपत्रों में पीपल्स जरनल का प्रसार 3,82,000 था। 'पीपल्स थौट' का प्रसार 3,66,000 था। मनीला क्रॉनिकल 3,00,000 और मनीला बुलेटिन का 2,80,000 था। अन्य इसी प्रकार के पत्रों में फिलीपीन्स स्टार, मनीला टाईम्स आदि थे। मेट्रो मनीला के दावे के अनुसार उसका प्रसार 7 मिलियन था। इस पत्र द्वारा 41 पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। प्रेस निजी उद्यमियों के हाथों में है

5.8.2.2 रेडियो

अमेरिकी शासन के समय 1922 में रेडियो शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले 6 व्यावसायिक केन्द्र थे। जापानियो के अधिकार के बाद एक स्टेशन को छोड़कर बाकी बंद कर दिए गए। दूसरे महायुद्ध के बाद रेडियो का प्रसार तेजी से हुआ और 30 स्टेशन हो गए।1972 के मार्शल-लॉ ने सारे माध्यमों को बन्द कर दिया। लेकिन सरकारी वॉयस ऑफ फिलीपीन्स कों जारी रखा गया।दो निजी स्टेशनों को भी संचालन की आज्ञा दी गई। हाल ही के वर्षों में रेडियो का व्यापक विस्तार हुआ है। 1998 फिलीपीन्स में 517 स्टेशन थे। 88 प्रतिशत लोगों तक इसकी पहुंच है।

5.8.2.3 टेलीविजन

फिलीपीन्स में रेडियो, टी.वी. और समाचारपत्रों को वहाँ जीवन एवं संस्कृति को सुनने देखने और पढने के दृष्टिकोण से देखा जाता है। टेलीविजन की शुरुआत 1953 में हुई। ज्यादा लागत, टी.वी. सेट्स की कमी आदि के कारण विकास की गति प्रारम्भ में धीमा रहा। 1966 में निजी चैनलों की संख्या बढ़कर 18 हो गई। 87 प्रतिशत लोगों की टी.वी तक पहुंच है। 32 कम्पनियां रेडियो और टेलीविजन का संचालन करती हैं। 116 टी.वी. स्टेशन्स में दो नेटवर्क ही ऐसे हैं जो 38 स्टेशनों का संचालन करते हैं। 1998 के आकड़ों के अनुसार विज्ञापनों का 53 प्रतिशत टी.वी. को तथा 15 प्रतिशत रेडियो को जाता है।

5.8.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी

इन्टरनेट का प्रारम्भ 'फिलनेट' द्वारा 1994 में हुआ। देश में इस समय 139 इन्टरनेट सेवा देने वाले सस्थान हैं। 75 प्रतिशत इन्टरनेट उपभोक्ताओं की 'वर्ल्ड-वाइड वैब' तक पहुँच है फीलीपीनी एक्सप्रेस, मनीला बुलेटिन, मनीला टाईम्स जैसे लगभग, दर्जन समाचारपत्र इन्टरनेट पर उपलब्ध हैं। फ़ीमेन एवं सनस्टार जैसे दैनिकों के इन्टरनेट संस्करण भी हैं।

5.8.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति

फिलीपीन्स में राजनैतिक उतार-चढ़ाव के बाद समाचारपत्रों एवं इलेक्ट्रोनिक माध्यमों के विकास में तेजी आई है। इसका कारण यह है कि अब वहां का समाज एक जनतांत्रिक एवं स्वतन्त्र उद्यमी समाज है। स्पेन के 377 साल के तथा अमेरिका के 46 साल के शासन के कारण वहां के समाज पर पश्चिमी प्रभाव पड़ा। प्रेस और अन्य जनसंचार माध्यमों पर निजी उद्यमियों का अधिकार तथा विज्ञापनों का समर्थन प्राप्त है। यह एक विकासशील देश है। सूचनातंत्र एवं जनसंचार माध्यमों को राष्ट्रीय विकास के सन्दर्भ में प्रोत्साहन देने 'की नीति है। फिलीपीन्स ही एक ऐसा देश है जहां संविधान द्वारा सूचना माध्यमों की राष्ट्र निर्माण के सन्दर्भ में श्रमिक को मान्यता दी गई है। प्रेस की सर्वाधिक स्वतन्त्रता है। समाचारपत्र सरकार के कटु आलोचक हैं तो प्रसारण माध्यमों का रुख नरम है।

5.8.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे

राजनैतिक एवं सम्पन्न लोगों के जनसंचार माध्यम उद्योग में लिप्त होने के कारण उनके हित प्रमुख रूप से संरक्षित होते हैं। एक स्वतन्त्र देश में जनता की पहुँच जनसंचार माध्यमों तक होगी चाहिए, लेकिन फिलीपीन्स पर यह बात लागू नहीं होती क्योंकि वहां जनसंचार माध्यमों पर उच्च वर्ग सम्पन्न वर्ग का एकाधिकार है। यौन एवं अहिंसा की ओर माध्यमों के झुकाव की वजह से बच्चों और युवाओं पर कुप्रभाव पड़ रहा है। यह देश की बड़ी समस्या है। जनसंचार माध्यमों के सन्दर्भ में ग्रामीण क्षेत्र उपेक्षित है। संविधान में एकाधिकार पर पाबंदी है लेकिन सरकार ने संविधान के प्रावधानों को परिभाषित करते हुए एकाधिकार को रोकने के कानून नहीं बनाए हैं

मीडिया

Media	MediaMetro Manila Broadsheets

Broadsheets	Date Founded	Circulation
Malaya	January 17, 1983	80,000
Manila Bulletin	February, 1990	200,000
Manila Times	October 11, 1945	200,000
Philippine Daily Inquirer	1985	240,000
Philippine Journal	October 21, 1942	131,000
Philippine Star	July 28, 1986	268,000
Manila Standard	1987	184,650
Today	January 10, 1994	152,268
The Evening Paper	-	50,000
Business World	July 27, 1987	54,936
Business Daily	October 31, 1994	78,218
The Businessman	-	10,000
Manila Chronicle	1946 revived 1986	80,000
Money Asia	-	52,000
Chinese Com. News	-	50,000
China Times	-	12,000
United Daily News	-	85,000
Diario Uno	-	50,200
Kabayan	-	20,000
Universal Daily	July 2, 1986	58,000
World News	June 1, 1981	88,000
The Philippine Post	-	-
The Journal	-	-
Total	**-**	**2,314,272**

Source: Philippine Media Factbook, 1998.

5.9 सिंगापुर में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी

5.9.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

सिंगापुर 20 द्वीपों का समूह है। इसका क्षेत्रफल 650 वर्ग किलोमीटर है जो अमेरिका के वाशिंगटन शहर से मात्र 3.5 गुणा बड़ा है। आबादी 3.5 मिलियन है, जिसमें 10 प्रतिशत विदेशी हैं । 76.4 प्रतिशत चीनी, 14.9 प्रतिशत भारतीय एवं शेष अन्य लोग है। अंग्रेजी कामकाज की भाषा है। चीनी, तमिल भी बोली जाती है। शत-प्रतिशत शहरी आबादी है। 92 प्रतिशत शिक्षा हैं। बौद्ध, इस्लाम, ईसाई,' हिन्दु, सिक्स, कन्फ़्यूशियस धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यहां पहले अंग्रेजों ने अपना व्यावसायिक केन्द्र बनाया। 1942 में जापानियों का अधिक हुआ। 1945 में फिर

अंग्रेजों के हाथ में आया। 1948 में साम्यवादी सत्ता आई। 1959 में स्वतन्त्र सरकार बनी। 1965 में सिंगापुर मलेशिया से अलग हुआ।

5.9.2 जनसंचार: उद्भव एवं विकास

5.9.2.1 समाचारपत्र

प्रिंस ऑफ वेल्स आईलैण्ड गजट सिंगापुर का पहला समाचारपत्र 1805 में निकला। भारतीय पत्र 1876 में छपा। विश्व युद्ध के समय जापानियों ने भी पत्र प्रकाशित किया। 1950 के दशक में चीनी प्रेस सक्रिय हुई। अंग्रेजी में सिंगापुर टाईगर स्टेन्डर्ड 1949 में शुरू हुआ। ईसाई एवं मुसलमानों ने धार्मिक लक्ष्य को लेकर प्रारम्भ में समाचारपत्र प्रकाशित किए। 1970 में सरकार ने दो अंग्रेजी पत्र बन्द कर दिए। चीनी भाषा के पत्रों को अंग्रेजी पत्रों का स्थान लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सिंगापुर में प्रेस को कानूनी दायरे में ही कार्य करना पड़ता है। यद्‌यपि संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का प्रावधान है। 8 स्थानीय समाचारपत्र हैं जिनका सयुक्त प्रसार एक मिलियन प्रतियां है। इसके अलावा 4500 विदेशी प्रकाशनों का भी प्रसार है। 'दी स्टेट्स टाईम्स' सबसे पुराना समाचारपत्र है।

5.9.2.2 रेडियो

वैसे सिंगापुर में रेडियो का आरम्भ 1936 में अंग्रेजों ने किया। 1980 में सिंगापुर ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन की स्थापना की गई। रेडियो कारपोरेशन सिंगापुर ने भी संचालन शुरू किया जो अधिकांश रेडियो स्टेशन के द्‌वारा प्रसारण करती है। 1997 में निजी संस्थानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का मार्ग प्रशस्त किया गया।

5.9.2.3 टेलीविजन

सिंगापुर में 1963 में टेलीविजन का आरम्भ हुआ। 1984 में सिंगापुर ब्रॉडकास्टिंग कआरेश्च ने चैनल-12 शुरू की। प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण को देखते हुए टेलीविजन के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। टेलीविजन कार्पोरेशन सिंगापुर ने टी.वी. सेवाओं का विस्तार करना प्रारम्भ किया। 1997 में एवी.एन., बी.बी.सी., ई.एस.पी.एन., एम.टी.वी. जैसी 26 कम्पनियों के प्रसारण होने लगे।

5.9.3 नई सूचना प्रौद्‌योगिकी

इन्टरनेट का 1994 में चलन होने लगा। 1995 में नेशनल इन्टरनेट वेबसाईट चालू करके दुनिया का इस सन्दर्भ में सिंगापुर पहला देश हो गया। इन्टरनेट की सेन्सरशिप के लिए लाईसेन्स प्रणाली चालू की गई। 1998 में सिंगापुर में पचास प्रतिशत लोगों के पास कम्प्यूटर हो गए। जापान, ताईवान, दक्षिण कोरिया तथा हांगकन के बाद 5,00,000 इन्टरनेट उपभोक्ताओं के साथ सिंगापुर पांचवें नम्बर का देश हो गया। केबल टी.वी. का प्रसार भी बढ़ा।

5.9.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति

सिंगापुर में जातीय एवं भाषाई विविधता के सन्दर्भ में जनसंचार माध्यमों का विकास हुआ है। घने नगरीय आवास के कारण सिंगापुर वासी जनसंचार माध्यमों के सन्दर्भ में उत्साही

उपभोक्ता हैं। कई अन्तर्राष्ट्रीय माध्यमों का भी वहां जमघट हो गया है। सिंगापुर में माध्यमों का 'डेवलपमेन्टल मॉडल' स्वीकार किया गया है। सरकार को यह एहसास हुआ है कि असुविधाजनक खबरों को रोकना और इन्टरनेट जैसे साधनों को नियन्त्रण में रखना संभव नहीं है। खबरों को दबाने का जमाना पीछे छूटता जा रहा है। अत: सरकार को अब नई प्रौद्योगिकी के साथ काम करना होगा। इसे दबाना मुमकिन नहीं है। सरकारों के लिए स्वाधिकार के द्वारा माध्यमों पर नियन्त्रण करने की प्रवृत्ति को सूचना प्रौद्योगिकी तेजी से झुठलाती जा रही है। अत: टेकनोलॉजी के विकास के साथ गति में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

5.9.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे

एशियाई देशोंमे अन्य कुछ देशों की तरह प्रशिक्षित मानव संसाधनों की सिंगापुर में भी कमी है। सिंगापुर में माध्यमों के लिए बनाए गए कानूनों और नियमों तथा जागरूक जनता द्वारा माध्यमों को आधुनिक स्तर पर लाने की ललक के बीच के तनाव की समस्या का समाधान एक बड़ा मुद्दा है। प्रेस स्वतन्त्रता के वर्गीकरण के अनुसार सिंगापुर की प्रेस स्वतन्त्र नहीं है। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था और बाजार की प्रतिस्पर्द्धाओ के बीच माध्यमों पर नियन्त्रण करना दुविधा की स्थिति है। सरकार की सोच बदलने लगी है और यह माना जाता है की सूचना युग सेन्सरशिप का उपयोग करना खतरे से भरा काम है। इसलिए 20वीं सदी के अन्तिम दशक में माध्यमों की स्वतन्त्रता की धीमी प्रक्रिया शुरू हुई है। इससे आशा जागती है कि 21वीं सदी में मीडिया का ढांचा बदलेगा और माध्यमों को स्वतन्त्रता मिल सकेगी।

Media Daily Newspapers Singapore

Newspaper	Year Estiblished	Frequency	Language	Circ'n	Per 1,000 Population
The Straits Times	1845	Daily a.m	English	369,773 (390,000)	123.81
Lianhe Zaobao	1983	Daily a.m	Chinese	202,063 (201,000)	27.65
Lianhe Wanbao	1983	Daily p.m	Chiense	129,715 (135,000)	43.43
Shin Min Daily	1967	Daily p.m	Chinese	112,497 (118,000)	37.66
The New Paper	1988	Daily p.m	English	107,080 (111,000)	35.85
Berita Minggu	1960	Sunday	Malay	67,377	22.56
Berita Harian	1957	Daily a.m	Malay	56,438 (60,000)	18.89
Business Times	1976	Daily a.m	English	34,446 (32,000)	11.53
Tamil Murasu	1935	Daily a.m	Tamil	8,162 (9,000)	2.73

Source: Goonasekera & Holaday, 1998, p. 16; SRS Media Index Circulatin data for 1998 appear in parentheses (WAN, 1999).

5.10 थाईलैण्ड में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी

5.10.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

थाईलैण्ड 5,13,115 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी सीमाएं म्यांमार, कम्बोडिया एवं मलेशिया से लगी हुई हैं। थाईलैण्ड की 60.6 मिलियन आबादी का 10 प्रतिशत लोग बैंकाक में रहते हैं। 75 आबादी 'थाई' है, 14 प्रतिशत चीनी एवं बाकी 11 प्रतिशत है। 95 प्रतिशत बौद्ध, 3.8 प्रतिशत मुसलमान, 0.5 प्रतिशत ईसाई एवं 0.1 प्रतिशत हिन्दु है। बैंकाक में चीनी एवं भारतीय व्यवसाइयों की संख्या नगर की कुल आबादी का 10 प्रतिशत है। 'थाई' राष्ट्रीय भाषा है। साक्षरता का प्रतिशत 94.1 है। 1932 तक वहां पूर्ण राजशाही शासन व्यवस्था थी। इसके बाद संवैधानिक राजशाही आई। 1992 तक सेना का शासन रहा। 1997 में राजनैतिक दलों की मिलीजुली सरकार बनी।

5.10.2 जनसंचार : उद्भव एवं विकास

5.10.2.1 समाचारपत्र

थाईलैण्ड का पहला समाचारपत्र 'बैंकाक रिकार्डर' 1844 में छपा। शिक्षा के उच्च स्तर एवं विदेशी व्यापार के कारण लोगों का समाचारपत्रों के प्रति गहरा रुझान रहा है। पूर्ण राजशाही के बावजूद समाचार माध्यमों के लिए स्वतन्त्रता एवं विकास के अवसर आते रहे। 1925-32 की अवधि में तत्कालीन नरेश के शासन में 60 दैनिक समाचारपत्रों एवं 160 अन्य पत्रों का प्रकाशन होता था। 1945 के बाद एक बार समाचारपत्रों को अधिक आजादी दी गई। परिणाम यह हुआ कि प्रेस का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना होने लगा। 1958 में थाई पत्रकारिता के लिए फिर काला युग का आ गया। 1973 में छात्र क्रान्ति के अधिनायकवादी शासन का तख्ता पलट दिया। प्रेस ने आजादी का जश्न मनाया। तीन साल स्वतन्त्रता का उपयोग किया। लेकिन पुन: प्रेस की आजादी का दुरुपयोग होने लगा। अश्लील चित्र एवं कॉलम छपने लगे। भ्रष्टाचार फैलने लगा। मुफ्त खाना और सफेद लिफाफों में पत्रकारों को नगद उपहार मिलने लगे। इस प्रकार आचरण के स्तर में गिरावट आ गई। लेकिन इस गैर दायित्वपूर्ण पत्रकारिता का उस समय फिर अन्त आ गया जब 1976 में सेना ने खूनी सत्ता संघर्ष अभियान में जीत प्राप्त की। समाचारपत्रों के बन्द होने का सिलसिला चलने लगा। 1992 में सेना के आधिपत्य समाप्त होने का श्रेय 1992 मे पत्रकारिता को मिला। लेकिन समाचारपत्र जगत् के उत्थान और पतन की घटनाओं ने सबक सिखाए और व्यावसायिक स्तर के साथ प्रेस ने सावधानी से काम करना प्रारम्भ किया। 1996 में वहाँ 30 दैनिक समाचारपत्र थे। बैंकाक पोस्ट, जो 1945 में शुरू हुआ, की प्रसार: संख्या 65,000 थी।

5.10.2.2 रेडियो

रेडियो की थाईलैंड में 1932 में शुरूआत हुई। सरकार ने 1932 में थाई लोगों को जनतान्त्रिक शिक्षा प्रदान करने के लिए रेडियो का उपयोग करना आरम्भ किया। रेडियो का उपयोग निजी संस्थानों के माध्यम से व्यवसायिक स्तर पर होने लगा, लेकिन संचालन में सरकार

का पूर्ण नियन्त्रण रहा। 1999 में वहाँ 523 रेडियो स्टेशन थे। 1992 के बाद रेडियो के कार्यक्रमों का स्तर मजबूत हु आ और सरकार की आलोचना भी होनी लगी।

5.10.2.3 टेलीविजन

टेलीविजन का राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करने के लिए तत्कालीन सरकार ने सरकार व निजी क्षेत्र के सयुक्त सहयोग से थाई टेलीविजन कम्पनी की स्थापना की तथा 1955 में चैनल-4 बैंकाक में शुरू हु ई। 1967 से रंगीन प्रसारण प्रारम्भ होने लगा। टी.वी. सरकार का एकाधिकार रहा। थाईलैण्ड में 6 टी.वी. स्टेशन है। इन्टरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग कार्पोरेशन एवं यू.टी.वी. केवल नेटवर्क को लगभग पूरी स्वायत्तता है।

5.10.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी

1998 में देश में लगभग 12लाख (1.2 मिलियन) कम्प्यूटर तथा 59,718 इन्टरनेट थे। इन्टरनेट की वहां 1987 में ही शुरूआत हो गई थी। आर्थिक संकट के बावजूद देश में राष्ट्रीय स्तर पर इन्टरनेट के उपयोग की योजना क्रियान्वयन की। सरकारी एजेन्सियों के पास अपनी वेबसाईट्स है जहां ताजा सूचना का आदान-प्रदान किया जाता है।

5.10.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति

थाईलैण्ड सरकार जनसंचार माध्यमों के विकास के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन तो देती है लेकिन ये माध्यम सरकार के नियन्त्रण से मुक्त नहीं है। प्रेस को अधिक स्वतन्त्रता देने एवं प्रोत्साहन देने की कोशिशें होने लगी है। प्रेस की आजादी पर प्रहार करने वाले कानूनो को संशोधित करने के प्रयास जारी हैं। समाचारपत्र भी मुक्त विश्व अर्थ-व्यवस्था एवं प्रतिस्पर्द्धा के आधुनिक माहौल में व्यावसायिकता का स्तर ऊँचा उठाने एवं चरण में सुधार लाने के लिए प्रयासरत है।

5.10.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे

1977 के संविधान में अभिकर्त्ता की स्वतन्त्रता के अधिकार द्वारा जनसंचार माध्यमों को यह अवसर दिया गया है कि वे 'पीत पत्रकारिता' से मुक्त होकर जनता के लिए वॉचडॉग' की भूमिका अदा करने के लिए अग्रसर है। दायित्व के साथ आचरण को बेहतर बनाए।

Media	**Daily Newspapers (Thai)**
	Circulation
Baan Muang	200,000
Baan Muang Printing	
1 Soi Pleummanee Vibhavadi-Rangsit Chatujak	
Bangkok 10900	
Daily News	750,000
Si-Phya Publishing	
1/4 Vibhavadi-rangsit Don Maung	
Bangkok 10210	
Khao Sod	400,000

Khao Sod Co., Ltd
40/9 Tessabanimitmai Ladyao Chatujak
Bangkok 10900

Krungthep Turakij 75,882
Nation Multimedia group
44 Moo 10 Banga-Trad Km 4.5 Prakhanong
Bangkok 10260

Matichon Daily 400,000
Matichon
12, Tessaban-Narumarn Prachanivej 1 Chatujak
Bangkok 10900

Naew Na 200,000
Neawna Newspaper
96 Moo 7 Vibhavadi-Rangsit BangKhen

Poojadkarn 260,000
The manager Media Group
101/1 Baan Pra-Arthit Chanasongkham PranaKhon
Bangkok 10210

Siam Rath 100,000
Saim Rath
6th Bldg 12 Rajdamnoen
Bangkok 10200

Siam Sports Daily 200,000
Siam Sports Syndicate
1776-1784 Rama IV Kasemrat Prakhanong
Bangkok 10110

Sports World Daily 180,000
Wattachak Public
88 boromrajachonnee Taling Chan
Bangkok 10170

Sports Game Daily 98,000
Wattachak Public
88 boromrajachonnee Taling Chan
Bangkok 10170

Thai Post 30,000
Thai General Group
12/F1 Sorachai Bldg
23/15-19 Ekamai Sukhumvit 63 Klontoey
Bangkok 10110

Thai Rath 1,000,000
1 Vibhavadi-Rangsit Ladyo Chatujak

Bangkok 10900

Wattachak Daily 200,000

Wattachak Public

88 boromrajachonnee Taling Chan

Bangkok

Daily Newspaper (Chinese) 90,000

Kia Hua Tong Ngun (Sirinakorn)

Sirinakorn Newspaper

108 Suapa Pomprab

Bangkok 10100

Sing Sian Yit Pao 90,000

Sing Sian Yit Pao

267 New Road

Bangkok 10100

Tong Hua Yit Pao 90,000

Tong Hua Newspaper

877-879 Charoenkrung Talad Noi Samphantawong

Bangkok 10100

The Universal Daily News 40,000

Universal Press

21/a Charoenkrung Wangburapa Phirom Prankorn

Bangkok 10200

Daily Newspapers (English)

Bangkok post 65,000

The Post Publishing

136 Na Ranong Off Sunthorn Kosa Klongtoey

Bangkok 10110

Business Day 40,000

Business Day

22/F1 Olympia Thai Tower

444 Ratchadapisek Smsennok Huaykwang

Bangkok 10320

Nation 55,000

Nation Multimedia Group

44 Mo 10 Bangna-Trad Km. 4.5 Prakhanong

Bangkok 10260

Television Channels

Bangkok Entertainment (Thai TV Color Channel 3)

1126 Vanich Bldg New petchburi

Bangkok 10400

Bangkok Broadcasting & TV (channel 7)

998/1 Phaholyothin Chatujak
Bangkok 109000

Mass Communications Organization of Thailand
(Thai TV Color Channel 9)
63/1 Rama IX HuavkWang
Bangkok 10320

Royal Thai Army Television station (TV 5)
210 Phaholyothin Sanmpao
Bangkok 10400

Television of Thailand (channel 11)
New Petchburi Bengkok 10310

Independent Television (ITV)
SCB Park Plaza, Tower 2 West
18 Ratchadapisek Road
Bangkok 10900

5.11 वियतनाम में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी

5.11.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

उत्तर में चीन, दक्षिण में कम्बोडिया एवं लाओस तथा पूर्व में दक्षिण 'चाईना सी' की सीमाओं से घिरा वियतनाम 3,25,360 वर्ग किलोमीटर में फैला है। देश के मध्य भाग में पहाड़ी क्षेत्र देश को दो भागों उत्तर वियतनाम एवं दक्षिण वियतनाम में बाटता है। 40 प्रतिशत भाग जंगलों से आच्छादित है तथा 22 प्रतिशत भू-भाग खेती करने के लायक है। अनुमानत: आबादी 77.3 मिलियन है जिसमें 21 प्रतिशत शहरी आबादी शामिल है। 91.9 प्रतिशत साक्षरता है। 85 से 90 प्रतिशत वियतनाम एवं 3 प्रतिशत चीनी रहते हैं तथा बौद्ध, रोमन, कैथोलिक, इस्लाम, प्रोटेस्टेन्ट आदि. धर्मों के लोग अनुयाई है। वियतनामी भाषा देश में कामकाज की भाषा है। लेकिन फ्रेन्च, अंग्रेजी, चीनी, खमेर एवं अन्य आदिवासी भाषाएँ प्रचलित हैं। हो-ची मिन्ह नगर (साईगोन) एवं देश की राजधानी हनोई सबसे बड़ा शहर है।

वियतनाम के उपनिवेशवादी विरासत का लम्बा इतिहास है। ईसा से 11 वर्ष पहले चीन ने वियतनाम पर कब्जा किया। 1937 में चीन से आजाद हुआ। पुन: चीनी शासन हो गया। 1867 से 1945 तक फ्रांसीसियों का शासन रहा। फिर जापानी आए और पुन: फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया। 1954 में फ्रांस से उपनिवेश को मुक्ति मिली। 1961 से 1973 तक युद्ध के समय अमेरिका का हस्तक्षेप रहा। साम्यवाद एवं स्वतन्त्र विचारधाराओं की लड़ाई के बाद 1975 में कम्यूनिस्ट शासन हुआ। 1976 में स्पेशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की घोषणा हुई तथा देश फिर से एक हो गया।

5.11.2 जनसंचार: उद्भव एवं विकास

5.11.2.1 समाचारपत्र

वियतनाम का पहला समाचारपत्र 1860 में छपा। यह फ्रेंच भाषा में था। वियतनामी भाषा का पत्र 1865 से शुरू हुआ। 1892 में उत्तरी वियतनाम से भी समाचारपत्र निकला फ्रेंच उपनिवेशवाद के समय समाचारपत्र उपनिवेशी शासन के हितों की पूर्ति के लिए हथियार के रूप में प्रयुक्त होते थे। समाचारपत्रों के सन्दर्भ में दोहरी नीति का पालन किया जाता था। नियमों के द्वारा फ्रेंच नागरिकों द्वारा फ्रेंच भाषा के पत्रों के प्रकाशन को प्रोत्साहन दिया जाता था।

1920 से 1940 की अवधि में फ्रांस की उपनिवेशवाद नीतियों के विरोध के स्वर उभरने लगे। वियतनाम वासियों मैं राष्ट्रीयता की सोच बढ़ने लगी। शासन की नीति में यद्यपि कुछ लचीलापन आया और 1938 में वियतनामी एवं चीनी भाषा के समाचारपत्र पनपने शुरु हुए लेकिन एक साल बाद स्वतन्त्र वातावरण समाप्त हो गया और समाचारपत्रों पर पाबंदियां लगा दी गईं। इस काल में कुछ राष्ट्रीय पत्र उभरे थे।

इसके बाद 1945 में 7 दैनिक समाचारपत्र थे। देश के माध्यमों पर चीनी, फ्रांसीसी एवं अंग्रेजी उपनिवेश की परछाइयाँ स्पष्ट झलकती हैं। अधिकांश समाचारपत्रों की भाषा उपनिवेशवादी देशों की भाषाएँ थीं। मुद्रण तकनोलॉजी के विकास में फ्रांस ने योग दिया। मुख्य पृष्ठ पर सम्पादकीय छापने की परंपरा थी वियतनाम में समाचारपत्रों का स्वरूप संगठित था। पत्रों के प्रकाशन में स्थायित्व था और उनका प्रमुख ध्यान साम्यवादी विचारधारा पर टिका हुआ था। समाचारपत्र शासन के पूर्ण नियन्त्रण में थे। दक्षिण वियतनाम में समाचारपत्र असंगठित अवस्था में थे तथा सरकार के दबाव, सेन्सरशिप, बन्द आदि के शिकार थे। 1954 से 1975 तक दो प्रकार की समाचारपत्र प्रणाली का विकास हुआ। 1976 में उत्तरी- दक्षिण वियतनाम के मिलने और पुन: एक देश के रूप में उभरने के साथ ही उत्तर एवं दक्षिण के समाचारपत्रों में भी एकरूपता आने लगी। उस समय दक्षिण वियतनाम में काफी प्रकाशन ते तथा उत्तरी वियतनाम से 139 पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी। इस समय कुल 42 पत्र-पत्रिकाएं ऐसी हैं जिनमें 38 का प्रकाशन 1980-90 के बीच हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशन भी अब उपलब्ध है।

5.11.2.2 रेडियो

वॉयस ऑफ वियतनाम ने पहला प्रसारण 1945 में किया। 1960 में इसके नौ प्रसारण केन्द्र थे। 11976 में सरकार ने रेडियो हनोई आरम्भ किया। देश में फ़्रांस ने रेडियो की शुरूआत की थी लेकिन देश के दक्षिण में रेडियो सेवाओं का आधुनिकीकरण अमेरिका ने 1956 से 1972 की बीच पूंजी नियोजन करके किया। वियतनाम में रेडियो सरकार के अधीन है। 1991 में 288 स्टेशन एवं 8365 रिले केन्द्र थे। रेडियो की पहुँच 70 से 80 प्रतिशत आबादी तक है।

5.11.2.3 टेलिविजन

वियतनाम में टेलीविजन का प्रसारण 1966 में हुआ। अमेरिका ने उपकरण, प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की। 1968 में 20 प्रतिशत अमेरिकी सिपाहियों के पास टी.वी. सेट थे। 1970 में 75 प्रतिशत आबादी तक टी.वी. की पहुंच हो गई यद्यपि 40 प्रतिशत लोगों के पास ही सेट

थे। रेडियो की तरह टी.वी. भी सरकारी नियन्त्रण में है। टेलीविजन वियतनाम हनोई से अपने तीन चैनल्स से प्रसारण करता है।

5.11.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी

1980 के दशक में वियतनाम में कम्प्यूटर का चलन शुरू हुआ। 1996 में 2,50,000 कम्प्यूटर थे। 1997 में यह संख्या 3,50,000 तक पहुँच गई। 70 प्रतिशत कम्प्यूटर का आयात किया जाता था। 1993 में सरकार ने सूचना तकनोलॉजी कें विकास की पहल की। 1997 में इन्टरनेट से देश का सम्बन्ध हुआ। इन्टरनेट का उपयोग करने वालों की संख्या 11,000 थी।

5.11.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति

1988 से सरकार ने कुछ माध्यमों में निजी क्षेत्र को छूट देने की प्रवृत्ति के संकेत देना आरम्भ किया। यद्यपि जनसंचार माध्यमों पर सरकार ने अपना वर्चस्व कायम रखा। बाजार से प्रेरित अर्थव्यवस्था के व्याकरण माध्यमों की गुणवत्ता बढ़ाने एवं रेडियो के राष्ट्रीय विकास को गति देने वाले प्रभावपूर्ण साधन के रूप में उपयोग करने के प्रयास जारी है। लेकिन इस सम्बन्ध में कम्यूनिकेशन का मौलिक ढांचा मजबूत करने की दिशा में स्पष्ट नीति अपनाए जाने की आवश्यकता है।

5.11.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे

विकासशील देशों की तरह वियतनाम के संचार माध्यमों के समक्ष कई समस्याएं हैं। लोगों की आय कम होना, समाचारपत्रों की पाठक संख्या में कमी, टेकनोलॉजी एवं टेकनोलॉजी-विशेषज्ञता की कमी तथा आर्थिक विकास का निम्न स्तर कुछ ऐसे कारण हैं जो जनसंचार माध्यमों के विकास मार्ग में बाधा डालते हैं। विद्युत आपूर्ति में कमी, सड़क एवं परिवहन साधनों के सम्बन्ध में कठिनाइयां एवं ढांचागत सुविधाओं का अभाव आर्थिक एवं माध्यमों के विकास की गति धीमी रही है।

देश में साम्यवादी शासन एवं अर्द्ध स्वतन्त्र बाजार की दोहरी प्रणाली के कारण भी जनसंचार माध्यमों के सामने अनेक कठिनाइयां आई हैं। देश के स्वतन्त्र बाजार व्यवस्था की ओर झुकाव के कारण जनसंचार माध्यमों की गुणवत्ता, कुशल मानव माध्यमों का विकास एवं अधिक स्वतन्त्र वातावरण के निर्माण की चुनौतियाँ देश के सामने हैं।

Media **Daily Newspapers:**

Name	Date established	Place of publication	Language	Circulation
Le Courrier Vietnam	N.A	Hanoi	French	N.A
Hanoi Moi	1976	Hanoi	Vietnamese	35,000
Nhan Dan	1946	Hanoi	Vietnamese	180.000
Quan Dot Nhan Dan	1950	Hanoi	Vietnamese	60.000
Vietnam News	1991	Hanoi	English	10,000

Saigan Giai Phong	1975	Ho Chi Minh	Vietnamese	100.000
Saigon Times	1995	Ho Chi Minh	English	N.A

Source: The Europa world yearbook 1997, *Nhan Dan Websit

5.12 सारांश

प्रस्तुत इकाई में दक्षिण एशिया के दस-ब्रुनोई दारूसलम, कम्बोडिया, इन्डोनेशिया लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन्स, सिंगापूर, थाईलेण्ड एवं वियतनामके जनसंचार माध्यमों समाचारपत्र, रेडियो एवं टेलिविजन पर प्रमाणिक रूप से प्रकाश डाला गया है। साथ ही वहां की नई सूचना प्रोद्योगिकी तथा सरकार की जनसंचार माध्यमों के प्रति नीति की विवेचना की गई है।

आशा की जाती है की शीशार्थी इस इकाई के अध्यन के पश्चात दक्षिण पूर्व एशिया के जनसंचार माध्यम के संबंध में व्यापक रूप से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

5.13 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. पी.एच. लिम्प: (1992) सिंगापूर, मलेशिया एंड ब्रुनेई: इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़
2. युसुफ (1998): मीडिया सिस्टम इन ब्रुनेई दारूसलाम: यूनिवरसिटि
3. एच.सी. मेहता (1997): कम्बोडिया प्रेस अंडर सिक्स रियापमस मीडिया एशिया
4. वर्ल्ड फेक्ट बूक (1998): कम्बोडिया
5. एल लुआरसो (1998): लिब्रेशन ऑफ इन्डोनेशिया प्रेस
6. ई.जे. सिंगारा (1989): इन्डोनेशिया प्रेस सिस्टम इन एशियन स्टेट्स सिंगापूर
7. के. कोंगवोंगसा (1996): मीडिया डेव्लपमेंट इन दी काओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक
8. ए.आर. आखी (1990): कम्यूनिकेशन डेव्लपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स इन एशिया; ए.एस.आई.सी. सिंगापूर
9. एल. आर. सुस्मात (199): प्रेस फ़्रीडम, न्यूज ऑफ सेच्युरी: न्यूयार्क
10. वर्ल्ड फेक्ट बुक (1999): फिलीपीन्स: वाशिंटन
11. सिंगापुर (1997): मीडिया गाईड: सूचना एवं कला मंत्रालय: सिंगापुर
12. थाईलेण्ड प्रेस सिस्टम इन एशियन स्टेट्स, सिंगापुर
13. ए. मार्शल (1999): वियतनाम, एशियन एडवर्टाइजिंग एण्ड मार्केटिंग
14. यूनेस्को स्टेटिकल ईयर बुक, युनेस्को प्रेस

5.14 निबन्धात्मक प्रश्न

1. 'ब्रूनेई (दरूसलम) में पत्रकारिता एक व्यवसाय (प्रोफेसन) के रूप में विकसित नहीं हो पाई है'। समीक्षा कीजिए।
2. 'कम्बोडिया में प्रेस क स्वतन्त्रता नहीं है'। इस मत की विवेचना कीजिए।
3. इन्डोनेशिया के जनसंचार माध्यमों पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए।
4. 'लाओस के लोग अपने जनसंचार माध्यमों के विकास के द्वारा अपने भविष्य की संरचना करने के इच्छुक है'। इस कथन की समीक्षा कीजिए।

5. मलेशिया में जनसंचार माध्यमों की दशा-दिशा पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए।
6. फिलीपीन्स की नई सूचना प्रोद्योगिकी एवं जनसंचार माध्यमों में सरकार की नीति पर प्रकाश डालिए।
7. 'प्रेस स्वतन्त्रता वर्गिकरण के अनुसार सिंगापुर की प्रेस स्वतंत्र नहीं है। आप इस मत से कहां तक सहमत है। विवेचना कीजिए।
8. 'थाईलेण्ड की प्रेस जनता के लिए 'अग्रसर' की भूमिका अदा करने के लिए अग्रसर है'। सिद्ध कीजिए।
9. वियतनाम के जनसंचार माध्यमों के समक्ष क्या समस्याएं है। प्रकाश डालिए।

इकाई 6 एशिया में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी-3 (दक्षिण एशिया) Media in Asia-3 (East Asia)

इकाई की रूपरेखा

6.0 उद्देश्य
6.1 प्रस्तावना
6.2 चीन में जनसंचार और नई-प्राद्योगिकी
6.2.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य
6.2.2 जनसंचार : उद्भव एवं विकास
6.2.2.1 समाचारपत्र
6.2.2.2 रेडियो
6.2.2.3 टेलीविजन
6.2.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी
6.2.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति
6.2.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे
6.3 हांगकांग (चीन) में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी
6.3.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य
6.3.2 जनसंचार : उद्भव एवं विकास
6.3.2.1 समाचारपत्र
6.3.2.2 रेडियो
6.3.2.3 टेलीविजन
6.3.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी
6.3.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति
6.3.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे
6.4 मकाऊ (चीन) में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी
6.4.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य
6.4.2 जनसंचार: उद्भव एवं विकास
6.4.2.1 समाचारपत्र
6.4.2.2 रेडियो
6.4.2.3 टेलीविजन
6.4.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी
6.4.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति
6.4.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे

6.5 जापान में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी

6.5.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

6.5.2 जनसंचार : उद्धभव एवं विकास

6.5.2.1 समाचारपत्र

6.5.2.2 रेडियो

6.5.2.3 टेलिविजन

6.5.3 नई सूचना प्रोंद्योगिकी

6.5.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति

6.5.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे

6.6 उत्तरी कोरिया में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी

6.6.1 राष्ट्रीय पीरप्रेक्ष्य

6.6.2 जनसंचार : उद्भव एवं विकास

6.6.2.1 समाचारपत्र

6.6.2.2 रेडियो

6.6.2.3 टेलीविजन

6.6.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी

6.6.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति

6.6.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे

6.7 दक्षिण कोरिया में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी

6.7.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

6.7.2 जनसंचार : उद्भव एवं विकास

6.7.2.1 समाचारपत्र

6.7.2.2 रेडियो

6.7.2.3 टेलीविजन

6.7.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी

6.7.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति

6.7.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे

6.8 मंगोलिया में जनसैचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी

6.8.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

6.8.2 जनसंचार: उद्भव एवं विकास

6.8.2.1 समाचारपत्र

6.8.2.2 रेडियो

6.8.2.3 टेलीविजन

6.8.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी

6.8.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति
6.8.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे
6.9 ताईवान में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी
6.9.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य
6.9.2 जनसंचार : उद्भव एवं विकास
6.9.2.1 समाचारपत्र
6.9.2.2 रेडियो
6.9.2.3 टेलीविजन
6.3.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी
6.9.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति
6.9.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे
6.10 सारांश
6.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें
6.12 निबन्धात्मक प्रश्न

6.0 उद्देश्य

- प्रस्तुत इकाई में पूर्वी एशिया के देशों-चीन, हांगकांग (चीन), मकाऊ (चीन) जापान उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया तथा ताईवान के जनसंचार माध्यमों पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला गया है।
- सूचना युग में पूर्वी एशियाई देश चीन, मकाऊ, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया, ताईवान एवं हांगकांग किस प्रकार समय के अनुसार विकासित हैं या यहां पीछे रह गये हैं, इस इकाई के अध्ययन से आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों तथा पूर्वी एशियाई राज्यों के जनसंचार माध्यमों के उद्भव एवं विकास की तुलनात्मक विवेचना कर सकेंगे।
- पूर्वी एशिया के देशों के विभिन्न संचार माध्यमों के विकास की समस्याओं एवं स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नई सूचना प्रौद्योगिकी से भी अवगत हो सकेंगे।
- किसी भी देश में जनसंचार माध्यमों के विकास एवं प्रगति के सन्दर्भ में उसकी भूमिका का विश्लेषण कर सकेंगे।
- नई सूचना प्रौद्योगिकी की विकास मात्रा में किस प्रकार पूर्वी एशिया के विभिन्न देश आगे बढ़ रहे हैं? इस प्रश्न की तह में भी आप जा सकेंगे। साथ ही पूर्वी एशिया की 'मीडिया ' के बारे में आपकी जानकारी व्यापक होगी।

6.1 प्रस्तावना

दक्षिण एशिया के सात देशों तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के दस देशों के जनसंचार माध्यमों के उदभव एवं विकास, नई सूचना कनोलॉजी के प्रसार, स्वतन्त्रता के प्रसार, स्वतन्त्रता के मुद्दों एवं विभिन्न देशों की इस सन्दर्भ में नीतियों का अध्ययन करके आप यह भली भांति परिचित हैं

कि एशिया में सदियों के अंधेरों को पार करके किस प्रकार विभिन्न जनसंचार माध्यम अपने अस्तित्व को कायम रखने में समर्थ हुए हैं। सरकार की नीतियों के कारण किस प्रकार जनसंचार माध्यमों के सामने कठिनाइयां और विपत्तियां आई हैं। आप यह भी जान चुके होंगे कि स्वतन्त्रता के बिना जनसंचार माध्यम अपनी विकासोन्मुक्खी भूमिका का निर्वाह करने में असमर्थ रहते हैं।

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप पूर्वी एशिया के आठ देशों के जनसंचार माध्यमों के उद्भव विकास एवं उनकी भावी दिशा के बारे में परिचय प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही एशिया महाद्वीप के 25 राष्ट्रों के जनसंचार माध्यमों का तुलनात्मक विवेचन भी कर सकेंगे। इस इकाई के द्वारा आप यह जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि भौगोलिक परिस्थितियों, जनसख्या, शिक्षा, अर्थव्यवस्था एवं राजनैतिक व्यवस्थाओं के प्रसंग में जनसंचार माध्यमों का विकास मार्ग किस प्रकार प्रभावित होता है। आप ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी जनसंचार माध्यमों के उद्भव एवं विकास का विश्लेषण करने मैं समर्थ होंगे।

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन से आप यह भी ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे कि विभिन्न देशों में पत्रकर्ग़रेता की शिक्षा-प्रशिक्षण एवं कुशलता के अभाव में सूचना प्रौद्योगिकी या जनसंचार माध्यमों को गति देने में कितनी कठिनाइयां आती हैं और जो देश सचेत हैं, वे जनसंचार माध्यमों की भूमिका का उपयोग किस प्रकार देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास कौ गति देने की दिशा में करते हैं।

6.2 चीन में जनसंचार और नई सूचना -प्रौद्योगिकी

6.2.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

चीन का क्षेत्रफल अत्यन्त विशाल है। चीन की सीमाएं 14 देशों से लगी हुई हैं। अधिकांश भू-भाग पहाड़ी एवं रेगिस्तानी है। चीन की आबादी एक अरब, 24.7 लाख है। देश में 53 जाति समूह हैं लेकिन अधिकांश चीनी है, जो हॉन या चीनी भाषा बोलते हैं। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रभाव है लेकिन इस्लाम, ईसाई आदि धर्मो को मानने वाले लोग भी रहते हैं। साक्षरता का प्रतिशत 84 है। चीन के पांच हजार वर्ष के इतिहास में राजाओं का शासन लगभग दो हजार वर्ष तक चला। 1949 में चीन की साम्यवादी पार्टी ने 'पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना' की स्थापना की। 1957 से 1966 का दशक विध्वंसकारी रहा। 1976 में सांस्कृतिक क्रान्ति हुई। 1978 में चीन ने सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाया।

6.2.2 जनसंचार: उद्भव एवं विकास

6.2.2.1 समाचारपत्र

वांगवंश के शासनकाल (618-907) में अधिकत गजट रिपोर्ट के रूप में निकला जिसे चीन का पहला समाचार पत्र कह सकते है। यह सन् 1911 तक जारी रहा। लेकिन आधुनिक अर्थों में एक अंग्रेज मिशनरी ने 1815 में समाचारपत्रों शुरू किए। 1840 के 'ओपियन वार' के 50 वर्ष के बाद की अवधि में विदोशेयो ने 300 समाचारपत्रों का एवं शंघाई भाषा में प्रकाशन किया। 1895-98 में 94 समाचारपत्र प्रकाशित हुए। 'शी व बाओ' सबसे प्रभाव शाली समाचारपत्र था। 1905 में 160 क्रान्तिकारी विचारों के पत्र शुरू हुए चिन में समाचारपत्रों के प्रारम्भिक विकास से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि प्रेस और राजनीति (प्रोलिटिक्स) का नजदीकी संबंध रहा है।

राजनीतिज्ञों द्वारा चीन में प्रेस का इस्तेमाल प्रारम्भ से ही अपने विचारों और हितों का प्रसार करने के लिए किया गया। वह विरासत या प्रवृत्ति साम्यवादी क्रांति, राजनैतिक संघर्षों एवं आर्थिक विकास के प्रोत्साहन आदि विभिन्न पड़ावों को पार करती हुई जारी है।

जनसंचार माध्यमों की साम्यवादी पद्धति की संरचना और विकास, चाइनीज कम्यूनिस्ट पार्टी (सी.सी.पी) की स्थापना और विकास से जुड़ा हुआ है। इस पार्टी या दल ने एक प्रोपेगन्डा को तैयार किया, उसका विस्तार किया। इस शक्ति ने पार्टी के हित को प्रोत्साहन दिया तथा पार्टी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आखिर इसे 1949 में सत्ता में पहुँचाया साम्यवादी दल के सत्ता पाने के बाद चीनी नेताओ ने अपने क्रांतिकारी पूर्व इन नेताओं का अनुसरण किया जिन्होंने अपने विचारों की वकालत करने हेतु समाचारपत्रों का उपयोग किया था। चाईनीज कम्यूनिस्ट पार्टी ने प्रेस का इस्तेमाल पार्टी के हथियार के रूप में शुरू किया था, इसलिए पार्टी में आये परिवर्तनों का माध्यमों पर प्रभाव पड़ा। 1945-49 की अवधि में कुओमिनतांग एवं साम्यवादियों के बीच चले गृहयुद्ध के समय माध्यमों का विकास तेज गति से हुआ। कम्यूनिस्ट जब शासन में आए, उस समय तक वे नए चीन के लिए माध्यमों की प्रणाली को मजबूत कर चुके थे। यह माध्यम प्रणाली, लेनिन द्वारा अपने जनसंचार माध्यम प्रणाली के सिद्धान्तों के आधार पर इस में स्थापित प्रणाली से बहुत अधिक प्रभावित थी। चीन में जनसंचार माध्यम प्रणाली का लक्ष्य पार्टी के पूर्ण नियन्त्रण में पार्टी के हितों के लिए सेवा देना था। साम्यवादी दल ने सत्ता में आते ही राष्ट्रीय 'प्रेस सिस्टम' की स्थापना कर अपनी शक्ति को सुदृढ़ बनाना आरम्भ कर दिया।

सांस्कृतिक क्रान्ति' (1966-76) के दौरान समाचारपत्रों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई जब पार्टी के भीतर के विभिन्न समूहों ने समाचारपत्रों को अपनी लड़ाई का रणक्षेत्र बनाना आरम्भ कर दिया। 'पीपल्स डैली' एवं 'लिब्रेशन आर्मी डैली' जैसे समाचारपत्र राजनीति के संघर्ष में उलझ गये जो लोग सत्ता में थे, उन्होंने कई समाचारपत्रों का प्रकाशन बन्द करवा दिया। इसके बाद आर्थिक सुधारों के युग में राजनैतिक माहौल में नर्मी आई और समाचारपत्रों ने थोड़ी शान्ति का अनुभव किया। सांस्कृतिक क्रान्ति के शिकार हुए कुछ समाचारपत्र थे। 1989 में जनतांत्रिक व्यवस्था के लिए प्रारम्भ अभियान असफल हो गया। कुछ समाचारपत्रों को राजनैतिक कारणों से बन्द होना पड़ा। लेकिन राजनैतिक दबाव कुछ समय बाद कुछ ढीला पड़ा। 1990 में चीन में 44 दैनिक समाचारपत्र थे।

6.2.2.2 रेडियो

जैसा कि प्रेस के सम्बन्ध में चीन में दृष्टि रही है, रेडियो का विकास भी चीन सरकार ने राजनैतिक विचारधारा से प्रेरित होकर किया। 1949 में चीन में 49 रेडियो 'स्टेशन थे। इनमें 30 निजी संस्थानों के प्रसारण केन्द्र थे। न्यू चाईना सरकार ने सेन्ट्रल पीपल्स ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन (सी.पी.बी.एस) के माध्यम से चार स्तरों-केन्द्रीय, क्षेत्रीय, प्रान्तीय एवं स्थानीय स्तरों पर प्रसारण नेटवर्क तैयार किया। इसके अन्तर्राष्ट्रीय विभाग रेडियो पेकिंग' ने 1950 में काम प्रारम्भ किया। 1959 में नेटवर्क के अन्तर्गत 122 रेडियो स्टेशन थे। रेडियो सुविधाओं के अभाव, साक्षरता में कमी आदि समस्याओं के सन्दर्भ में शिक्षा एवं जनसंचार प्रोपेगेन्डा के लिए सरकार ने 1950 के दशक में देश में 'वाईड ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम' का विकास किया। 'सांस्कृतिक क्रान्ति के समय

विकास में गतिरोध आया लेकिन 1980 के दशक में राजनैतिक, आर्थिक एवं टेकनोलॉजीकल विकास के लिए रेडियो सेवाओं का भारी विकास किया गया। रेडियो की पहुँच 70.6 प्रतिशत लोगों तक हो गई है। 1990 में रेडियो स्टेशनों की संख्या 1200 पर पहुँच गई। रेडियो जनसंचार का लोकप्रिय माध्यम बन गया। साम्यवादी शासन में रेडियो प्रसारणों पर राज्य के नाम पर पार्टी का आधिपत्य रहता है। पार्टी का प्रोपेगन्डा विभाग जनसंचार माध्यमों की रीति-नीत तय करता है। 'पीपल्स रेडियो' का ढांचा अधिनायकवादी रहा। लेकिन 'बाजार सुधार' कार्यक्रम इस ढांचे में परिवर्तन लाया। 'आर्थिक रेडियो' एवं टी.वी. स्टेशन खोले गए जिनकी संख्या 1992 में एक सौ थी। 12वीं सदी के अन्तिम वर्षों में विशेषज्ञता एवं 'डिसेन्ट्रलाईजेशन' की ओर प्रवृत्ति बढ़ी। इस प्रकार स्वतन्त्र एवं व्यावसायिक प्रसारणों के विकास का मार्ग खुला।

6.2.2.3 टेलीविजन

चीन के प्रथम टेलीविजन स्टेशन का प्रारम्भ बीजिंग टेलीविजन स्टेशन का नाम बदलकर 1978 में चाईना सेन्ट्रल टेलीविजन स्टेशन (सी.सी.टी.वी) रखा गया। 1961 में चीन में 26 टी.वी. केन्द्र थे लेकिन राजनैतिक दखलंदाजी एवं आर्थिक संकट के कारण एक दशक तक टी.वी. का विकास अवरुद्ध रहा। 1973 में रंगीन टेलीविजन प्रसारण आरम्भ हु ए। ग्राउण्ड सैटेलाईट स्टेशन की 1972 में स्थापना की गई। 1980 तक राष्ट्रीय टी.वी. नेटवर्क तैयार लिया गया। 1985 में रेडियो एवं टेलीविजन का ग्रामीण जनता तक प्रसार का कार्यक्रम बनाया गया।

1998 के अन्त में चीन में एक हजार टी.वी. प्रसारण केन्द्र, एवं हजार केबल स्टेशन एवं एक हजार शैक्षणिक टी.वी. केन्द्र स्थापित हो गए। टी.वी. की पहुँच 90 प्रतिशत आबादी तक हो गई। 90 प्रतिशत घरों में टी.वी. सेट हो गए। चीन एक तरह से टेलीविजन का दुनिया में सबसे बड़ा बाजार हो गया। लोगों के चीन संस्कृति को समझने एवं महसूस करने का टी.वी. एक बड़ा माध्यम बन गया।

6.2.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी

चीन में इन्टरनेट सेवा का प्रारम्भ 1994 में हु आ। इसके बाद देश में तेजी से ये सेवाएं फैली। 1997 में 75 लाख कम्प्यूटर हो गए। इन्टरनेट को उपयोग करने वालों की संख्या 4 लाख हो गई। चीन का पहला कम्प्यूटर नेटवर्क 'सीएनेट' 1987 में शुरू हु आ था। 82 समाचारपत्रों ने 1998 में 'इन्टरनेट साईट्स ' शुरू की तथा समाचारपत्रों के 128 संस्करण 'ऑन लाईन' पर उपलब्ध होने लगे। इनमें 'पीपल्स डेली', चाईना इकोनोमिक डेली, चाईना ट्रेड न्यूज आदि प्रमुख हैं। साईबर स्पेस पर छा जाने की इच्छा के बावजूद चीन में कम्पयूटर नेटवर्क पर नियन्त्रण रखने की प्रवृत्ति जारी है। बाजार की शक्तियों के चीन में प्रवेश के कारण सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार की मांग चीन में बलवती हो गई है। लेकिन चीन का मानना है कि सूचनातंन्त्र की शक्तियों का स्वतन्त्र अस्तित्व सम्भव नहीं है क्योंकि उन्हें आशंका है कि ऐसा होने पर उनकी व्यवस्था, स्थायित्व, एकता और आर्थिक नियन्त्रण प्रभावित होते हैं। राजनीति के दृष्टिकोण एवं यौन सम्बन्धी वेबसाईट्स को सरकार रोकने के प्रयास करती है। चीन ऐसी ताकतों को रोकने की व्यवस्था करता है जो सांस्कृतिक प्रदूषण उत्पत्र कर सकती हैं। इसलिए सी.एन.एन., न्यूयार्क टाइम्स आदि वेबसाईट्स पर पाबंदी लगाई गई और जून, 1999 में शंघाई के 2000 इन्टरनेट कैफे में से 300 बन्द कर दिए गए क्योंकि वे बिना लाईसेन्स के संचालन में थे।

6.2.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति

चीन में सरकार की यह सोच है कि जनसंचार माध्यमों को सामाजिक स्थायित्व कायम रखने में मदद करनी चाहिए। अत : राज्य में सख्त या नरम होने या उसके स्थायित्व के प्रभावित होने की स्थितियों के अनुरूप जनसंचार माध्यमों पर अंकुश लगता रहा है या उन्हें छूट मिलती रही है। बाजार सम्बन्धी सुधारों के शुरू होने के बाद सरकारी नीति में कुछ परिवर्तन एवं लचीलापन आया है। 1980 में, जबकि सरकार का अधिक ध्यान देश के आर्थिक विकास की ओर था तथा बाहरी दुनिया की तरफ चीन के द्वार खुलने लगे थे, जनसंचार माध्यमों को काफी स्वतन्त्रता मिलने लगी। लेकिन 'टाईनमिन स्क्वायर' की घटना के बाद सरकार ने कड़ा रुख अपनाना चालू कर दिया। चीन में जनसंचार माध्यमों की स्थिति स्वतन्त्रता के परिप्रेक्ष्य में 'पेन्डूलम' की तरह है और आर्थिक सुधारों के युग में यह अधिक पेचीदगी का सामना करने लगे हैं। एक और सरकार और पार्टी कुछ विशेषज्ञता प्राप्त माध्यमों पर अंकुश कम करने की प्रवृत्ति प्रगट करने लगी, वहीं राजनैतिक सामग्री का प्रकाशन करने वाले माध्यमों पर नजर कड़ी कर दी गई। सरकार का स्थायित्व प्रमुख लक्ष्य है। अत : जनसंचार माध्यमों पर अंकुश को राजनैतिक दृष्टि से आवश्यक माना जाता है और आर्थिक सन्दर्भों में इन्हें नरमी के साथ देखा जाता है। अत: जनसंचार माध्यमों के प्रति नीति में यह अधरझूल की स्थिति जारी है।

6.2.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे

चीन के जनसंचार माध्यमों के परिदृश्य से चीन के आर्थिक सुधारों की नीति ने अनचाहे परिवर्तन कर दिए हैं। आर्थिक सुधारों के कारण सरकार के सामने जनसंचार माध्यमों की भूमिका को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता पैदा कर दी है। कई दशकों से चीन के पत्रकारों को बताया गया कि जनसंचार माध्यम मात्र पार्टी के हथियार हैं। जो कुछ वे करें वह पार्टी की सेवा के लिए ही करें। लेकिन व्यवसायीकरण की शक्तियों ने उनका ध्यान पार्टी से हटाकर उपभोक्ता की ओर मोड़ दिया है। परिणाम यह हुआ है कि इस दृष्टि से कई समाचारपत्रों का विकास हुआ है तो सरकारी समाचारपत्रों की मांग तेजी से घटी है।

इसके अलावा आर्थिक सुधारों के कारण पार्टी के नियन्त्रण की प्रवृत्ति को धक्का लगा है। जनसंचार माध्यमों के व्यावसायीकरण एवं आर्शिक सुधारों ने जनसंचार माध्यमों पर पार्टी के नियन्त्रण से पार्टी के माध्यमों के प्रति जनरुझान घटने लगा है।

जनसंचार माध्यमों में इन सुधारों के कारण दुराचरण की प्रवृति बढ़ी है। विज्ञापनों पर निर्भरता बढ़ने से संचार माध्यमों में बुराइयां घर करने लगी हैं। 'रैडपैकेट' की प्रवृत्ति भी बढ़ी है क्योंकि 'रैडपैकेट' पत्रकारिता का लक्ष्य व्यवसायों द्वारा सूचना-पत्रकारों को भ्रष्ट करके उनकी प्रतिष्ठा को गिराना होता है। यह कार्य अपने पक्ष में प्रचार के लिए लोग करते हैं। इसके अलावा बाहरी संचार माध्यमों का भी खतरा है। ऐसे में सरकार के लिए प्रेस स्वतन्त्रता के मुद्दे पर चिन्तन करना अनिवार्य हो गया है। जनसंचार माध्यमों के बीच का तनाव घट गया है। व्यवसायीकरण एवं जनतांत्रिक रण की बढ़ती प्रवृत्तियों के कारण स्वतन्त्रता का प्रश्न कोई न कोई मार्ग पर तो जाकर स्थिर होगा।

Media China's Top Dailies

Select titles	Established	Estimated

		circulation
Sichuan Ribao (Sichuan Daily)	1952	8milliion
Cankao Xiaoxi (Reference News)		2.90 million*
Renmin Ribao (People's Daily)	1948	2.13 million*
Xinmin Wanbao (Xinmin Evening News)	1903	1.72 million*
Wenhui Bao (Wenhui Daily)	1938	1.7 million*
Jingji Ribao (Economic Daily)	1983	1.5 million
Yangcheng Wanbao (Yangcheng Evening Post)	1957	1.29 million*
Nongmain Ribao (Present daily)	1980	1 million
Jeifang Ribao (Libration Daily)	1949	1 million
Gaungming Ribao (Gaungming Daily)	1949	950,000
Huber Ribao (Huber Daily)	1949	900,000
Guangzhou Fazhi Bao (Guangzhou Daily)	1952	870,000*
Zhongguo Fazhi Bao(China legal Daily)		830,000*
Gongren Ribao (Workers Daily)	1949	820,000*
Jiefangjum Ribao (Liberation Army Daily)	1949	800,000
Zhonggou Tiyu Bao (China Sport Daily)		800,000
Beijing Wanbao (Beijing Evening News)	1958	800,000
Zhongguo Qingnian Bao (China Youth daily)	1951	790,000*
Beijing Ribao (Beijing Daily)	1952	700,000
Nanfang Ribao (South China Daily)	1949	670,000
Guangxi Ribao (Tiajin daily)	1949	650,000
Liaonong ribao (Liaoning daily)		600,000
Fujian Ribao (Fujhan Daily)	1949	600,000
Dazhong Ribao (Masses Daily)	1939	550,000
Jingji Xinxi Bao (Economic Infornation Daily)		500,000
Weisheng Bao (Health Daily)		500,000
Shaanxi Ribao (Shaanxi Daily)		500,000
Jilin Ribao (Jilin Daily)	1948	500,000
Heilongjiang Riabo (Heilonggjang Daily)		500,000
Guizhou Ribao (Guizhou Daily)	1949	300,000
Human Riabao (Human Daily)		300,000

China Daily)	1981	150,000

Source: Editor & publisher international yearbook,1999. *WAN 1999.

Newspaper Organizations

Renmin Ribao (people's Daily)
2 Jin Tan Xi1.u
Beijing 100733

Jingji Ribao (economic Daily)
277 Wang Fu Jin Da Jle
Beijing 100746

Gongren Ribao (Worker's Daily)
An Ding Men Wat. Jin Pu Kang
Beijing 100718

Zhungguo Furu Bao (Chinese Daily)
50 Deng Shi Koudaa Jle,
DongCheng District
Beijing 100730

Wen Hiu Bao (Wen Hui Daily)
50Hu Qiu 1.u
Shangha, 200002

Guang Ribao (Guangming Daily)
106 Youmg An 1.u
Beijing 100029

Zhngguo Riabao (China Daily)
15 Hui Xin Dong Jue, ChaoYang District
Beijing 100029

Zhngguo Qingnian Bao (Chinese Youth Daily)
2 Dong Jhi Men Nei Hai YUn Chang
Beijing 1000702

Beijing Wanbao (Beijing Evening News)
34 Dong dan Xi Brang Bei Hu Tong
Beijing 100734

Xinmin Wanbao (Xin Min Evening News)
839 Yan An Zhong Lu
Shanghai, 200040

6.3 हांगकांग (चीन) में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी

6.3.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

हांगकांग 1092 वर्ग कि॰मी॰ में फैला हुआ है। कुल 200 द्वीपों तक इसका विस्तार है। चीन की दक्षिण सीमा पर बसा हुआ है। केवल छह प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। 'एशियावीक' के अनुसार 'गुणवत्तापूर्ण जीवन' की दृष्टि से यह एशिया का सातवां श्रेष्ठ नगर है। छह करोड़ आबादी के इस नगर की 92. 4 प्रतिशत जनता साक्षर है। 75 प्रतिशत लोग नगरीय क्षेत्र में रहते हैं।

हांगकांग पूर्व एवं पश्चिम की संस्कृतियों का केन्द्रीय स्थल है। 95 प्रतिशत जनता चीनी की है लेकिन इण्डोनेशिया, फिलीपीन्स, थाईलैण्ड एवं मलेशिया के लोग भी यहां रहते हैं। जापान, भारत, कनाडा, आस्ट्रेलिया, अमेरिका इंग्लैंड एवं अन्य देशों के लोग भी निवास करते हैं। चीनी बोली 'केन्डोनीज' का प्रयोग बहुतायत से होता है। कई लोग अंग्रेजी बोलते हैं। राजकाज की भाषा चीनी है। ईसाई, मुसलमान एवं हिन्दु भी रहते हैं लेकिन बहुसंख्यक बौद्ध एवं नाओ धर्म मानते हैं।

हांगकांग में प्राकृतिक स्त्रोत कम हैं। लेकिन इसके चीन के द्वार के रूप में होने तथा कठिन परिश्रम के कारण यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है। जब चीन 1841 में 'अफीम युद्ध' हार गया तो हांगकांग ब्रिटेन के हाथों में चला गया। इसके बाद यह चीन और अन्य दुनिया के व्यापार का केन्द्र बन गया। यह एक छोटा सा गाव था लेकिन चीन में साम्यवदि‍ा शासन के समय अनेक शरणार्थी यहां आकर बस गये। टेक्सटाईल एवं गवरमैन्ट वस्त्रों के निर्माण एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्टेड उद्योग के निर्माण से यह युद्ध हुआ। साईनो-ब्रिटिश सयुक्त घोषणापत्र के अनुसार यह चीन का 'स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रिजन' (एस.ए.आर.) बन गया तथा इसने अपनी मुक्ति अर्थ-व्यवस्था प्रणाली जारी रखी।

6.3.2 जनसंचार : उद्धभव एवं विकास

6.3.2.1 समाचारपत्र

हांगकांग की प्रमुख विशेषता यह है कि यह सदैव चीन की राजनीति के करीब रहा। हांगकांग एवं शंघाई ब्रिटेन के उपनिवेश थे। चीन की आधुनिक प्रेस के जन्मस्थल थे। 1850 में अंग्रेज मिशनरियों ने अंग्रेजी भाषी प्रैस की शुरूआत की। 1870 में चीनी प्रेस का जन्म हुआ। चीन की साम्यवादी पार्टी एवं नेशनेलिस्ट पार्टी के टर्न पर हांगकांग के समाचारपत्र बंटे रहे। हांगकांग की 1970 के दशक में एक नई पहचान उभरी। जनसंचार माध्यमों का झुकाव जनता की भावनाओं के अनुरूप ढलने लगा। 1980 में जब चीन और ब्रिटेन के बीच समझौता होने लगा। हांगकांग की प्रेस ने ब्रिटेन का पक्ष लिया। 1984 से 1097 तक शक्ति के दोहरे मापदण्डों के साथ समन्वय किया। हांगकांग के चीन को 1997 में सुपुर्द किए जाने के बाद इस उपनिवेश ने बचाव का रुख अपनाया। चीन को हांगकांग की जीवन शैली एवं प्रेस स्वतन्त्रता को जारी रखने को विवश होना पड़ा। 1997 में हांगकांग में 30 चीनी भाषा क तथा 10 अंग्रेजी पत्र थे। एशियन वाल स्ट्रीट जनरल, एशिया वीक, दी फोर ईस्टर्स, इकोनोमिक रिव्यू एवं इन्टरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून जैसे समाचारपत्रों ने मुद्रण के लिए हांगकांग को आधार स्थल बनाया।

समाचारपत्रों का वितरण - हांगकांग में आबादी का बाहरी केंद्रीयकरण एवं भारी संख्या में कई मंजिली ईमारतों के कारण डाक से समाचार भेजने या वितरण करने का आम तरीका कारगार नही है।इसलिए वहां स्ट्रीट होकर प्रणाली आम चलन में है। अनेक लोगों ने रेस्तरों के पास घनी आबादी के मोहल्लों के किनारों पर छोटे-छोटे स्थल निर्धारित कर रखे हैं। जहां सब प्रकार के समाचारपत्र एवं पत्रिकाएं उपलब्ध कराए जाते है। लोगों की आदत मैं यह शुमार है कि वे इन गली मोहल्लों के हार्स से पत्र पत्रिकाएं खरीदते हैं। कुल समाचारपत्रों की बिक्री में 'सब्सक्रिप्सन' के द्वारा बहुत ही कम मात्रा में पत्रों की बिक्री होती है। पत्र छपते है होल सेलर्स के केन्द्रीय पॉइन्ट या स्थलों पर रोज सुबह समाचारपत्र ट्रकों से कूच जाते हैं। इसके बाद वाहनों से विभिन्न स्थलों पर पत्रों को आपूर्ति की जाती है वितरण में वहां आधुनिक टेकनोलार्जों का उपयोग नहीं किया जाता।

6.3.2.2 रेडियो

हांगकांग में रेडियो का प्रारम्भ 1928 में हुआ। 1948 में रेडियो हांगकांग बना। 1960 में रेडियो स्टेशन का विस्तार होने तथा 1970 में टी.वी. की शुरूआत के साथ रेडियो का नाम बदलकर रेडियो टेलीविजन हांगकांग कर दिया गया। रेडीफ्यूगन केबल प्रसारण ने अपनी प्रसारण सेवाएं 1949 में आरम्भ की। केबल रेडियो सेवाएं 1950 और 1960 के दशकों में लोकप्रिय रही लेकिन ट्रांजिस्टर के चलन ने केबल रेडियो की सेवा की मांग में कमी कर दो। ट्रांजिस्टर सेट्स की उपलब्धता एवं 1967 में रेडियो लाईसेन्स प्रणाली खत्म होने के बाद लोगों की पहुँच रेडियो हांगकांग के कार्यक्रमों में होने लगी। इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एण्ड ब्राडकास्टिंग ब्यूरो की स्थापना 1977 में हुई। यह प्रसारण सेवाओं की रीति-नीति तय करता है। हांगकांगकी कोई निश्चित' सांस्कृतिक नीति नहीं है। यह सूचनाओं का मुक्त पोर्ट है। यहां माध्यमों द्वारा सूचना प्रवाह पर कोई सख्त नियन्त्रण नहीं है। आधुनिक तकनालॉजी एवं बाजार के नियमों से मुक्त विश्व प्रवृत्ति का हांगकांग में अनुसरण होता है। यद्यपि चीन के अधिकार में आने से कुछ पाबन्दियों का कानूनों को लागू किया जा सकता है लेकिन अभी संकेत यह है कि हांगकांग अपनी मुक्त नीति का अनुसरण करता रहेगा। हांगकांग में 50 प्रतिशत लोग रेडियो कार्यक्रम सुनने में रुचि रखते हैं।

6.3.2.2 टेलिविजन

यद्यपि हांगकांगमें टी.वी. प्रसारण 1970 में शुरु हो गया लेकिन 20वीं सदी के अन्त तक टी.वी. की पहुँच हर घर तक हो गई। 20 लाख घरों मे टी.वी. हैं तथा 63 लाख टी.वी. दर्शक हैं। 35 प्रतिशत लोगों के पास एक से ज्यादा टी.वी. सेट है। टी.वी. के 38 चैनल उपलब्ध हैं। सैटेलाईट टेलीविजन एशियन विजय लि. (स्टार टी.वी.),चाइनीज टेलीविजन नेटवर्क (सी.टी.एन.) आदि कई प्रमुख चैनलों के प्रसारण होते हैं। हांगकांग में सबसे बड़ा चीनी टी.वी. प्रोग्राम लाभप्रेरी है। यहां से आडियो विजुअल उत्पादों का निर्माण होता है। चीन के अधिकार में आने के बाद टी.वी. की आर्थिक स्थिति में कमी आई है। लेकिन इसके संचालन का वातावरण मुक्त है तथा इसके विकास की सम्भावनाएँ बनी हुई हैं।

6.3.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी

20वीं सदी के अन्तिम दशक में हांगकांग में नई सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। 1998 में 125 इन्टरनेट प्रोवाईजर्स थे। आधे लोगों के पास पर्सनल कम्प्यूटर हैं। 8,50,000 लोग इन्टरनैट का उपयोग करते हैं। 1996 में 2,70,000 इन्टरनेट उपभोक्ता थे। यह संख्या 1997 में बढ़कर 5,00,000 हो गई। 1999 में अति आधुनिक 'साईबर पोर्ट ' स्थापित करने के लिए भवन निर्माण एवं आधुनिकतम उपकरणों द्वारा स्थानीय एवं बहुराष्ट्रीय संस्थानों की सूचना सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने की यौजना बनाई गई।

6.3.4 जनसंचार माध्यमों संदर्भ मे नीति

हांगकांग में 'ब्रिटिश कॉमन लॉ' के तहत समाचारपत्रों का संचालन होता है। यद्यपि इस उपनिवेश में कई गैर जनतांत्रिक कानून मौजूद हैं। यह एक प्रकार से मुक्त स्थान के रूप में अपने जनसंचार माध्यमों का संचालन करता आया है। 1950 में शीत युद्ध के समय साम्यवार्दा चीन से खतरा उत्पन्न हुआ। प्रेस की आजादी को कम करने के लिए कई कानून बने। लेकिन हांगकांग में प्रेस पाबन्दी लगाने की विवशता इसलिए नहीं हुई कि हांगकांग में वहां के राजनैतिक दल नहीं हैं और श्रमिक संगठन भी कमजोर है। माध्यमों का राजनैतिक दलों या संगठनों के साथ ढांचागत कोई तालमेल नहीं है। इसलिए उपनिवेशी शासन के सामने जनसंचार माध्यमों की कोई चुनौती नहीं रही।

6.3.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे

हांगकांग पर चीन का अधिकार होने के बाद यह आशंका थी कि जनसंचार माध्यमों की आवाज धीमी हो जाएगी, लेकिन संचार माध्यम द्वारा अपनी स्वतन्त्र परम्पराएँ जारी रखी गईं। 'एफल डेली' जैसे सफल समाचार पत्र के प्रवेश ने कई समाचारपत्रों के समक्ष अस्तित्व का संकट पैदा कर दिया। समाचारपत्रों में इससे पाठकों तक पहुंचने के लिए प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई और उनकी प्रकाशन सामग्री सस्ती या अश्लील प्रकार की होने लगी। सम्प्रादकीय सामग्री में गिरावट दौर शुरू हुआ। बाजार की शक्तियों के अनुरूप गतिशील होने की प्रवृत्ति ने पत्रकारिता में 'पीत पत्रकारिता' की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। माध्यमों के इस प्रकार के आचरण के बारे में सरकार को शिकायतें मिलने लगी। इससे हांगकांग में प्रेस स्वतन्त्रता के भावी स्वरूप के निर्धारण की दिशा में अनिश्चय की स्थिति बनी है।

Media Press HongKong S.A.R

Title	Established	Nature	Circulation	Readership
Oriental daily News	1969	mass	*	2,551,000
Apple dairy	1995	mass	406,666	1,780,000
The Sun	1999	mass	*	**
Ming Pao Daily News	1959	elite	85,699	285,000
Sing Pao Daily News	1939	mass	*	241,000
South China Morning Post	1903	elite, English	117.563	206,000
HongKong Daily News	1959	mass	*	157,000

Tin Tin Daily News	1960	mass	*	158,000
Sing Tao Daily	1938	elite	59.338	118,000
Hong Kong Economic Times	1988	elite, business	68,123	101,000
Hong Kong Economic Journal	1973	elite, business	63,120	62,000
Wen Wei Po	1948	pro-china	*	*
Ta Kung Pao	1938	pro-china	*	*
Hong Kong Commercial Daily	1952	pro-china, business	*	*
Hong Kong Standard	1949	elite, English	*	*

Source: *Hong Kong Audit Bureau of Circulation (ABC) Ltd. (July-December, 1998 figures).

बोधप्रश्न - 1

1. चीन की सरकार का जनसंचार माध्यमों के प्रति क्या सोच है?
2. हांगकांग में समाचारपत्रों का वितरण कैसे होता है?
3. हांगकांग की नई सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में प्रकाश डालिए ।

6.4 मकाऊ (चीन) में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी

6.4.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

चीन के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एस.ए.आर. (स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटीव रीजन) मकाऊ, हांगकांग से 70 कि॰मी॰ दक्षिण में 21.45 वर्ग कि॰मी॰ क्षेत्र में फैला हुआ है। मकाऊ की आबादी 4,37,312 है। 69 प्रतिशत लोग चीनी हैं, 27 प्रतिशत पुर्तगाली हैं। 96 प्रतिशत लोग चीनी भाषा बोलते हैं। 75 प्रतिशत साक्षरता है। 90 प्रतिशत लोग शहरी हैं।

1958 में पुर्तगाली शासन था 1959 में चीन ने मकाऊ पर नियन्त्रण कर लिया था। 1987 में पुर्तगाली शासन जनसंचार मकाऊ को चीनी क्षेत्र माना गया। चीन और पुर्तगाल दोनों एक देश दो पद्धतियों' के सिद्धान्त के आधार पर मकाऊ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) को हांगकांग के मॉडल पर रखने को सहमत हो गए। दोनों देशों ने अपने सयुक्त घोषणा पत्र में यह सहमति प्रगट की कि समसामयिक सामाजिक एवं आर्थिक प्रणाली में को परिवर्तन नहीं किया जाएगा। समस्त अधिकारों एवं स्वतन्त्रता का बेसिक लॉ के द्वारा सरक्षण किया जाएगा, यह कानून 20 दिसम्बर, 1959 से उस समय लागू हुआ क्रांति चीन की मकाऊ पर सार्वभौम सत्ता स्थापित हुई।

6.4.2 जनसंचार : उद्भव एवं विकास

6.4.2.1 समाचारपत्र

मकाऊ का विकास हांगकांग से पहले हुआ लेकिन यह उसकी तुलना में अधिक महत्व नहीं प्राप्त कर सका। मकाऊ पूर्व-पश्चिम की संस्कृतियों का केन्द्र था। पश्चिमी पादरी यहां अपने धार्मिक साहित्य का प्रकाशन करने आते थे। यहां चीन, जापान, कोरिया तथा पुर्तगाली समाचारपत्र प्रकाशित हुए, लेकिन आर्थिक एवं राजनैतिक कारणों में ये समाचारपत्र अधिक दिन नहीं चले। इस

अवधि में अंग्रेजी समाचारपत्र भी प्रकाशित हुए जिन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा। हांगकांग की तरह चीन की राजनैतिक शक्तियों की प्रोपेगेन्डा लड़ाई का भी यहां कुछ असर हुआ। मकाऊ में प्रेस का विकास 1911 के आसपास शुरू हुआ। जनरल इनफोरमेशन, ताईवान जैसे पत्र छपने लगे। जब चीन में साम्यवादी दल ने राष्ट्रवादी पार्टी को हरा दिया, उस समय ताईवान समर्थक मकाऊ आ गए तथा वहाँ समाचारपत्र निकाले। 1966 में मकाऊ की प्रेस पर चीन की सांस्कृतिक क्रान्ति का प्रभाव पड़ा। चीन का राजनैतिक प्रभाव बढ़ा एवं मकाऊ की सरकार कमजोर हुई। चीन के ताईवान समर्थकों को समाचारपत्रों को बन्द करवाने में योग दिया।

मकाऊ में आठ चीनी समाचारपत्र प्रकाशित होते हैं जिनमें साम्यवादी 'मकाऊ आर्गन' प्रभावशाली पत्र है। जरनल "वा कियो' गैर दलीय पत्र है। तीन पुर्तगाली भाषा के पत्र भी हैं। पुर्तगाल के संविधान द्वारा मकाऊ की प्रेस सम्पादकीय स्थिति, संचालन एवं प्रबंधन के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त थी। सरकारी सूचना सेवाएं मात्र नियामक संस्था है।

6.4.2.2 रेडियो

मकाऊ में रेडियो प्रसारण की शुरूआत 1993 में हुई। 1948 में सरकार ने इसका अधिग्रहण किया। 1982 में सरकार ने रेडियो का प्रबन्ध सरकार संस्था टेलेडिफुजाओ डे मकाऊ (टी.डी.एम.) को सौंप दिया। मकाऊ में दो रेडियो चैनल हैं। एक पुर्तगाली भाषा में प्रसारण करता है तथा दूसरा 'केन्जोनीज़' भाषा में।

6.4.2.3 टेलीविजन

मकाऊ में टी.वी. प्रसारण 1984 में आरम्भ हुआ। सरकार के वित्तीय सहयोग से एक सार्वजनिक संस्था इसका संचालन करती थी। कमजोर प्रबन्धन एवं भारी वित्तीय नुकसान होने पर 49.5 प्रतिशत पूंजी को अपने पास रखते हुए इसे एक समूह को बेच दिया। 1987 में टी.वी. का निजीकरण कर दिया गया। हांगकांग एवं चीन से निःशुल्क उच्च स्तरीय कार्यक्रम मकाऊ में उपलब्ध हो जाते हैं। हांगकांग और मकाऊ का सम्बन्ध कनाडा और अमेरिका के बीच के संबंधो की तरह है।

6.4.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी

मकाऊ मे तीन इन्टरनेट सर्विस प्रोवाईडर हैं। 1996 में 3037 इन्टरनेट उपभोक्ता थे। उस समय 40,000 कम्प्यूटर थे। पूरी तरह डिजीटल नेटवर्क एवं दो सेटेलाईट स्टेशन है।

6.4.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति

मकाऊ के जनसंचार माध्यम साम्राज्यवादी नीतियों से ग्रस्त हैं, लेकिन माध्यमों के संचालन के सन्दर्भ में लोगों को कोई शिकायत नहीं है। मकाऊ एक बहुत छोटी जगह है। इस कारण वहाँ हांगकांग के जनसंचार माध्यमों का वर्चस्व है।

6.4.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे

जनसंचार माध्यमों के सन्दर्भ में मकाऊ की स्थिति हांगकांग से अलग है। मकाऊ के समाचार पत्रों का सम्बंध बीजिंग से रहा। अत: 1999 में पुर्तगाल के शासन की समाप्ति पर स्वयं

द्वार सेन्सरशिप या कानूनी खतरे उपस्थित नहीं हुए। अब मकाऊ चीन की ओर उन्मुख हो गया है। प्रेस में विविधता की कमी प्रमुख मुद्दा है। इस कारण अलग-अलग प्रकार के विचारों एवं विस्तृत झलक पर विचार अभिव्यक्ति की सीमाओं से प्रेस जुड़ा हुआ है।

Media Press maco S.A.R

Title	Established	Circulation
Macao Daily News	1958	100,000
Journal""VA koi"	1937	35,000
Journal""Tai Chung"	1933	16,000
Si Man Pou	1944	12,000
Today Macao Journal	1987	2,000
Seng Pou (Journal Estrela)	1963	*
Cheng Pou	1978	*
Correo Sino-macaense	1989	*

Source: Editor & publisher international yearbook, 1999

Broadacasting

Number of TV channels	4	Canal Portugues (2 channels)
		Canal Chinese (2 Channels)
Number of Radio channels	2	Radio Macau, Ou Mun Tin Toi

6.5 जापान में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी

6.5.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

जापान सात हजार द्वीपों की श्रृंखला है। वह एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 3,77,835 वर्ग किलोमीटर है। इसमें चार प्रमुख द्वीप हैं। 1999 में जापान की जनसख्या 12 करोड़, 62 लाख थी। 40 प्रतिशत आबादी टोकियो, ओसाका एवं नागोवा नगरों में बसी हुई है। देश की भाषा जापानी है। सिनोटोइडस धर्म को मानने वालों का प्रतिशत 49.2 है, जबकि 44.1 प्रतिशत बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। ईसाई 1.5 प्रतिशत एवं अन्य 5.2 प्रतिशत है। जापान में राजशाही है लेकिन वहाँ संसदीय लोकतन्त्र कायम है। 1955 से लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का शासन रहा है। 1993 के चुनाव में यह दल हार गया। जापान में युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ लेकिन 1994 में यह फिर सत्ता में आ गया।

6.5.2 जनसंचार. उद्भव एवं विकास

6.5.2.1 समाचारपत्र

1615 में प्रारम्भ ‘का वारवान’ (टाईल ईनग्रेविंग) समाचारपत्र से प्रेस युग का जापान में सूत्रपात हुआ। 'बटालियान' शिम्बुन-1861 में जापानी भाषा का पहला पत्र प्रकाशित हुआ। 1860 में अंग्रेजी में समाचारपत्र छपा। जापानी भाषा का पहला दैनिक 1871 में निकला। 1937 तक जापान

में 1200 पत्र-पत्रिकाएं हो गई लेकिन 1942 में इनकी संख्या घटकर मात्र 54 हो गई। यह तत्कालीन सरकार की समाचारों पर पाबन्दी की नीति का परिणाम था। साथ ही इसका कारण अखबारी कागज की कमी भी था। 1941 में सेना के शासन में न्यूज़ पेपर बिजनेस कन्ट्रोल आरडिनेन्स लागू कर दिया गया था।

दूसरे विश्वयुद्ध के समय जापान की हार के कारण दी जनरल हेडक्वार्टर्स ऑफ दी सुप्रीम कमांडर (जी.एच.क्यू) ने इस पर नजर रखना आरम्भ कर दिया। 'कोल्डवार' के समय जी.एच.क्यू ने साम्यवादी समाचारपत्र 'अकाहाता' पर रोक लगा दी तथा सभी माध्यमों को अपने यहां के सम्पादकीय कार्यालयों से साम्यवादियों को हटाने का आदेश दे दिया। जी.एच.क्यू द्वारा की गई सेन्सरशिप ने पत्रकारिता में सरकार के खिलाफ असन्तोष एवं नाराजगी उत्पन्न कर दी। इससे सरकार ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और कालान्तर में 126 समाचारपत्र उभरकर सामने आए। 'न्यूजप्रिन्ट कन्ट्रोल' 1951 में समाप्त होने के बाद समाचारपत्रों की पृष्ठ संख्या भी तेजी से बढ़ने लगी और कई पत्रों में समाचारपत्र की पृष्ठ संख्या 26 का आकड़ा पार कर गई। समाचारपत्रों के प्रसार के क्षेत्र में भी पतिस्पर्द्धा तेज हो गई। बड़े समाचारपत्रों का राष्ट्रीय स्तर पर तथा क्षेत्रीय पत्रों का क्षेत्रीय स्तर पर वर्चस्व बढ़ने लगा।

जापान समाचारपत्रों से समृद्ध देश है। एन.एस.के. से सम्बद्ध 121 दैनिक समाचारपत्रों की प्रसार संख्या 1998 में लगभग 53.7 मिलियन (अर्थात् 1.6 प्रतियां प्रति घर) (एन.एस.के. 1999) इस आकड़े में थी। प्रात:कालीन एवं सायंकालीन संस्करण की एक प्रति मानी गई है क्योंकि कई जापानी समाचारपत्र प्रातःकालीन एवं सायंकालीन दोनों संस्करण प्रकाशित करते हैं तथा उनकी एक सेट (दोनों प्रतियों का) के रूप में विक्रय करते हैं। यदि प्रात:कालीन एवं सायंकालीन संस्करणों की प्रतियों की अलग-अलग गणना करें तो कुल प्रसार संख्या 72.4 मिलियन पर पहुंच जाती। इससे चलता है कि जापान में प्रति 100 व्यक्तियों के पीछे 57.6 प्रतियां बिकती हैं।

जापान में पांच ऐसे समाचारपत्र है जिनका प्रसार पूरे राष्ट्र में होता है। ये है -योमिमूरी शिम्बुन, असाही शिम्बुन, मैनिची शिम्बुन, निहोन केजाई शिम्बुन एवं सैंकाई शिम्बुन।

6.5.2.2 रेडियो

सार्वजनिक नियमों के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ 1924 में सरकार ने तीन रेडियो स्टेशन शुरू करने का निर्णय लिया। 1925 में जापान में रेडियो के प्रसारण शुरू हुए। टोकियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में ओसाका एवं नागोया स्टेशनों से प्रसारण आरम्भ किए। 1926 में तीनों स्टेशनों को मिलाकर 'निहोन हो सो व्योकाई' की स्थापना की। रेडियो पर सरकार का पूर्ण आधिपत्य था। 1945 में विश्वयुद्ध के समय रेडियो मिलिट्री प्रोपेगेन्डा का हथियार बन गया लेकिन युद्ध के बाद एक जनतान्त्रिक माध्यम के रूप में पुन: उभरा। जी.एच.क्यू ने रेडियो की एकाधिकार प्रणाली को समाप्त करके इसे अमेरिका के मॉडल पर ढालना शुरू किया । 1950 में तीन कानूनों के तहत रेडियो का जापान में नवयुग प्रारम्भ हुआ। रेडियो रेगूलेटरी कमीशन ने 1950 से 1952 तक 16 व्यावसायिक प्रसारण केन्द्रों के लिए लाईसेन्स दे दिए।

1950 का दशक रेडियो के विकास एवं विस्तार की दृष्टि से जापान में सुनहरा काल था। लेकिन टी.वी. के आगमन ने 1960 के दशक मे रेडियो सेवाओं पर कुप्रभाव डाला और सेवाओं की संख्या घटने लगी। 1950 में यह औसत 30 मिनट प्रतिदिन पर आ गया। 1995 के बाद 20

प्रतिशत से भी कम लोग रेडियो श्रोता थे। रेडियो ने संगीत, खेलों एवं समाचार के विशिष्ट कार्यक्रमों के माध्यम से एक विशेष प्रकार का श्रोतावर्ग तैयार करके अपने अस्तित्व को कायम रखा है।

6.5.2.3 टेलीविजन

'निहोन हो सो क्यो काई' (N.K.K) (जापान की ब्राडकास्टिंग कार्पोरेसन) ने 1953 में टी.वी. प्रसारण आरम्भ किया। इसके बाद उसी साल अगस्त में पहला कामर्शियल स्टेशन-एन.टी.वी. शुरू हुआ। प्रारम्भ में टी.वी. सेट्स की कीमत अधिक थी लेकिन आर्थिक विकास एवं टी.वी. सेंट्स के अधिक उत्पादन से सेंट्स की किमत कम होने के कारण जापानी समाज में टी.वी. के प्रति रुझान तेजी से बढ़ा। 1964 में औलम्पिक खेलों के समय टी.वी. के प्रसार को और गति मिली। रंगीन टी.वी. का आरम्भ 1960 में हुआ। आज हर घर में टेलीविजन है। टी.वी. सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम है। मल्टीचैनल केबल टी.वी. एवं कम्यूनिकेशन सेटैलाईट डिजिटल ब्राडकास्टिंग के कारण जापानी टी.वी. दर्शकों के समक्ष चैनल के चयन का विस्तृत दायरा है। जापान में टी.वी. के विकास की रफ्तार धीमी रही है लेकिन यह निरन्तर विकासोन्मुख रही। जापान में 1998 में 126 व्यावसायिक प्रसारण संस्थान थे। उनमें पांच नेटवर्क ऐसे थे जिनमें 118 स्टेशनों का सम्पर्क था। जापान न्यूज नेटवर्क, (जे.एन.एन.) आदि प्रमुख हैं।

6.5.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी

जापान ने अपने सूचनातन्त्र को सुदृढ़ बनाने एवं विकसित राष्ट्रों के अनुरूप बनाने के प्रयत्न 1965 में शुरू कर दि थे । यही कारण है कि टी.वी., डिजीटल, ब्राडकास्टिंग, इन्टरनेट एवं दूरसंचार के क्षेत्र में जापान ने तीव्र गति से विकास किया है। देश में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के विकास ने परम्परागत माध्यमों से सामने एक चुनौती खड़ी कर दी है। इन्टरनेट के क्षेत्र में जहां 1995 में 13 लाख इन्टरनेट उपभोक्ता थे जो 1997 में 57 लाख हो गए। 1998 में यह संख्या एक करोड़ हो गई तथा 1999 फरवरी में बढ़कर 1 करोड़ 50 लाख तक पहुंच गई। 1938 में 32.6 प्रतिशत लोगो के पास कम्प्यूटर थे।

समाचारपत्र उद्योग भी नए इलेक्ट्रानिक वातावरण के साथ अपना समन्वय बनाए रखने को प्रयत्नशील है । अधिकांश बड़े समाचारपत्र ऑन लाईन पर उपलब्ध हैं। साईबरस्पेस में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जापान के बड़े संस्थान ऑन लाईन उत्पादों की प्रवृत्ति के लिए प्रयोग रत हैं। फरवरी, 1998 में 77 संस्थानों ने वर्ल्ड वेब साईट पर अपने वेब साईट आरम्भ कर दिए थे। ये ऑन लाईन समाचारपत्र नि:शुल्क उपलब्ध है यद्यपि समाचारपत्र इस क्षेत्र में प्रवेश कर चुके है लेकिन आम आदमी के बीच ऑन लाईन समाचारपत्रों के विस्तृत उपयोग की अभिरूचि ने अभी जड़ें नहीं जमाई हैं।

6.5.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति

यद्यपि जापान ही एक ऐसा देश है जहां समाचारपत्रों के नियमन के लिए कोई अलग से कानून नहीं है। लेकिन वहाँ कानून में कई ऐसे प्रावधान हैं जो प्रेस से सम्बन्ध रखते हैं। 1945 में जापान की हार के बाद एलॉयड फोर्सेज ने जापान की असैन्यकरण की प्रक्रिया में युद्ध के पूर्व के प्रेस पर पाबन्दी सम्बन्धी कानून समाप्त कर दिए थे। जापान के संविधान आर्टिकल-21 में लिखा

है, "किसी प्रकार की सेन्सरशिप लागू नहीं रहेगी तथा न सम्प्रेषण (कम्यूनिकेशन) के साधनों की गोपनीयता का उल्लंघन किया जाएगा।" यद्यपि (क्रिमिनल कोड के आर्टिकल 175 के अनुसार अश्लील सामग्री पर पाबन्दी है। कॉपीराईट कानून के द्वारा लेखकीय अधिकारों का संरक्षण है तथा प्रकाशन एवं मुद्रण व्यवसाय को प्रोत्साहन दिया जाता है। इस प्रकार कुछ अलग-अलग ऐसे कानून हैं जो प्रेस से सम्बन्धित हैं। जापान की प्रेस पर जापान न्यूज़ पेपर्स पब्लिशर्स एण्ड एडीटर्स एसोसिएशन अर्थात् 'निहोनशिन बुल क्योकाई' (एन.एस.के.) ने जो नियम 1946 में प्रतिपादित किए थे, मूलतः उसी के अनुरूप प्रेस पर नियन्त्रण है। इस एक प्रकार की आचार संहिता को 1955 में संशोधित किया गया। यह नैतिक 'चार्टर' है, जिसका मन्तव्य है-'स्वतन्त्रता की भावना, दायित्व, निष्पक्षता एवं शालीनता'। इस प्रकार पत्रकारिता का एक स्तर तय किया गया जिसका पालन न केवल पत्रकारों के लिए आवश्यक माना गया बल्कि समाचारपत्रों के काम से सम्बन्ध रखने वाले हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। नियमों में यह भी कहा गया है कि-'समाचार रिपोर्टिंग का मौलिक नियम यह है कि तथ्यों को सही एवं विश्वसनीयता के साथ प्रस्तुत किया जाए तथा रिपोर्टर अपनी व्यक्तिगत राय को समाचारों में न जोड़े।'

6.5.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे

प्रेस स्वतन्त्रता की दृष्टि से जापान में प्रेस अनुशासित है। इसकी स्वतन्त्रता प्रेस के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण होने की बात इस तथ्य से प्रगट होती है कि 'योमियूरी शिम्बुन' अपने प्रचार संख्या के एक करोड़ के आकड़े को 1994 में ही पार कर गया है। दी 'आशाहि शिम्बुन' 83 लाख काँपी के प्रसार वाला जापान का ऐसा पत्र है जो विश्व में इस सन्दर्भ में दूसरे नम्बर का अखबार है।

जापान में प्रेस स्वतन्त्रता के नहीं लेकिन प्रेस के सामने कुछ मुद्दे जरूर हैं। एक समूह का गठन किया गया तथा जिसे इस बात का अध्ययन करने का दायित्व सौंपा गया था कि ब्राडकास्टिंग एवं युवाओं के बीच किस प्रकार का रिश्ता होना चाहिए। इसके अलावा इस बात को भी अहम माना गया कि 21वीं सदी में युवाओं से सम्बन्धित प्रसारण नीति की दिशा क्या हो? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की जिस अध्ययन दल को जिम्मेदारी दी गई थी, उसने 1998 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में सात सिफारिशें की गई जिनमें "मीडिया लिटरेसी" पर ध्यान देने की जरूरत बताई गई थी।

Media Newspapers in May, 1999

Newspaper title	**Circulation**	
	Morning edition	Evening edition
National Newspapers		
Yomiuri Shimbun	10,240,812	4,248,549
Asahi Shimbun	8,284,486	4,117,875
Mainichi Shimbun	3,962,917	1,768,369
Nihon keizai Shimbun	3,012,890	1,652,241
Sankei Shimbun	1,976,650	909,354

Block News Paper		
Chunichi Shimbun	2,673,210	754,209
Hokkaido Shimbun	1,229,167	743,380
Nishinippon Shimbun	840,470	189,230

Source: Japan audit bureo of circulations monthly report.

Newspaper organizations

The Japan Newspaper Publishers & Editors Association

Nihon Press Center Bldg. 2-2-1 Unchisaiwai-cho, Chiyoda-ku Tokyao, Japan 100

Yomiuri Shimbun (Tokya main office)

The Yomiuri Shimbun

1-7-1, Ote-machi, Chiyodia-ku, Tokyo 100-8055

Asahi Shimbu (Tokyo Main Office)

Asahi Shimun Publishing Co.

5-3-2, Tsukiji, Chu-ku, Tokyo 104-8011

Mainchi Shimbun (Tokyo Main office)

The mainchi Newspapers

1-1-1, Hitotsubashi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8051

Nihon Keizai Shibun (Tokyo Main office)

Nihon Keizai Shibun Inc

1-9-5, Ote-machi, Chiyoda-ku, Tokyo 100 8066

Sankei Shimbun (Tokyo Main Office)

Sankei Shimbun Co. Ltd

1-7-2, Ote-machi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8077

Electronic Media Organizations

The National Association of Commercial Broadcasters in Japan

3-23, Kioi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8577

Nihon Hoso Kyokai (NHK)

Japan Broadcasting Corp.

NKH Hoso Center, 2-2-1, Jin-nan, Shibuya-ku

Tokyo 15-8001

Japan cable Television Association

2nd Floor,SDI Gotanda Bldg.

7-13-6, Nishigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031

<u>Commercial Television Stations (Key Stations)</u>

Fuji Television Networks Inc. (CX)

2-4-8, Daiba, Minocha, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8004

Nippon Television Network Corp. (NTV)

14, Nibancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8004

Asahi National Broadcasting Co. Ltd (TV Asahi)

2-1-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-8001

Tokyo Broadcasting System Inc. (TBS)

5-3-6, Akasaka, Minato-ku

6.6 उत्तरी कोरिया में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी

6.6.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया चीन और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1,20,540 वर्ग कि.मी. है। यहां की आबादी दो करोड़ 14 लाख है। इनमें 64 प्रतिशत आबादी नगरीय है। बौद्ध एवं कन्फूसिस धर्म प्रमुख धर्म हैं। कुछ ईसाई, चीनी एवं अन्य लोग भी रहते हैं। साक्षरता का प्रतिशत 95 है। रूस और जापान की लड़ाई में कोरिया प्रमुख मुद्दा था। एशिया में कोरिया ही वह जगह है जहां साम्यवादी आन्दोलन सबसे पुराना है। रूस ने कोरिया के लोगों को गुरिल्ला देकर जापान के अधिकार की कोशिशें नाकाम की। कोरिया के दक्षिण में अमेरिकी सेना ने अधिकार किया। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया की स्थापना कम्यूनिस्ट राज्य के रूप में 1948 में हुई।

6.6.2 जनसंचार उद्भव एवं विकास

6.6.2.1 समाचारपत्र

उत्तरी कोरिया के जनसंचार माध्यम प्रणाली एक प्रकार की 'बन्द' प्रणाली लगती है, क्योंकि इसे तानाशाही शासन के हितों के लिए काम करना पड़ता था। मार्क्स एवं लेनिन की अवधारणा में प्रेस का काम प्रोपेगेन्डा करना है। अत: उत्तरी कोरिया में प्रेस का इतिहास एक तरह से वहां के साम्यवादी शासन का इतिहास है। लेकिन उत्तरी कोरिया के सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से वहां प्रेस प्रणाली जनतान्त्रिक है। उत्तरी कोरिया की प्रेस की विशेषताएं उस समय उभरी जबकि जापानी उपनिवेशवाद के खिलाफ राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम शुरू हुआ। 1945 में जापान का उपनिवेशवाद समाप्त हुआ।

लोकप्रिय पत्रकारिता, अभिव्यक्ति का लोकप्रिय तरीका एवं क्रान्तिकारी, लेखन, जैसी प्रवृत्तियां जापान के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध के समय उभरी थीं। इसके अन्तर्गत लोकप्रियता का अर्थ था कि पत्रकार जनता के लिए काम करेगा उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप अभिव्यक्ति दे तथा जनता के साथ समझ एवं समन्वय से चले। अभिव्यक्ति संक्षिप्त एवं जीवन्त है। सक्रिय एवं आक्रामक रिपोर्टिंग की जाए। प्रेस के प्रथम चरण में 1945 से 1950 की अवधि 'रोडोंग सिल्मन' जैसे पत्र छपे। केनोंग सिन्मन' लिब्रेशन वार के समय 1953 के समय प्रकाशित हुआ। यह वह

समय था जबकि माध्यमों को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम में पूरी शक्ति के साथ सेवाएं देनी पड़ती थीं। तीसरा चरण 'सोशियलिस्ट कन्स्ट्रक्शन पीरियड था जो 1944 तक चला। 'पोन्डायान्ग इल्बो एवं 'रांग्बांग इल्बो'-ये दो समाचारपत्र इस अवधि में प्रकाशित हुए। समाचार पत्रों को प्रोपेगेन्डा के संचालन में योग देना पड़ता था। समाचारपत्रों की आजादी की गारन्टी की सीमा यह है कि समाचारपत्र केवल पूरी शक्ति से सोसियलिज्म के निर्माण में भागीदारी निभा सकते हैं। सरकार द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसे में समाचारपत्रों की अभिव्यक्ति की कल्पना भी मुमकिन नहीं हो सकती।

6.6.2.2 रेडियो

उत्तरी कोरिया में कोरियन सेन्ट्रल ब्राडकास्टिंग स्टेशन 14 अक्टूबर, 1945 को आरम्भ हुआ। 1950-56 के बीच रेडियो सेवाएं बन्द रहीं। इसके बाद सोवियत सहयोग से रेडियो सेवाएं पुन: शुरू की गईं। 'लिब्रेशन ऑफ साऊथ' रेडियो स्टेशन ने 1967 में प्रसारण करना प्रारम्भ किया। ब्राडकास्ट नेटवर्क संघर्ष की नीति में पार्टी की नीतियों का वाहक या हथियार होता है। सोशियलिस्ट शासन में प्रसारण का दायित्व जनता को क्रान्ति के लिए तैयार करना तथा अमेरिका जैसी पूंजीवादी वर्ग वाले देश के खिलाफ लड़ना तथा समाजवाद की स्थापना करना माना गया। कम्यूनिस्ट शासन में सूचना के प्रवाह को रोका गया। दक्षिण कोरिया या अन्य प्रसारणों को सुनना, राजनैतिक अपराध माना गया।

6.6.2.3 टेलीविजन

उत्तरी कोरिया में टेलीविजन प्रसारण 1963 में शुरू हुआ। सोवियत रूस के सहयोग से 1969 में छोटा टी.वी. स्टेशन तैयार किया गया। 1971 में दक्षिण कोरिया को निशाना बनाते हुए केसोंग टी.वी. स्टेशन प्रोपेगेन्डा चैनल के रूप में ये काम करने लगा। रेडियो की तरह ही टी.वी. सरकार की नीतियों का पार्टी लाईन पर प्रोपेगेन्डा करने का एक माध्यम रहा। उत्तरी कोरिया के टी.वी. की खास बात यह है कि कार्यक्रमों का प्रसारण अनियमित है तथा कार्यक्रमों में विज्ञापन वर्जित है। संगीत, नृत्य, फिल्म एवं साहित्यिक कार्यक्रम ही अधिकांशत: प्रसारित होते हैं।

6.6.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी

माध्यमों का ऑन लाईन होना, इन्टरनेट आदि की नई संचार प्रौद्योगिकी की विकास की दिशा में बहुत कम ध्यान दिया गया। टोकियो में एक वेबसाईट सरकार ने प्रोपेगेन्डा के लिए स्थापित किया। कोरियन सेन्ट्रल न्यूज एजेन्सी टोकियो में इसका संचालन करती है। कम्प्यूटर एवं इन्टरनेट उपभोक्ताओं के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

6.6.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति

उत्तरी कोरिया में प्रेस की स्वतन्त्रता की सम्भावनाओं के अभाव में एशियन डेमोक्रेटिक कांफ्रेंस, 1998 में यहां व्यक्त किया गया कि उत्तरी कोरिया में अभिव्यक्ति की मौलिक आजादी का पूर्ण अभाव है।

6.6.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे

विश्व के स्वतन्त्र माहौल में उत्तरी कोरिया की सरकार की नीतियों ने देश को दुनिया से अलग कर दिया। यह नीति आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा है लेकिन इस जनसंचार माध्यम साम्यवादी, राजनैतिक एवं सामाजिक ढांचे के अंग हैं। ऐसे में, प्रेस की स्वतन्त्रता के निकट भविष्य में उभरने की सम्भावनाएं क्षीण है।

Media **Provincial Newspapers**

Newspaper	**Date of estaluishement**
Hwangbuk ilbo	September 6, 1945
Hwangnam ilbo	September 6, 1945
Hamnam ilbo	October 1, 1945
Pyongbuk ilbo	November 15, 1945
Kangwon ilbo	November 27, 1945
Changang ilbo	March 11, 1949
Kaesong Singmun	March 26, 1952
Ryanggang ilbo	January 1, 1955
Pyongyang ilbo	June, 1, 1957

6.7 दक्षिण कोरिया में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी

6.7.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

दक्षिण कोरिया, जापान एवं उत्तरी कोरिया के बीच स्थित है। देश का क्षेत्रफल 98,480 वर्ग कि.मी. है। उत्तरी-कोरिया से 2413 किलोमीटर तथा 2,413 कि.मी. सीमा समुद्र तट से लगी है। दक्षिण कोरिया की आबादी 4 करोड़ 69 लाख है। इसमें 20 हजार चीनी हैं। साक्षरता 98 प्रतिशत है तथा 84 प्रतिशत आबादी शहरों में रहती है। 47 बौद्ध, 49 प्रतिशत ईसाई, 3 प्रतिशत कन्फूशियस धर्म को मानते हैं। यह देश गणतन्त्र है।

6.7.2 जनसंचार: उद्भव एवं विकास

6.7.2.1 समाचारपत्र

कोरिया का पहला समाचार पत्र 'चौबी' (कोर्ट गजट) 1392 में निकला। चीन ने आधुनिक प्रेस का आरम्भ होने से पहले 1898-99 में कुछ समाचारपत्र प्रकाशित किए। जापान के अधिकार में आने के बाद 1910 में तीन अखबारों को छोड़कर बाकी बन्द कर दिए गए। आज के दो सबसे बड़े अखबार 'चोजुम इल्बो' एवं 'डोंग ए इल्बो' 1920 में आरम्भ हुए थे। कई ऐतिहासिक घटनाएं हुईं। 1945-48 में अमेरिका मिलिट्री शासन रहा। कोरिया युद्ध एवं 1961 में मिलिट्री द्वारा तख्तापलट, 1987 जनतांत्रिक सग्राम तथा 1992 में चुनी हुई सरकार का अन्त आदि के दौर से गुजरी दक्षिण कोरिया की प्रेस को योजनाबद्ध दबाव एवं नियन्त्रण की स्थितियां भोगनी पड़ी। 1945-48 में अमेरिकी अधिकार के समय माध्यमों में दक्षिण पंथी संस्कृति उभरी। सरकार का

नियन्त्रण रहा। अधिनायकवाद शासन में वामपंथी विचारधारा वाले समाचारपत्रों पर दबाव बढ़ा। "जनतन्त्र की रक्षा के लिए साम्यवाद का विरोध" नारा उभरा। 1948-60 की अवधि में तत्कालीन सरकार ने नागरिकों को मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया।

1960 में छात्र आन्दोलन हुआ। दक्षिण कोरिया के इतिहास में प्रेस को पहली बार आजादी मिली। जनतान्त्रिक तरीके से चुनी गई सरकार ने प्रेस को स्वतन्त्रता की गारन्टी दी। सरकार ने समाचारपत्रों को लाईसेन्स देने की प्रणाली के बजाय उनका पंजीकरण करने आरम्भ किया। इससे एकाएक कई समाचारपत्र प्रकाशित होने शुरू हो गए। एक साल में ही दैनिक समाचारपत्रों की संख्या 41 से बढ़कर 112 हो गई। अन्य प्रकार के पत्रों का भी तेजी से विकास हुआ। 1970 का समय फिर प्रेस के लिए सबसे बुरा साबित हुआ। यह देश में मार्शल-लॉ का समय था। इस प्रकार राजनैतिक परिवर्तनों से होकर गुजरती दक्षिण कोरियाई समसामयिक प्रेस एवं माध्यमों ने स्वतन्त्र वातावरण में सास लेना प्रारम्भ किया। प्रेस यूनियनों एवं माध्यमों के संगठनों ने अपने सम्पादकीय अधिकारों के लिए संघर्ष चलाए। दक्षिण कोरिया में 10 बड़े राष्ट्रीय दैनिक तथा 64 दैनिक पत्र है। इनमें 'चोजुम इल्बो' एवं 'डोंग ए इल्बो' प्रमुख हैं।

6.7.2.2 रेडियो

अमेरिका मिलिट्री सरकार (1945-48) ने दक्षिण कोरिया में रेडियो को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1954 में कोरियन नेशनल किश्चिप कौंसिल ने पहला निजी रेडियो स्टेशन शुरू किया। इसके बाद रेडियो का विकास हुआ और अधिक रेडियो संचालन में आये। देश में चार राष्ट्रिय रेडियो नेटवर्क भी काम करने लगे। कोरियन ब्राडकास्टिंग सिस्टम (के.बी.एम.) द्वारा रेडियो सेवाओं का संचालन किया जाता है। इसके अलावा बुद्धिस्ट ब्राडकास्टिंग स्टेशन आदि द्वारा विशिष्ट प्रकार के प्रसारण किए जाते हैं। टेलीविजन के आने के बाद रेडियो के श्रोताओं में कमी आने लगी। विज्ञापन के स्रोत भी कम होने लगे । रेडियो को टेलीविजन ने विशिष्ट प्रकार की ब्राडकास्टिंग सेवाएं एवं संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करने को विवश कर दिया। इस बुद्धिस्ट रेडियो ट्राफिक ब्राडकास्टिंग सिस्टम, एज्यूकेशनल ब्राडकास्टिंग सिस्टम जैसे पांच प्रसारण 1990 में शुरू हुए।

6.7.2.3 टेलिविजन

दक्षिण कोरिया में टेलिविजन 1956 में आया। लेकिन एक साल बाद बन्द हो गया, क्योंकि देश में केवल तीन हजार टी.वी. सेट थे तथा विज्ञापनों में टी.वी. की आय बहुत कम थी। 1957 से 61 तक अमेरिकन फोर्सेज कोरिया नेटवर्क (ए.एफ.के.एन.) ने अमेरिकी मूल्यों का प्रसार किया। 1961 में के.बी.एस. एक सरकारी टी.वी. प्रणाली के रूप में पूरी तरह संचालन में आया। सियोल ब्राडकास्टिंग सिस्टम (एस.बी.एस.-टी.वी.) का कुछ संस्थानों ने लाईसेन्स लेकर 1990 में आरम्भ किया। 1995 में चार निजी टी.वी. स्टेशन संचालन में आये।

6.7.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी

20वी सदी के अन्तिम दशक में कम्यूनिकेशन एवं इन्टरनेट का विकास एकाएक तेज हुआ। देश में 1998 में 3,88,256 कम्प्यूटर थे। 37,364, कम्प्यूटर उपभोक्ता थे। चोजुम इल्बो। डोंग ए इल्बो, हकुक इल्बो, टाइम्स आदि एक दर्जन समाचारपत्र ऑन लाईन पर हैं। एक

ब्राडकास्टिंग कम्पनी-इन्टरनेट टी.वी. ने अपनी सेवा देना 1977 में शुरू की। साईबर जनरल परम्परागत प्रेस पर व्यंग करता है और काफी लोकप्रिय है।

6.7.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति

मुक्त वैश्वीकरण के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा के कारण दक्षिण कोरिया की प्रेस में तेज गति से अनेक परिवर्तन हुए है। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कोरिया की सरकार ने प्रेस के लिए स्वंय सुधार की नीति को प्रोत्साहन दिया है। 1998 में सरकार ने देश के सांस्कृतिक ढांचे को ग्रहण करने के लिए पांच सूत्री योजना बनाई। सरकार की धारणा है कि सरकार एवं प्रेस के एकाधिकार को रोका जा सकें। एक तरफ सरकार के प्रेस पर नियन्त्रण का लम्बा इतिहास है और दूसरी ओर व्यावसायिकता के प्रति गहरा रुझान है।

6.7.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे

दक्षिण कोरिया में कोरियन फेडरेशन ऑफ प्रेस यूनियन्स एवं अन्य संस्थाओं के प्रयत्न यह हैं कि प्रेस एवं माध्यमों में ढांचागत सुधार हो, माध्यमों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो तथा एकाधिकार की प्रवृत्तियों पर रोक लगे। सम्पादकीय स्वतन्त्रता के लिए प्रेस को प्रबन्धन से मुक्त किया जाए। इसके अलावा कानूनी एवं आचार संहिता के सम्बन्ध में भी सुधार के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। प्रसारण की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की भी समस्या है ताकि इसे राजनैतिक प्रभाव से मुक्त किया जा सके।

बोधप्रश्न 2

1. मकाओ (चीन) के जनसंचार माध्यमों पर प्रकाश डालिए।
2. 'जापान आज भी जनसंचार माध्यमों में तेज गति से विकास की ओर अग्रसर है'। समीक्षा करें।
3. उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया में प्रेस की स्वतन्त्रता की क्या स्थिति है?

Media	South Korea
	Daily National Newspapers
	Dong-A ilbo
	139, Choong-chung-ro-3-ka
	Seo-dae-man-ku, Seoul, Korea
	Chosun ilbo
	61, Tae-pyung-ro-1-ka
	Choong-ku, Seoul, Korea
	Joong-ang ilbo
	7, Soonhwa-tong Choong-ku
	Seoul, Korea
	Hankyoreh

116-25, Gong-deuk-tong
Mapo-ku, Seoul, Korea

Hankook ilbo
14,Joong-hak-tong, Chong-ro-ku
Seoul, Korea

News Agencies

Yonhap News
85-1, Soonsong-tong, Chong-to-ku
Seoul, Korea

Broadcasting Networks

KBS (Korea Broadcasting System)
KBS-TV 1&2, Satellite 1&2,AM 1&2, FM 1&2
18 Yodio-tong
Youngdungpo-ku

MBC (Munhwa Broadcasting Corporation)
MBC-T\AM, FM
31, Yoido-tong
Youngdungpo-ku
Seoul, Korea

SBS (Seoul Broadcasting Corporation)
SBS-TV, AM, FM
10-2 Yoido-tong
Youngdungpo-ku
Seoul, Korea

EBS (Educational Broadcasting System)
TV, FM
92-6 Woomyun-tong
Secocho-ku, Seoul, Korea

6.8 मंगोलिया में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी

6.8.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

रूल्स एवं उत्तरी चीन के बीच मंगोलिया मध्य एशिया में स्थित है। भू-भाग में रेगिस्तान, पर्वत, वन एवं घास के मैदानी क्षेत्र है। गर्मी का समय कम है और सर्दियां लम्बी हैं। सर्दियों में पारा 50 डिग्री सैल्सियस नीचे चला जाता है। आबादी केवल 26 लाख है। मंगोलियनों की अधिकांश आबादी अर्थात् लगभग 4 लाख लोग चीन के इनर मंगोलिया प्रान्त में रहते हैं। 90

प्रतिशत आबादी मंगोलियन है। खाल्खा मंगोल इनकी भाषा है। अधिकांश लोग तान्त्रिक हैं या तिब्बत के बौद्ध सम्प्रदाय को मानते हैं। एक सार्वभौमिक राज्य के रूप में मंगोलिया का लम्बा इतिहास है। कभी इनका साम्राज्य चीन के पूर्वी तट से सेन्ट्रल यूरोप तक फैला हुआ था। यह शासन 15 सदी तक चला। इसके बाद चीन या रूस का दबदबा बढ़ गया। मंगोलिया की परम्परागत राजशाही पर चीन का कब्जा हो गया। 1821 में मार्क्स क्रान्ति हुई। रूस के नियन्त्रण में शक्तिशाली बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया गया। 30 हजार मोंक (बौद्ध भिक्षु) मारे गये। देश में आतंक छा गया और आबादी उस समय मात्र 6 लाख रह गई।

6.8.2 जनसंचार: उद्भव एवं विकास

6.8.2.1 समाचारपत्र

सोवियत रूस के देश में आने से पहले मंगोलिया एक पिछड़ा हुआ एवं एकान्त राष्ट्र था। 1911 में एक साप्ताहिक 'शाईन रोल' (न्यू मिरर) शुरू हुआ लेकिन यह जल्दी ही बन्द हो गया । पहली बार सोवियत रूस के सहयोग से स्थापित सरकार ने साम्राज्यवादी प्रोपेगेन्डा मॉडल पर जनसंचार की रूपरेखा तैयार की। साक्षरता कम होने के कारण समाचारपत्रों की पहुंच राजधानी तक सीमित रही। 'यूनेन' (सत्य/यथार्थ) साम्यवादी शासन में पहला पत्र शुरू हुआ उसके बाद भी कुछ पत्र प्रकाशित हुए। समाचारपत्रों का विकास सोवियत प्रेस प्रणाली पर आधारित था। देश में 23 राष्ट्रीय पत्र तथा 19 क्षेत्रीय पत्र थे। 1990 में इनकी संख्या 45 थी। चेप्टर 2 के तथा 1992 में संविधान द्वारा मानव अधिकारों एवं प्रेस स्वतन्त्रता की गारन्टी का प्रावधान किया। सूचना पाने के अधिकार की भी व्यवस्था की गई, परिणामस्वरूप 1995 एवं 1998 के बीच 800 समाचारपत्रों का पंजीयन हुआ।

1990 में साम्यवादी शासन के समाप्त होने के बाद जनसंचार माध्यमों की स्वतन्त्रता की मांग बलवती हुई। नई सरकार ने पाबन्दियां खत्म की। कई कारणों से साम्यवादी शासन के बाद के काल में माध्यमों में बिखराव रहा। 28 अगस्त, 1998 में मंगोलिया की संसद ने जनसंचार माध्यमों की स्वतन्त्रता के लिए कानूनी आधार की संरचना करते हुए कानून पारित किया। इसमें जनतन्त्रीय को सुदृढ़ करने के लिए माध्यमों को प्रोत्साहन देने की प्रावधान भी रखा। यसर्ड डे, टुडे एवं डे आफ्टर टूमारो में सीधे खबरें होती हैं एवं अन्य समाचारपत्र छपते हैं। अब मंगोलिया के समाचारपत्र जितने स्वतन्त्र हो सकते हैं, उतने स्वतन्त्र हैं।

6.8.2.2 रेडियो

मंगोलिया में रेडियो की स्थापना 1934 में हुई। यह साम्यवादी दल की नीतियों पर आधारित था तथा साम्यवादी काल की समाप्ति तक इसी नीति पर चलता रहा। मंगोल रेडियो के 1975 में 20 रेडियो स्टेशन थे। साथ ही एक राष्ट्रीय रेडियो स्टेशन था। एक लाख, 48 हजार रेडियो रिसीवर थे। प्रेस की तरह रेडियो का मन्तव्य भी प्रोपेगेन्डा करना था। समाजवादी मूल्यों की शिक्षा पर कार्यक्रमों में बल दिया जाता था। सामाजिक दायित्व प्रमुख मुद्दा था।

6.8.2.3 टेलीविजन

टेलीविजन का मंगोलिया में 1967 में प्रसारण होने लगा। सरकार द्वारा संचालित टी.वी. चैनल को सैटेलाईट द्वारा सोवियत यूनियन दो कार्यक्रम प्रसारित करती थी। कार्यक्रमों में साम्यवादी राष्ट्रों द्वारा दी जाने वाली सामग्री के अलावा किसी अन्य देश की सामग्री नहीं होती थी। इस प्रकार साम्यवादी विचारधारा से टी.वी प्रभावित रहा। लेकिन शासन बदलने के बाद टी.वी. का स्वरूप एवं कार्यक्रम बदले। 1997 में मंगोलिया में 1,50,400 टी.वी. थे, जबकि इससे पूर्व 1990 में यह संख्या 1,37,400 थी।

6.8.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी

मंगोलिया उन विकासशील देशों में से एक है जो नई संचार प्रौद्योगिकी के युग में छलांग लगाने की तैयारी में हैं। इन्टरनेट क्रांति के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के बावजूद ऑन-लाईन प्रौद्योगिकी के विकास की गति धीमी है। 1998 मे इन्टरनेट उपभोक्ताओं की संख्या मात्र 3200 थी। 1994 में स्थापित डेटाकोम ही केवल इन्टरनेट सेवाएं देता है। 'उन-ऊदौर', आर्डिन एर्स, ओडीरन टोली जैसे 6-7 समाचारपत्र ऑन लाईन पर उपलब्ध हैं।

6.8.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति

मंगोलिया में सरकार जनसंचार माध्यमों के निजीकरण की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है। सरकार के स्वामित्व एवं नियन्त्रण वाले माध्यमों का स्थानान्तरण करने की प्रक्रिया में है। 1998 के प्रेस कानूनों के अनुसार दो सरकारी समाचारपत्रों की सहायता बन्द कर दी गई एवं उन्हें निजी हाथों में सौंप दिया गया। सरकार आर्थिक उदारीकरण की नीति से प्रभावित है। मंगोलिया की प्रेस को 'स्वतन्त्र प्रेस' माना गया है।

6.8.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे

1998 के मीडिया कानूनों के लागू होने से प्रेस की स्वतन्त्रता को गति अवश्य मिली है लेकिन 'प्रोपेगन्डा मिल' के मुक्त विचारों एवं अभिव्यक्ति के वाहक के रूप में पूरी तरह बदलने का क्रम जारी है। सरकारी नीति तो प्रेस स्वतन्त्रता की पोषक है लेकिन जनसंचार माध्यम इकाइयों पर अभी राज्य के विभिन्न विभागों का नियन्त्रण है। यद्यपि अब प्रोपेगेन्डा करने की जरूरत नहीं है लेकिन सरकार के अप्रत्यक्ष नियन्त्रण के कारण संचार माध्यमों को सरकार की नीतियों एवं कार्यों की आलोचना करते संयम बरतना पड़ता है। विज्ञापन की अवधारणा भी जनसंचार माध्यमों के लिए नई बात है। एडवरटाइजिंग स्पेस के विक्रय को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है ताकि समाचारपत्र मात्र समाचारपत्रों के विक्रय पर निर्भर न रहे। अभी तक कई समाचार पत्रों के विज्ञापनों के लिए कोई स्टाफ तक नहीं है। मुक्त एवं लोकप्रिय प्रेस बनने की तेज प्रक्रिया ने प्रेस के सामने स्तरीय आचार संहिता के विकास की समस्या भी है। पत्रकारों के व्यावसायिक स्तर को ऊंचा करने की भी आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। साम्यवादी काल में पत्रकारों के आलोचनात्मक होने की प्रवृत्ति को हतोत्साह किया जाता था । अत: पश्चिमी शैली पर पत्रकारों को प्रशिक्षित करने की नीति बनाई गई है।

Media	Newspaper (1998) Mangolia

State-owned until end of 1998	
Ardyn Erkh (People Right/National	
Right/Daily Mirror/Daily News) Former	25,000*
Publisher Garrin Medee (Government	
News/Century News). Former Publisher,	13,550*
Government og Mangolia	
Njamgarig (Sunday)	9.000
Private	
Onoodor (Today)	
Publisher Mongol News Co.	6,000*(daily)
Mongolian Medee	
Publisher: Erel Co. Ltd.	3,000*(daily)
Seuuleg (Alarm)	45,000-51,000
Il tovechoo (OpenHistory)	N.A
Deesin Hureleen (High Society)	21,000
Shar Sonin (Yellow Paper)	13,000-15,000
Bi, Bi, Bi, (Me, Me, Me)	12,000
Hoh Toblo (Blue Sport)	8,000-12,000
Mongolian neg under (Mongolian Day)	10,000
Khumuus (People)	10,000
Jigshuurt Hereg (Crime)	12,000
Other	
Unaanbaater Times	
(UB Muncipalty owned)	3,500*(daily)
Unen (Reality) (MPRP: party-owned)	5,000-6,000

Source: *WAN, 1999, PIM, 1998

Radio Brodcasting (1998)

Station	**market share**
Mongol State Radio	39 percent
FM 102.5	35 percent
Durvun Uul	18 percent
FM 107	8 percent

Source: PIM, 1998

6.9 ताईवान में जनसंचार और नई सूचना-प्रौद्योगिकी

6.9.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

ताईवान का पुराना नाम फार्मोसा था। चीन के दक्षिण पूर्वी तट से 160 किलोमीटर दूर यह एक द्वीप है। 1949 में यह चीन के 35 प्रान्तों में से एक था। लेकिन जब राष्ट्रीय सरकार को गृहयुद्ध के समय साम्यवादियों के हाथों हार हुई उस समय ताईवान एवं अन्य द्वीप वे अलग हो गए। ताईवान 36,140 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। 7वीं सदी से 17वीं सदी तक चीनी लोग जाकर ताईवान में बस गए। लेकिन जब राष्ट्रीय सरकार की हार होने के बाद 1950 में साम्यवादी शासन हुआ, काफी संख्या में चीनी लोग ताईवान पलायन कर गए। लगभग 20 लाख शरणार्थी चीन से ताईवान पहुंचे। 1999 में ताईवान की जनसंख्या 21 लाख थी। इनमें ताईवान के मूल निवासी एवं चीन विस्थापित शामिल है।

1987 तक ताईवान मे एक दल की सरकार थी। मार्शल-लॉ के अन्तर्गत कुमिनतांग (के.एम.टी.) कानून वहां की एक मात्र राजनैतिक पार्टी थी। 1996 में राष्ट्रपति का सीधा चुनाव हुआ। नए राजनैतिक दल उभरे। 1997 में ताईवान पूर्ण रूप से जनतान्त्रिक देश बन गया।

6.9.2 जनसंचार: उद्भव एवं विकास

6.2.2.1 समाचारपत्र

1895 से 1945 तक ताईवान पर जापान का आधिपत्य रहा। इस अवधि में जापानी सरकार ने समाचारपत्रों के प्रकाशन पर पूर्ण नियन्त्रण किया। 1944 में जापानी गवर्नर ने ताईवान के तत्कालीन छह समाचारपत्रों को मिलाकर 'ताईवान सिन न्यूज' में मिला दिया। जब ताईवान को जापानियों ने 1945 में चीन को सौंपा तो इसका नाम बदलकर 'ताईवान सिन शेन न्यूज' (न्यू लाईफ डेली न्यूज) रख दिया गया। राष्ट्रीय सरकार ने सेन्सरशिप समाप्त कर दी। समाचारपत्रों की संख्या बढ़कर 28 हो गई। साम्यवादियों की चीन पर 1949 में विजय के बाद राष्ट्रीय सरकार ताईवान पलायन कर गई। न्यूज पेपर लाईसेन्सिंग बन्द कर दी गई। उसके बाद 37 वर्ष तक समाचारपत्रों की संख्या 31 समाचारपत्रों पर स्थिर रही। सरकार ने समाचारपत्रों पर पूर्ण रोक लगाई तथा प्रेस स्वतन्त्रता पर अंकुश लगा दिए। के.एस.टी. एवं सेना का 31 में से 14 पत्रों पर स्वामित्व था। प्रमुख समाचारपत्रों यूनाईटेड डेली न्यूज एवं चाईना टाइम्स पर के.एम.टी. का प्रत्यक्ष नियन्त्रण था। 1987 से पूर्व 'इन्डीपेन्डेट इवनिंग पोस्ट' एकमात्र विपक्ष का समाचारपत्र था। 1988 में समाचार के लिए लाईसेन्स पर लगी पाबन्दी समाप्त कर दी गई। इसका परिणाम यह हुआ कि जहां 1987 में 31 समाचारपत्र थे, 1998 में इनकी संख्या बढ़कर 360 हो गई। इनमें 40 पत्रों के विस्तृत पाठक हैं। समाचारपत्रों पर पाबन्दी के हटते ही दो सबसे बड़े अखबारों यूनाइटेड डेली न्यूज एवं चाईना टाइम्स की पृष्ठ संख्या 12 से दुगुनी हो गई। 1990 के दशक में ताईवान के समाचारपत्रों का मुद्रण रंगीन होने लगा। सामग्री में विविधता आई। रिपोर्टिंग में संतुलन आया। जनमत पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। 'लैटर टु एडीटर' के लिए पूरा एक पृष्ठ छपने लगा। कवरेज का दायरा बढ़ा। राजनीति, खेलों, कला, संस्कृति, समाज, बिजनेस रिपोर्ट आदि के प्रकाशन पर बल दिया जाने लगा। पुस्तक समीक्षा, विज्ञान आदि विषयों के लिए खास दिनों विशेषक छपने लगे।

6.9.2.2 रेडियो

जापानी उपनिवेश के समय ताईवान में 1925 में जापान ने रेडियो स्टेशन स्थापित किया। 1931 में पूरे द्वीप में नेटवर्क तैयार किया। रेडियो सरकार के नियन्त्रण में था। जब जापान ने चीन को यह क्षेत्र सौंपा, ताईवान में 5 रेडियो स्टेशन तथा 1 ,77,000 रेडियो सेट थे। 1950 में ताईवान का आर्थिक विकास प्रारम्भ हुआ। 1956 में 2,49,000 रेडियो सेट हो गये। 1959 में रेडियो लाईसेन्स देने पर सरकार ने रोक लगा दी। इससे रेडियो स्टेशनों की संख्या 33 पर सीमित हो गई लेकिन सुनने वालो की संख्या बढ़ती रही और 1974 में हर एक सौ लोगों में 26 रेडियो श्रोता थे। रेडियो लाईसेन्स देने पर जो रोक थी, वह 1993 में हटा दी गई। 1998 में इससे रेडियो स्टेशनों की संख्या 80 हो गई। 199 के दशक में ये पूरे देश में रेडियो की पहुंच हो गई। 1998 में देश के 99 प्रतिशत घरों में कम से कम एक रेडियो रिसीवर हो गया।

6.9.2.3 टेलीविजन

ताईवान में 1962 में टी.वी. प्रसारण शुरू हुआ। चाईना टेलीविजन (सी.टी.वी.) चाईना टेलीविजन सिस्टम आदि के प्रसारण आरम्भ किया। 1990 के दशक में फार्मोसा टेलीविजन (एफ.टी.वी.) एवं पब्लिक टेलीविजन आदि प्रसारण में आए। 1997 में 71 लाख टी.वी. सेट थे। 1998 में तो स्थिति यह हो गई कि लगभग एक प्रतिशत घरों में ही टी.वी. नहीं थे।

6.3.3 नई सूचना प्रौद्योगिकी

परम्परागत जनसंचार माध्यमों पर चले आ रहे सख्त नियन्त्रण के बावजूद बेहतर आर्थिक स्थितियां एवं नई सूचना प्रौद्योगिकी की मांग के सन्दर्भ में नये जनसंचार माध्यमों के लिए ताईवान एक उपजाऊ जमीन सिद्ध हुआ। 1990 के पूर्व कम्प्यूटर नेटवर्क की स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन 1990 के दशक में इतनी तेजी से नई सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हुआ कि कई विकसित देशों की संचार प्रौद्योगिकी में इसकी तुलना होने लगी। 1997 में ताईवान में लगभग दो करोड़ 57 लाख कम्प्यूटर थे । उस समय 34,897 इन्टरनेट हॉस्ट कम्प्यूटर थे। यह संख्या 1999 में बढ़कर 4,24,209 हो गई। ताईवान में एक दर्जन ऐसे संस्थान है जो इन्टरनेट सेवाएं करते हैं।

इसी प्रकार वेबसाईट के क्षेत्र में भी तेजी से वृद्धि हुई। 1996 में जहां 333 वेबसाईट थीं वहां 1977 में यह संख्या बढ़कर 1,951 हो गई। ताईवान ने इस प्रकार बहुत ही तेज गति से सूचना प्रौद्योगिकी युग में प्रवेश किया।

6.9.4 जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में नीति

ताईवान में जब जनतांत्रिकरण का विकास गति पकड़ने लगा सरकार ने जनसंचार माध्यमों पर अपना नियन्त्रण ढीला कर दिया एवं उनके पूर्ण विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करने के प्रयास भी तेज कर दिए। 1990 के दशक मे सरकार ने यह अनुभव किया कि तत्कालीन कानून जनसंचार के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। 1998 में सरकार ने अपनी कम्यूनिकेशन व्यवस्था या जनसंचार माध्यमों की सम्पूर्ण प्रणाली को बेहतर बनाने की एक योजना क्रियान्वित की। इसके अन्तर्गत एक स्वतन्त्र कम्यूनिकेशन कमीशन बनाया जिसे मंत्री स्तर का दर्जा दिया

गया। साथ ही जनसंचार माध्यमों के परिदृश्य को बरतने की विस्तार प्रक्रिया जारी की जिसके परिणामस्वरूप ताईवान ने तीव्र प्रगति का संकेत दिया।

6.9.5 प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे

जनसंचार माध्यमों के बीच की प्रतिस्पर्द्धा के कारण व्यावसायिक आचार संहिता का स्तर गिरने लगा। यदि किसी का अपहरण हो गया तो पत्रकार ऐसे मसलों का नाटकीय रूप में प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति के शिकार हो जाते हैं। नीतियों के निर्माण की दिशा में जनहित गौण होने लगे हैं। राजनीतिज्ञ भी माध्यमों के संचालन में आ गए, जिससे वे सरकार को प्रभावित करने लगे है। ऐसे में माध्यमों की स्वतन्त्रता को अनुशासित करने की समस्या पैदा हुई है।

बोध प्रश्न-3

1. मंगोलिया में इलेक्ट्रोनिक मीडिया की स्वतन्त्रता पर अपने विचार लिख।
2. ताईवान में जनसंचार माध्यमों के प्रति वहां की सरकार का क्या रुख है।
3. ताईवान में प्रेस स्वतन्त्रता के प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

Media

United Daily News

No.555, Sec. 4, Chung-Shio E. Road Taipei

China Times

132 Dali St. Taipei

The Liberty Times

137, Sec.2, Nanjing E. Road, Taipei

Taiwan Televsion Enterprise

10, Sec. 3, Bade Road, Taipei

China Television Co.

120, Chugyang Road, Nangang Area, Taipei

Chinese Televiosion Service

100, Gaunfu S. Road, Taipei

Formosa Televison

14F, No. 30 Sec. 3, Bade Road, Taipei

Public Television Service

100, Lane 75, Sec. 3

Kangning Road, Neihu Area, Taipei

Television Business Statellite

23, Sec. I, Bade Road, Taipei

Summon Television Network Company

7 F, No. 53, Dungshing Road

Shinyi Area, Taipei

Eastern Broadcasting Company

13F, No. 4, Sec. 1, Jungshian W. Road, Taipei

Videoland Enterprise Co. Ltd.

3F, No. 57, Dungshing Road, Taipei

WliigingNew Spread Enterprise Company

3f, No. 51

Dungshing Road, Taipei

Broadcasting Corporation of China

53 F, No. 102, Sec. 2, Luosfu Road, Taipei

UFO Radio

25 F No. 102, Sec. 2, Luosfu Road, Taipai

6.10 सारांश

प्रस्तुत इकाई में आपने पूर्वी एशिया के जनसंचार माध्यमों की जानकारी प्राप्त की। चीन में सरकार की सोच है कि जनसंचार माध्यमों को सामाजिक स्थाईत्व कायम रखने में मदद करनी चाहिए। अत: जनसंचार माध्यमों पर अकुंश को राजनीतिक दृष्टि से आवश्यक माना जाता है तथा आर्थिक संदर्भों में इन्हे नरमी के साथ देखा जाता है।

हांगकांग में 'ब्रिटिश कॉमन ला' के अन्तर्गत समाचार पत्रों का संचालन होता है। यहां के जनसंचार माध्यमों ने अपनी स्वतन्त्र परम्पराएं जारी रखी हैं। मकाओ के जनसंचार माध्यम साम्राज्यवादी नीतियों से ग्रस्त हैं। यह छोटा-सा स्थान, है अत: हागंकागं के जनसंचार माध्यमों का वर्चस्व है।

प्रेस की स्वतन्त्रता की दृष्टि से जापान के प्रेस अनुशासित हैं। यहां मीडिया लिटरेसी' को प्रधानता दी गई है। अधिकाशं बड़े समाचारपत्रों ने अपनी वेबसाइट शुरू कर दी है, जो पाठकों के लिए नि:शुल्क है। उत्तरी कोरिया की जनसंचार माध्यम प्रणाली एक प्रकार की 'बंद प्रणाली' है जिसे तानाशाही शासन के हितों के लिए काम करना पड़ता है। उत्तरी कोरिया में प्रेस का इतिहास एक तरह से वहां के साम्यवादी शासन का इतिहास है। मुक्त वैश्वीकरण के बीच बढती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण दक्षिण कोरिया में प्रेस में तेजी से परिवर्तन हुए हैं। सरकार ने प्रेस के लिए स्वयं सुधार की नीति को प्रोत्साहित किया है। मंगोलिया में प्रेस की स्वतन्त्रता को स्वतन्त्र माना गया है। ताईवान में प्रेस धीरे-धीरे विकास की ओर अग्रसर है।

6.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. डब्ल्यू एच चांग (1989): मास मीडिया इन चाईना: आवोवा यूनिवर्सिटी प्रेस
2. जी. डिग (1990): हिस्ट्री चाईनीज जर्नेलिज्म: वाहान यूनिवर्सिटी प्रेस
3. जे.ए. लेन्ट (1982): फ़्रीडम ऑफ दी प्रेस इन ईस्ट एशिया: हिनेमेन एशिया हांगकांग
4. यूनेस्को स्टेटिस्टिकल ईयर बुक (1999): यूनेस्को, पैरिस

5. एच के वाग (1996) मकाऊ ऑनर न्यू: मकाऊ फाउन्डेशन
6. टी. वातानाबों (1997): जापानन्स मीडिया एवं एजेन्ट: सोशियल साइन्स रिव्यू
7. जे.सी. चुंग (1994): मास कल्चर, मीडिया एण्ड दी पोपुलर कल्वरल मूवमेन्ट इन नाईन कोरियन सोसाइटी, सियोल

6.12 निबन्धात्मक प्रश्न

1. 'चीन में जनसंचार माध्यम' पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए?
2. चीन के जनसंचार माध्यमों के सन्दर्भ मे क्या नीति है? साथ ही चीन की नई संचार प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में अपने विचार स्पष्ट कीजिए।
3. 'हांगकांग में रेडियो एवं टेलीविजन की स्थिति बहुत ही संतोषजनक है'। इस संदर्भ में वहां की सरकार की नीति की चर्चा कीजिए।
4. मकाओ (चीन) के जनसंचार माध्यम पर एक लेख लिखिए।
5. 'जापान में जनसंचार माध्यमों ने विशेष प्रगति की है'। इस सन्दर्भ में जापान की नई संचार प्रौद्योगिकी का उल्लेख कीजिए।
6. उत्तरी एवं दक्षिण कोरिया के समाचारपत्रों, रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण की चर्चा कीजिए।
7. संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए (कोई दो) -
    1. ताईवान में नई सूचना प्रौद्योगिकी
    2. मंगोलिया में जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में सरकार की नीति
    3. उत्तरी कोरिया में इलेक्ट्रानिक माध्यमों की स्थिति
    4. थाईलैण्ड में जनसंचार
8. पूर्वी एशिया के जनसंचार माध्यमों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए।
9. मंगोलिया मे समाचारपत्रों की समस्याओं पर एक आलेख तैयार कीजिए।
10. ताईवान में जनसंचार की नई प्रौद्योगिकी के विकास के एकाएकत गति आ जाने के क्या कारण है? वहां के जनसंचार माध्यमों के सामने क्या चुनौतियां है?

छात्र टिप्पणी

छात्र टिप्पणी

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की सूची

	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि
1.	स्नातक उपाधि प्रारम्भिक पाठ्यक्रम	6 माह
2.	भोजन एवं पोषण में सर्टिफिकेट	6 माह
3.	कम्प्यूटर ज्ञान एवं प्रशिक्षण का प्रारम्भिक पाठ्यक्रम	6 माह
4.	सर्टिफिकेट इन कम्प्यूटिंग	6 माह
5.	पंचायती राज प्रोजेक्ट में प्रमाण-पत्र	6 माह
6.	संस्कृति एवं पर्यटन में प्रमाण-पत्र	6 माह
7.	महिलाओं में वैद्यानिक बोध में प्रमाण-पत्र	6 माह
8.	राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में प्रमाण-पत्र	6 माह
9.	बी.ए.एफ./बी.सी.एफ. (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम)	1 वर्ष
10.	एम.ए.(अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, हिन्दी)	2 वर्ष
11.	एम.बी.ए.	3 वर्ष
12.	पी.जी.डी.एच.आर.एम.	1 वर्ष
13.	पी.जी.डी.एफ.एम.	1 वर्ष
14.	पी.जी.डी.एम.एम.	1 वर्ष
15.	पी.जी.डी.एल.एल.	1 वर्ष
16.	टी.एच.एम.	1 वर्ष
17.	डी.एन.एच.ई.	1 वर्ष
18.	डी.सी.ओ.	1 वर्ष
19.	डी.एल.एस.	1 वर्ष
20.	डी.सी.सी.टी.	18 माह
21.	बी.जे.(एम.सी.)	1 वर्ष
22.	एम.जे.(एम.सी.)	2 वर्ष
23.	बी.लिब.	1 वर्ष
24.	पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1 वर्ष
25.	बी.एड.	2 वर्ष
26.	पी.एच.डी.	3 वर्ष
27.	पी.जी.डी.ई.एस.डी.	1 वर्ष